वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट का सार

2016

जन और संपूर्ण पृथ्वी के लिए शिक्षा:

सभी के लिए सुनिश्चित भविष्य का सृजन

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Sustainable Development Goals

Global Education Monitoring Report

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट का सार

2016

जन और संपूर्ण पृथ्वी के लिए शिक्षा:

सभी के लिए सुनिश्चित भविष्य का सृजन

यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से यूनेस्को द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र प्रकाशन है। यह रिपोर्ट संगठित प्रयासों का नतीजा है जिसमें रिपोर्ट टीम के सदस्य तथा अन्य कई लोग, एजेंसियां, संस्थान और सरकारें शामिल हैं।

इस प्रकाशन में दिए गए पदनाम और प्रस्तुत सामग्री का अर्थ किसी देश, प्रादेशिक सीमा, नगर या क्षेत्र या इसके प्राधिकारियों या इसकी सीमाओं का सीमांकन करने के संबंध में यूनेस्को की ओर से कोई राय, जो कोई भी हो, अभिव्यक्ति करना नहीं है।

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट दल इस रिपोर्ट में शामिल तथ्यों के चयन और प्रस्तुति तथा इसमें व्यक्त राय के लिए जिम्मेदार है। यह जरूरी नहीं कि इसमें व्यक्त विचार यूनेस्को के हों, और संगठन इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है।

रिपोर्ट में व्यक्त विचारों और राय की पूरी जिम्मेदारी इसके निदेशक की है।

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट दल

निदेशक: आरोन बेनावोट

मानोस एनटोनिनिस, माडेलेइन बैरी, निकोल बेला, निहान कोसेलेकी बलांची, मार्कोस डेलप्राटो, ग्लेन हेरटेलेंडी, कैथरीन जेरे, प्रियदर्शिनी जोशी, कर्टाजयना कुबाका, लेइला लोउपिस, कासियानी लाइथरैंगोमिटिस, अलासडॉयर मैकविलियम, अनिस्सा मेकटर, ब्रानवेन मिलर, क्लाउडीन मुकीज्वा, यूकी मुराकामी, ताया ओवेन्स, जुडीथ रंद्रियानातोआविना, केट रेडमैन, मारिया रोजनोव, अन्ना ईवा रूसजकिबिज, विल स्मिथ, ईमिली सुबडेन, रोसा विडार्टे तथा असमा जुबैरी।

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट एक स्वतंत्र वार्षिक प्रकाशन है। जीईएम रिपोर्ट सरकारों के समूह, बहुपक्षीय एजेंसियों और निजी फाउंडेशनों द्वारा वित्त-पोषित है जो यूनेस्को द्वारा समर्थित है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:
ग्लोबल शिक्षा निगरानी रिपोर्ट टीम
द्वारा यूनेस्को, 7, प्लेसडे फोनटेनोए
75352 पैरिस 07 एसपी, फ्रांस
ई-मेल: gemreport@unesco.org
दूरभाष:+33 145 680741
www.unesco.org/gemreport
https://gemreportunesco.wordpress.com

मुद्रण में बाद में पाई गई किसी भूल-चूक को ऑनलाइन पाठ www. unesco.org/gemreportt में सुधार दिया जाएगा।

© यूनेस्को, 2016
सर्वाधिकार सुरक्षित
प्रथम संस्करण
संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा 2016 में प्रकाशित,
7 प्लेस डे फोनटेनोए,
75352 पैरिस 07 एसपी, फ्रांस

यूनेस्को द्वारा टाइपसेट
एफएचआई 360 द्वारा ग्राफिक डिजाइन
एफएचआई 360 द्वारा लेआउट
कवर फोटो: फादिल अजीज/एएलसीआईबीबीयूएम फोटोग्राफी

नई वैश्विक निगरानी रिपोर्ट श्रृंखला

2016 लोगों और संपूर्ण पृथ्वी के लिए शिक्षा: सभी के लिए सुनिश्चित भविष्य का सृजन

ईएफए वैश्विक निगरानी रिपोर्ट श्रृंखला

2015 सभी के लिए 2000-2015 तक शिक्षा: उपलब्धियां और चुनौतियां
2013/14 अध्यापन और शिक्षण: सभी के लिए गुणवत्ता प्राप्त करना।
2012 युवा और कौशल: शिक्षा को कार्य से जोड़ना
2011 छिपा संकट: सशस्त्र संघर्ष और शिक्षा
2010 उपेक्षित वर्गों तक पहुंच बनाना
2009 असमानता दूर करना: शासन क्यों जरूरी है
2008 2015 तक सभी के लिए शिक्षा : क्या हम इसे पूरा करेंगे?
2007 ठोस आधार : शुरुआती बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा
2006 जीवन के लिए साक्षरता
2005 सभी के लिए शिक्षा: गुणवत्ता की अनिवार्यता
2003/4 जेंडर और सभी के लिए शिक्षा: समानता की ओर कदम
2002 सभी के लिए शिक्षा: क्या दुनिया सही रास्ते पर है?

हास्य-पुस्तक चित्रण टोबी मोरिस द्वारा

कवर फोटो सुलावेसी, इंडोनेशिया में तोगेन के द्वीपसमूहों में पलाउ पापन द्वीप से स्कूली बच्चों का है। बाजो जनजाति के बच्चे शहतीर के बने घरों में रहते हैं और रोज़ाना पास के मेलांगे द्वीप स्थित स्कूल जाने के लिए 1.8 कि.मी. लम्बा पुल पार करते हैं।

प्रस्तावना

मई 2015 में विश्व शिक्षा मंच ने इस एकमात्र लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 160 देशों से 1,600 भागीदारों को इंचेओन (कोरिया गणराज्य) में एकजुट किया: 2030 तक सभी के लिए समग्र और समान गुणवत्ता शिक्षा, तथा आजीवन शिक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए?

शिक्षा 2030 के लिए इंचेयोन घोषणा "समग्र और समान गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए दीर्घावधि शिक्षा अवसरों को प्रोत्साहित करना" शिक्षा पर स्थायी विकास लक्ष्य की रूपरेखा बनाने में काफी कारगर रही है।

इसने यूनस्को को शिक्षा 2030 के एजेंडा का नेतृत्व, समन्वय और निगरानी करने का कार्यभार सौंपा है। इसमें वैश्विक शिक्षा निगरानी (जीईएम) रिपोर्ट से अगले पंद्रह वर्षो के लिए शिक्षा पर स्थायी विकास लक्ष्य (एसडीजी-4), तथा अन्य एसडीजी में शिक्षा की स्वतंत्र निगरानी करने और रिपोर्टिंग उपलब्ध कराने का आह्वान किया गया है।

इस एजेंडा का अनंतिम लक्ष्य किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। इसके लिए ठोस आंकड़ों और सुदृढ़ निगरानी की आवश्यकता है। जीईएम रिपोर्ट के 2016 के संस्करण में एसडीजी-4 की निगरानी करने और प्रगति में तेजी लाने, उपलब्ध संकेतकों पर लक्ष्यों का निर्माण करने, संपूर्ण सफलता के उपायों के रूप में समानता तथा समग्रता के लिए सरकारों और नीति निर्माताओं की बहुमूल्य गहरी समझ को दर्शाया गया है।

इस रिपोर्ट में तीन संदेश पूरी तरह स्पष्ट किए गए हैं।

पहला, हमें नए दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता है। वर्तमान रुझानों के आधार पर केवल दो-तिहाई बच्चे ही 2030 में प्राथमिक शिक्षा पूरी कर पाएंगे, जबकि इस लक्ष्य को 2015 में पूरा कर लिया जाना चाहिए था। हमें इस रुझान को बदलने के लिए राजनीतिक इच्छा-शक्ति, नीतियों और अभिनवता तथा संसाधनों की आवश्यकता है।

दूसरा, यदि हम एसडीजी4 के बारे में गंभीर हैं तो हमें अत्यधिक तत्परता बरतते हुए कार्रवाई करनी होगी, और लम्बे समय तक के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। यदि हम इसमें असफल रहते हैं तो न केवल शिक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बल्कि इससे प्रत्येक और हरेक विकास लक्ष्य: गरीबी घटाना, भूख मिटाना, बेहतर स्वास्थ्य, स्त्री-पुरुष समानता तथा महिला सशक्तिकरण, स्थायी उत्पादन तथा खपत, नगरों का जीर्णोद्धार तथा अधिक समान और समावेशी समाजों का विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा।

अंत में, हमें जन कल्याण और वैश्विक विकास में शिक्षा और उसकी भूमिका के बारे में अपनी सोच में आमूल-चूल बदलाव लाना होगा। अब शिक्षा की पहले से कहीं अधिक सही प्रकार के कौशल, व्यवहार और विचारधारा विकसित करने की जिम्मेदारी है, जिससे स्थायी और समग्र विकास होगा।

2030 स्थायी विकास एजेंडे में हमसे अपेक्षा की गई है कि हम सामना की जा रही कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए सामूहिक और एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करें। इसका अर्थ है कि हमें पारंपरिक सीमाओं को तोड़ते हुए प्रभावी, बहु क्षेत्रीय भागीदारी करनी होगी।

सभी के लिए स्थायी भविष्य मनुष्य के सम्मान, उसकी सामाजिक पहचान और पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। यह ऐसा भविष्य है जहां आर्थिक विकास में असमानता नहीं होगी बल्कि इसमें सभी संपन्न होंगे, जहां शहरी क्षेत्र और श्रम बाजारों की रूपरेखा हर किसी को सशक्त बनाएगी और आर्थिक गतिविधियां, लोग और कॉर्पोरेट जगत हरित विकास की ओर अग्रसर होगा। स्थायी विकास का मानना है कि मानव विकास स्वस्थ धरती के बिना नहीं हो सकता। नए एसडीजी एजेंडा में हम सभी को पूरी जिन्दगी सीखते रहने के अनंतिम उद्देश्य को दर्शाया गया है। यदि इसका सही प्रयोग किया जाए तो शिक्षा में इतनी ताकत है कि वह नागरिकों को अधिकार संपन्न, प्रभावी और दक्ष बना सकती है जो सुरक्षित, हरी-भरी और कल्याणकारी धरती के लिए प्रयास करेंगे। इस नई रिपोर्ट में इन चर्चाओं के लिए तर्कसंगत साक्ष्य और सभी के लिए इसे साकार रूप देने की नीतियों की रूपरेखा दी गई है।

ईरिना बोकोवा
महानिदेशक, यूनेस्को

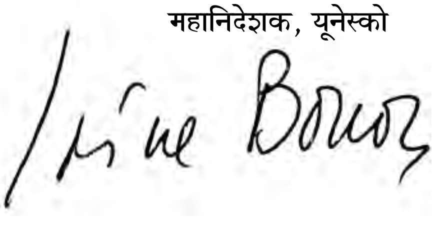

भूमिका

2016 वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट (जीईएम रिपोर्ट) गहन और चिंताजनक, दोनों है। यह विस्तृत, गंभीर और गहरी समझ वाली रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट निराशा भी पैदा करती है। यह प्रमाणित करती है कि शिक्षा स्थायी विकास और स्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का आधार है, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट करती है कि हम एसडीजी को प्राप्त करने से अभी कितना दूर हैं। यह रिपोर्ट दुनिया भर के लिए एक खतरे की घंटी साबित होनी चाहिए जो हमसे एसडीजी4 को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने का आह्वान करती है।

जीईएम रिपोर्ट में यह आधिकारिक लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है कि स्थायी विकास के प्रत्येक आयाम के लिए शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण निवेश है। बेहतर शिक्षा से व्यापक संपन्नता, उन्नत कृषि, बेहतर स्वास्थ्य परिणाम, कम हिंसा, अधिक स्त्री-पुरुष समानता, उच्च सामाजिक पूंजी और उन्नत प्राकृतिक पर्यावरण विकसित होगा। शिक्षा दुनिया भर में लोगों को यह समझाने में मदद करेगी कि स्थायी विकास हम सभी के भविष्य के लिए इतनी महत्वपूर्ण अवधारणा क्यों है? शिक्षा हमें प्रमुख साधन उपलब्ध कराती है जैसे अर्थव्यवस्था, सामाजिक, प्रौद्योगिकी, और नीतिपरकता भी – ताकि एसडीजी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हासिल किया जा सके। पूरी रिपोर्ट में इन तथ्यों को बेहद सूक्ष्म और विशिष्ट ब्यौरे के साथ प्रस्तुत किया गया है। तालिकाओं, ग्राफ और मूल-पाठ के जरिए विशद और बहुमूल्य जानकारी दी गई है।

फिर भी रिपोर्ट में उन महत्वपूर्ण कमियों को भी उजागर किया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया आज कहां खड़ी है तथा 2030 तक उसने कहां तक पहुंचने का संकल्प किया है। अमीर और गरीब के बीच देश के अंदर और देशों के बीच शिक्षा प्राप्त करने में जो बड़ा अंतर व्याप्त है, वह भयभीत करने वाला है। कई गरीब देशों में गरीब बच्चों को मौजूदा स्थितियों में काफी अधिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। उनके घर में किताबें नहीं होतीं; प्राथमिक शिक्षा से पहले स्कूल जाने का कोई अवसर नहीं होता, और उन्हें बिजली, पानी, स्वच्छता, योग्य शिक्षक, पाठ्य पुस्तकें तथा बुनियादी शिक्षा की अन्य सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं होती तथा जो किसी भी गुणवत्ता शिक्षा के लिए जरूरी होती हैं। इसके प्रभाव चौंकाने वाले हैं। हालांकि एसडीजी-4 में 2030 तक सार्वभौमिक ऊपरी माध्यमिक शिक्षा को पूरा करने की अपेक्षा की गई है, किंतु कम आय वाले देशों में शिक्षा को पूरा करने की मौजूदा दर मात्र 14% है (पूरी रिपोर्ट की तालिका 10.3)।

जीईएम रिपोर्ट में यह महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया है कि यदि मौजूदा रुझान बना रहा तो कितने देश 2030 लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे या यह भी कि इस क्षेत्र में सबसे तेजी से सुधार करने वाला देश कौन सा है। इसका सीधा सा उत्तर है: हमें अभूतपूर्व प्रगति करनी होगी, और शुरुआत तत्काल करनी होगी ताकि एसडीजी-4 को प्राप्त किया जा सके।

आलोचक कह सकते हैं, 'हमने आपको बताया था, एसडीजी-4 को हासिल करना नामुमकिन है', और सुझाव दिया था कि हम 'यथार्थ' को स्वीकार करें। फिर भी, चूंकि इस रिपोर्ट में कई बातों की जोरदार ढंग से आलोचना की गई है, अत: इसे नज़रअंदाज करना लापरवाह और अनैतिक हो सकता है। यदि हम वर्तमान युवा पीढ़ी को पर्याप्त स्कूली शिक्षा नहीं देंगे, तो हम उन्हें नरक में धकेल देंगे, और दुनिया का भविष्य गरीबी, पर्यावरण समस्याओं और आने वाले दशकों में सामाजिक हिंसा और अस्थिरता से परिपूर्ण होगा। इसे नज़रअंदाज करने का कोई बहाना नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट का संदेश यह है कि हमें शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य हासिल करने में तेजी लाने के लिए एक-साथ मिलकर अभूतपूर्व ढंग से कार्य करना होगा।"

इसमें तेजी लाने का सबसे अहम पहलू धन की व्यवस्था करना है। यहां फिर से रिपोर्ट में बड़ी साधारण बात कही गई हैं। आज शिक्षा के लिए विकास सहायता 2009 के स्तर से कम है (पूरी रिपोर्ट का चित्र 20.7)। यह पूर्णतया अमीर देशों की अदूरदर्शिता का नतीजा है। क्या दान देने वाले इन देशों का वास्तव में यह मानना है कि दुनिया

के कम आय वाले देशों में शिक्षा पर कम निवेश करके वे 'पैसे की बचत' कर रहे हैं? इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, उच्च आय वाले देशों के नेता और नागरिक यह बात अच्छी तरह जान जाएंगे कि शिक्षा में निवेश करना दुनिया के हित के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है; और यह कि सहायता का मौजूदा स्तर प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है - जो अमीर देशों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मात्र 5 अमेरिकी डॉलर बैठता है! - जो भविष्य में दुनिया में स्थायी विकास और शांति कायम करने के लिए बेहद मामूली कीमत है।

2016 जीईएम रिपोर्ट में अनेक गहरी दूरदर्शिता, सिफारिशें और विकास के मानक दिए गए हैं। इसमें एसडीजी-4 की निगरानी करने और प्रगति को मापने के बहुमूल्य सुझाव दिए गए हैं। इसमें दाखिला और शिक्षा को पूरा करने के सख्त पैमानों, जिन पर आज हम निर्भर हैं, की बजाय शिक्षा में निवेश, गुणवत्ता और शिक्षा हासिल करने के अधिक बेहतरीन तरीकों को उदाहरण देकर समझाया गया है। इन विस्तृत आंकड़ों, बेहतर सर्वेक्षण पद्धतियों, सुविधा केन्द्रों द्वारा निगरानी और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके हम सभी स्तरों पर शिक्षा प्रक्रिया और उसके निष्कर्षों का कहीं अधिक गहन अनुमान लगा सकते हैं।

पंद्रह वर्ष पहले, दुनिया ने एड्स महामारी की विशालता तथा स्वास्थ्य की अन्य आपात स्थितियों को अंततः स्वीकार किया था तथा मिलेनियम विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जन स्वास्थ्य गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए थे। इस प्रकार एड्स, तपेदिक और मलेरिया वैश्विक टीका एवं टीकाकरण समझौता (अब गावी, वैक्सीन समझौता) तथा अन्य कई समस्याओं से लड़ने के लिए वैश्विक कोष बनाने जैसे प्रमुख कदम उठाए गए थे। इन प्रयासों से जन स्वास्थ्य गतिविधियों और धन की व्यवस्था करने में व्यापक बदलाव आया। हालांकि इससे जैसी संभावना थी, वैसा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था (चूंकि 2008 के वित्तीय संकट से जन स्वास्थ्य के वित्त-पोषण में वृद्धि रूक गई थी), लेकिन इससे कई महत्वपूर्ण खोज हुई जिसके प्रभावों को आज भी महसूस किया जा सकता है।

2016 की जीईएम रिपोर्ट को एसडीजी को आधार मानते हुए शिक्षा हेतु ऐसी ही कार्रवाई किए जाने के रूप में देखा जाना चाहिए। मैंने पिछले कुछ वर्षों में अपने निजी विचारों को कई बार दोहराया है कि शिक्षा के लिए एक वैश्विक कोष तुरंत बनाया जाना चाहिए जो एड्स, तपेदिक और मलेरिया के लिए वैश्विक कोष के सकारात्मक पहलू पर आधारित है। धन की समस्या शिक्षा की चुनौती का मूलाधार है, क्योंकि इस रिपोर्ट में अनेक देशों के बीच और देश के अंदर मौजूदा स्थिति से संबंधित आंकड़ों के हर पहलू को स्पष्ट किया गया है।

इस दस्तावेज में हमसे अवसरों और तात्कालिकता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने तथा एसडीजी-4 में अंतर्निहित लक्ष्य को घोषित वैश्विक लक्ष्य: सभी के लिए उत्तम सार्वभौमिक शिक्षा तथा जीवन भर सीखते रहना, का आह्वान किया गया है। मैं लोगों से इस रिपोर्ट को पढ़ने और इसके महत्वपूर्ण संदेश को आत्मसात करने का आग्रह करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन पर, स्थानीय समुदाय से लेकर वैश्विक समुदाय तक, प्रत्येक स्तर पर कार्रवाई करें।

जेफरी डी. सैक्स
स्थायी विकास लक्ष्यों पर
यूएन महासचिव के विशेष सलाहकार

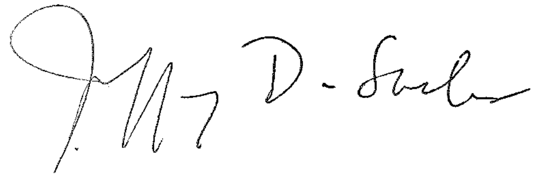

2016 वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट का सार

प्रस्तावना

सितंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें अधिवेशन में सदस्य देशों ने *अपनी दुनिया को बदलते हुए: स्थायी विकास के लिए 2030 का एजेंडा* नामक एक नए वैश्विक विकास एजेंडे को अपनाया। इसमें कुल 17 स्थायी विकास लक्ष्य (एसडीजी) हैं, जिनमें शिक्षा पर एसडीजी4 भी शामिल है। एसडीजी में 2030 तक की विकास प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं और यह मिलेनियम विकास लक्ष्य तथा सभी के लिए शिक्षा (ईएफए) लक्ष्य दोनों का स्थान लेगा, जिनकी अंतिम समय-सीमा 2015 में समाप्त हो गई थी।

> *जब तक स्कूल जाने की दर में पूरी तरह सुधार नहीं होगा, शिक्षा जीवन पर्यन्त हिस्सा नहीं बनती तथा शिक्षा प्रणालियां स्थायी विकास को पूरी तरह अपना नहीं लेतीं, तब तक शिक्षा का पूरा लाभ नहीं मिलेगा।*

नई वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट (जीईएम रिपोर्ट), जो पिछली *ईएफए वैश्विक निगरानी रिपोर्ट* श्रृंखला के अनुभवों पर आधारित है, ने नए 2030 एजेंडा के अंतर्गत शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक नया अध्यादेश प्राप्त किया है। 2016 जीईएम रिपोर्ट, जो नए 15 वर्षों की श्रृंखला में पहली है, शिक्षा तथा स्थायी विकास के अन्य पहलुओं के बीच जटिल संबंधों तथा एसडीजी4 के निगरानी प्रभावों को उजागर करती है। यह दर्शाती है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जब तक शिक्षा का पूरा दोहन नहीं होगा, स्कूल जाने की दर में पूरी तरह सुधार नहीं होगा, शिक्षा जीवन पर्यन्त हिस्सा नहीं बनती तथा शिक्षा प्रणालियां स्थायी विकास को पूरी तरह अपना नहीं लेतीं, तब तक दुनिया का विकास नहीं होगा।

रिपोर्ट के सैद्धांतिक पक्ष में उन साक्ष्यों, पद्धतियों और नीतियों को दर्शाया गया है जो यह दर्शाती हैं कि शिक्षा किस तरह समग्र स्थायी विकास एजेंडा में एक प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है। यह शिक्षा के स्वरूप के उन जरूरी तथ्यों को प्रस्तुत करता है जो गरीबी घटाने, भूख मिटाने, स्वास्थ्य में सुधार करने, स्त्री-पुरुष समानता और सशक्तीकरण, स्थायी कृषि, स्थिर शहरों तथा अधिक बराबरी वाले समग्र और न्यायसंगत समाज से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

निगरानी द्वारा मुख्य चुनौतियों से निपटा जाता है जैसे कि एसडीजी4 में हुई प्रगति का अनुमान कैसे लगाया जाए, जिसमें नीतिगत बदलाव के लिए की गई ठोस सिफारिश भी शामिल हैं। एसडीजी4 में प्रत्येक सात शिक्षा लक्ष्यों तथा तीन कार्यान्वयन पहलुओं की बारी-बारी से जांच की जाती है। इसके अलावा, शिक्षा, वित्त और शिक्षा प्रणालियों का इस दृष्टि से विश्लेषण किया जाता है कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अगले 15 वर्षों के दौरान नींव पर इमारत खड़ी करने तथा अधिक प्रभावी और कुशल वैश्विक शिक्षा निगरानी एजेंडा हेतु संभावित सक्रियता बनाई जा सके।

तालिका – 1:

शिक्षा अन्य स्थायी विकास लक्ष्यों के साथ खास तौर पर किस तरह से जुड़ी है।

लक्ष्य 1	लोगों को गरीबी से निजात दिलाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है।	लक्ष्य 10	जहां समानता होती है, वहां शिक्षा सामाजिक और आर्थिक असमानता में निश्चित अंतर पैदा करती है।
लक्ष्य 2	शिक्षा लोगों की स्थायी कृषि पद्धतियों को अधिक से अधिक अपनाने और पोषण को समझने में अहम भूमिका निभाती है।	लक्ष्य 11	शिक्षा लोगों को अधिक स्थिर शहरों को आकार देने और बनाए रखने में भागीदारी के लिए कौशल, और आपदा की स्थिति में लचीलापन प्रदान कर सकती है।
लक्ष्य 3	शिक्षा जल्दी मृत्यु दर, प्रजनन स्वास्थ्य, रोगों के फैलने, स्वस्थ जीवन शैली और तंदरुस्ती सहित स्वास्थ्य के अनेक मुद्दों में महत्वपूर्ण अंतर ला सकती है।	लक्ष्य 12	शिक्षा उत्पादन पद्धतियों (उदाहरण के लिए सर्कुलर इकोनोमी) में महत्वपूर्ण अंतर ला सकती है और उपभोक्ता उत्पादित वस्तुओं और अपशिष्ट को रोकने के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
लक्ष्य 5	महिलाओं और कन्याओं के लिए शिक्षा मूल साक्षरता प्राप्त करने, भागीदारीपूर्ण कौशल और योग्यताओं में सुधार करने और जीवन के अवसरों में सुधार करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है।	लक्ष्य 13	शिक्षा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को, विशेषकर स्थानीय स्तर पर व्यापक रूप से समझने तथा उसे अपनाने और उसके प्रभाव को कम करने में अहम भूमिका निभाती है।
लक्ष्य 6	शिक्षा और प्रशिक्षण दक्षता और प्राकृतिक संसाधनों को और अधिक बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ाते हैं तथा स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं।	लक्ष्य 14	शिक्षा समुद्री पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा अच्छे और स्थायी उपयोग के संबंध में सक्रिय आम राय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
लक्ष्य 7	शैक्षणिक कार्यक्रम विशेषकर अनौपचारिक और औपचारिक, बेहतर ऊर्जा संरक्षण और अक्षय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित कर सकते हैं।	लक्ष्य 15	शिक्षा और प्रशिक्षण स्थायी आजीविका तथा प्राकृतिक संसाधनों और जैव-विविधता, विशेषकर खतरे में पड़े पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए दक्षता और क्षमता को बढ़ाते हैं।
लक्ष्य 8	आर्थिक व्यवहार्यता, उद्यमशीलता, जॉब मार्केट दक्षता और शिक्षा के स्तर जैसे क्षेत्रों के साथ सीधा संपर्क होता है।	लक्ष्य 16	सामाजिक शिक्षा सामाजिक संबद्धता के साथ-साथ समग्र और उचित समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
लक्ष्य 9	अधिक लचीला ढांचा बनाने और अधिक स्थिर औद्योगिकीकरण संबंधी अपेक्षित दक्षता विकसित करने के लिए शिक्षा का होना आवश्यक है।	लक्ष्य 17	आजीवन सीखने से स्थायी विकास नीतियों और पद्धतियों को समझने और प्रोत्साहित करने की क्षमता बढ़ती है।

स्रोत: ऐसीएसयु तथा ऐएसएससी (2015)

डैन सा स्कूल, नाइजर में बच्चे ब्लैकबोर्ड का सहारा लेकर लिखते हुए

तगाजा डजिबो /यूनेस्को

पृथ्वी

@GEMReport #SDG4All bitly.com/sdg4all

शिक्षा और स्थायी विकास: ये कैसे जुड़े हैं और ये बिंदु क्यों महत्वपूर्ण हैं?

पृथ्वी: पर्यावरण स्थिरता

व्यक्तिगत और सामूहिक मानव कृत्यों ने धरती पर काफी दबाव डाला है और जीवन को इसके सहारे की जरूरत है। चूंकि मानवजाति पर्यावरण को दूषित करने, जैव-विविधता की तेजी से नष्ट करने तथा जलवायु को स्पष्ट रूप से प्रभावित करने का कारण बन रही है, अत: इसके कार्यों से उत्पन्न होने वाली इन चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान भी निकालने होंगे।

शिक्षा सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के प्रयासों के अनुरूप पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए स्थायी समाज बनाने में अपेक्षित परिवर्तन लाने में प्रमुख भूमिका निभा सकती है। शिक्षा मूल्यों और विचारधाराओं को आकार प्रदान करती है। यह दक्षता, विचारधारा और साधनों का विकास करने में भी मदद करती है जिनका इस्तेमाल अस्थायी पद्धतियों को कम करने या रोकने के लिए किया जा सकता है।

स्थिरता लाने के लिए शिक्षा की बहुआयामी भूमिका प्राय: सकारात्मक नहीं होती। यह अस्थायी पद्धतियों को बढ़ा सकती है, जिससे संसाधनों की अधिक खपत होती है, तथा स्थायी स्वदेशी ज्ञान को तेजी से नुकसान पहुंचता है तथा जीवन जीने की शैली बदल सकती है। शिक्षा को इस तरह से आकार देने और बदलने की जरूरत है ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव बना रहे।

मनुष्य के व्यवहार के कारण पर्यावरण संकट पैदा हुआ है

मनुष्य के व्यवहार के तीन सबसे समान कारण हैं जिनसे पर्यावरण के लिए संकट पैदा हुआ है। इसमें जनसंख्या का अध्ययन, आधुनिक जीवन शैली तथा व्यक्तिगत व्यवहार शामिल है। जनसंख्या का अध्ययन बतलाता है कि धरती पर काफी अधिक लोग रहते हैं, दुनिया की आबादी 1950 से 2015 के बीच तीन गुणा हो गई है, और इसके 2030 तक बढ़कर 8.5 बिलियन होने की संभावना है। आधुनिक जीवनशैली अवधारणा में शहरी क्षेत्रों और संपन्न देशों में लोगों द्वारा प्रति व्यक्ति संसाधनों की काफी अधिक खपत की जाती है। जिन देशों में जीवन स्तर तेजी से बढ़ा है, वहां पिछले दो दशकों में उनके पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव लगभग दुगना हो गया है। वर्ष 2012 में, अधिकांश उच्च आय वाले देशों में पर्यावरण प्रणाली कमजोर हुई थी। व्यक्तिगत व्यवहार से यह स्पष्ट हुआ है कि व्यक्ति ही पर्यावरण समस्याओं का कारण है और इनका संभावित समाधान भी उनके ही पास है, उदाहरण के लिए रिसाइकलिंग, साइकिल का प्रयोग और ईंधन बचाने वाली कारों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाना।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए सीखना अनिवार्य है

पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा अहम भूमिका निभा सकती है। विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के शिक्षित होने से जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने तथा गर्भधारण के समय का निर्णय लेने में उसकी राय लेना सबसे कारगर माध्यम है। शिक्षा आय बढ़ाकर आजीविका में सुधार कर सकती है और कुशल लोग अर्थव्यवस्था तथा खाद्य प्रणालियों को बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षा समकालीन, परंपरागत और आजीवन दृष्टिकोण की समझ द्वारा व्यक्ति और सामूहिक परिवेश को प्रभावित कर सकती है।

> *"78 देशों के पाठ्यक्रमों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि 55% देश 'पारिस्थितिकी' और 47% देश 'पर्यावरण शिक्षा' शब्दों का प्रयोग करते हैं।"*

समकालीन दृष्टिकोण: स्कूली शिक्षा के माध्यम से सीखना

पर्यावरण की किसी समस्या, उसके परिणामों तथा इसके समाधान के लिए की जाने वाली कार्रवाई को समझाने में स्कूल छात्रों की मदद करते हैं। पर्यावरण से संबंधित जानकारी को स्कूल के औपचारिक पाठ्यक्रमों में अधिक से अधिक शामिल किया जा रहा है। 78 देशों के पाठ्यक्रमों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि 55% देश "पारिस्थितिकी" और 47% देश "पर्यावरण शिक्षा" शब्दों का प्रयोग करते हैं।

उदाहरण के लिए, भारत में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 2003 में सरकारी एजेंसियों ने पर्यावरण शिक्षा पर काफी अधिक सामग्री का प्रयोग किया, जिसके कारण 30 करोड़ छात्रों ने 10 लाख 30 हजार स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया।

चित्र – 1:

पर्यावरण की कीमत पर उच्च स्तरीय मानव विकास हुआ है

देशों द्वारा पर्यावरण पर डाले जाने वाला समग्र प्रभाव, मानव विकास सूचकांक, 2012

वर्तमान जनसंख्या और उपलब्ध उत्पादक भूमि और समुद्री क्षेत्र (जैव क्षमता) को देखते हुए ***पर्यावरण फुटप्रिंट*** प्रति व्यक्ति 1.7 वैश्विक हेक्टेयर से कम है, जो स्थायी है; पृथ्वी देश के संसाधन उपयोग को फिर से पूरा कर सकती है।

मानव विकास सूचकांक (एचडीआई, यूएन विकास कार्यक्रम द्वारा) में स्वास्थ्य, ज्ञान और जीवन स्तर में देश की औसत उपलब्धि को मापा गया है। 0.8 या अधिक की एचडीआई मूल्य बहुत अधिक मानव विकास को दर्शाता है।

सिंगापुर की उच्च एचडीआई (0.91) प्रति व्यक्ति व्यापक पर्यावरण फुटप्रिंट (7.97) से संबद्ध है। इसका अर्थ है कि हालांकि सिंगापुर में लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, फिर भी वहां संसाधनों की उच्च मांग है।

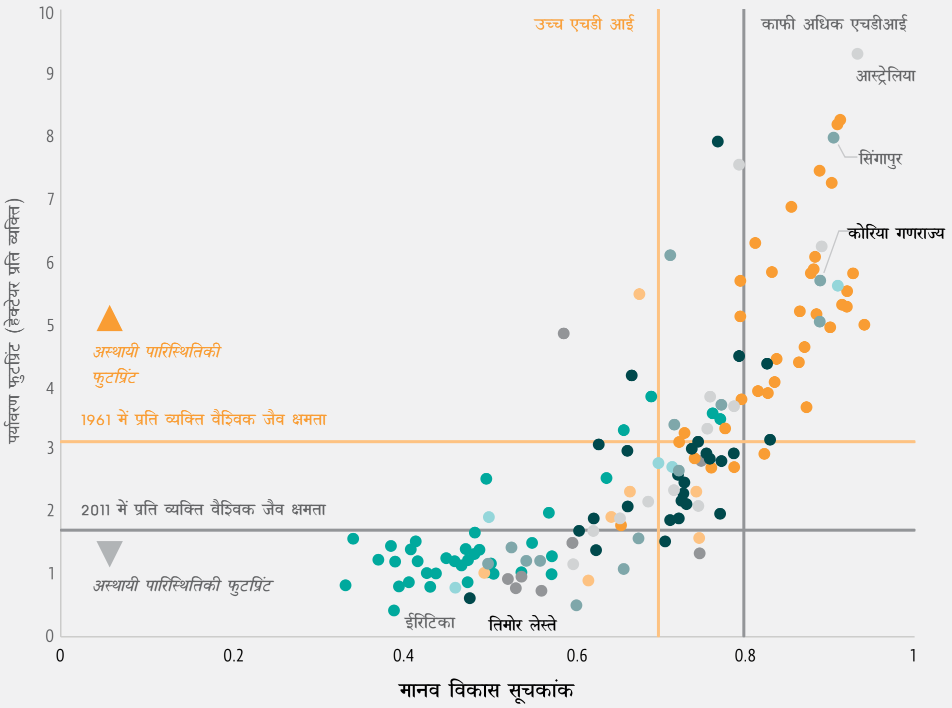

- काकेशस और मध्य एशिया
- पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया
- यूरोप और उत्तरी अमेरिका
- लेटिन अमेरिका और कैरेबियन
- उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया
- प्रशांत
- दक्षिणी एशिया
- उप-सहारा अफ्रीका

स्रोत: जीईएम रिपोर्ट दल का विश्लेषण वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क (2016) पर आधारित

पर्यावरण शिक्षा स्थिर जीवन शैली, कचरे को कम करने, किफायती ऊर्जा उपयोग, सार्वजनिक परिवहन के बढ़ते उपयोग, पर्यावरण अनुकूल नीतियों तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करती है। एस्टोनिया और स्वीडन में जहां स्थायी विकास पाठ्यक्रम का हिस्सा है, के छात्रों ने, जिन देशों ने स्थायी विकास को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया था, के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन 2006 कार्यक्रम में पर्यावरण विज्ञान के बारे में सही उत्तर दिए। कुछ स्कूलों ने 'पूरे स्कूल' में पर्यावरण शिक्षा दृष्टिकोण अपनाया है। इंग्लैण्ड (यूनाइटेड किंगडम) में ऐसे स्कूलों पर किए गए शोध से पता चला है कि इससे स्कूलों के आचरण और छात्रों के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार हुआ है तथा स्कूलों में पर्यावरण को होने वाले नुकसान में कमी आई है।

पारंपरिक दृष्टिकोण : समुदाय के माध्यम से सीखना

कृषि, खाद्य उत्पादन और संरक्षण जैसे क्षेत्रों में पारंपरिक – विशेषकर स्वदेशी – ज्ञान ने सदियों से पर्यावरण में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जैव विविधता और पर्यावरण प्रणाली प्रक्रिया का संरक्षण करने के लिए विश्व स्तर पर उत्कृष्ट दृष्टिकोण के रूप में स्वदेशी लोगों की पारंपरिक भूमि प्रबंधन प्रक्रिया के कई उदाहरणों को अपनाया गया है। कोलंबिया में, अमेरिका की स्थायी बसावट परिषद *बिएन विविर* (अच्छी तरह से रहना) की अवधारणा को लागू कर रही है, जिसमें स्वदेशी लोगों के योगदान को मान्यता दी गई है, उदाहरण के लिए शहरी पर्यावरण-बारियो परियोजनाएं, पारंपरिक रूप से स्थिर गांव, और स्थायी शिक्षा केन्द, शामिल हैं। स्थानीय और स्वदेशी जानकारी ने पर्यावरण की कार्यप्रणाली, आपदा संबंधी शुरुआती चेतावनी प्रणाली तथा जलवायु परिवर्तन के अनुरूप नीतियां अपनाने में योगदान दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का ग्रामीण व्यवस्थित पहल, जिसमें छात्र अपने देश के बुजुर्गों से बातचीत करते हैं, स्वदेशी ज्ञान से स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का एक उदाहरण है। स्कूली दिशा-निर्देशों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने से पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को साझा करने में मदद मिलती है।

आजीवन सीखने का दृष्टिकोण: कार्य और रोजमर्रा के जीवन से सीखना

औपचारिक शिक्षा के अलावा, सरकारी एजेंसियां, धार्मिक संगठन, लाभ अर्जित न करने वाले समुदाय समूह, श्रम संगठन और निजी क्षेत्र सभी व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं।

सरकार द्वारा समर्थित अभियान पर्यावरण समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं, इसके कारणों को बता सकते हैं और यह दर्शा सकते हैं कि लोग इसका कैसे समाधान कर सकते हैं। वर्ष 2015 में इथियोपिया की सरकार तथा भागीदारों ने सौर ऊर्जा से चलने वाले उत्पादों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दो वर्षीय जन-जागरूकता अभियान शुरू किया।

धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक नेता पर्यावरण के महत्व और व्यवहार का प्रचार-प्रसार करने में मदद कर सकते हैं। पर्यावरण की हिमायत करने के इन उदाहरणों में पोप फ्रांसिस, दलाई लामा और जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के लिए मुस्लिम एसोसिएशन शामिल हैं।

पर्यावरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यस्थल एक अहम केन्द्र होता है। कंपनियों ने अपने पर्यावरण में सुधार करने तथा अपने कर्मचारियों और जनता को पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागरूक किया है। 2008 में किए गए इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट सर्वेक्षण से पता चला है कि विश्व स्तर पर 40% से अधिक एक्जीक्यूटिव ने यह माना कि उनकी कंपनियों के लिए अपने व्यवसाय में स्थिरता लाना जरूरी है। श्रम संगठनों ने भी अधिक उपयुक्त कार्यस्थल पद्धतियों को प्रोत्साहित किया है।

जन सूचना अभियान, परियोजनाएं, सहभागिता और हरित गठबंधन, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) संरक्षण के लिए जन समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवाज जैसे वेब-आधारित अभियान समूह पर्यावरण पर जागरूकता पैदा करने में मदद करते हैं जिसमें 194 देशों के 44 मिलियन सदस्य शामिल हैं। ये सभी पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं जिन्होंने मधुमक्खी के कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दो वर्ष तक अभियान चलाया।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संगठित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता

शिक्षा जलवायु से जुड़े जोखिमों के बारे में लोगों की समझ को बढ़ाती है। यह इन जोखिमों को कम करने में उनका समर्थन करती है और भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करती है। आधारभूत ढांचे जैसे सी-वॉल और सिंचाई प्रणालियों में निवेश करने की तुलना में जलवायु परिवर्तन प्रभावों के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार करना अधिक प्रभावी होता है। महिलाओं के शिक्षित होने से आपदा से होने वाली दुर्घटनाएं कम होती हैं। अनुमान दर्शाते हैं कि यदि शिक्षा का विकास रुक जाए तो आपदा से संबंधित भावी दुर्घटनाएं प्रति दशक 20% तक बढ़ जाएंगी। जलवायु संबंधी घटनाओं के जोखिम से प्रभावित होने वाली अधिकांश आबादी आम तौर पर उन देशों से होती हैं जहां शिक्षा का प्रसार कम और एक-समान नहीं है।

> “यदि शिक्षा का विकास रुक जाए तो आपदा से संबंधित भावी दुर्घटनाएं प्रति दशक 20% तक बढ़ जाएंगी।”

शिक्षा लोगों को जलवायु से संबंधित आपदाओं से निपटने और स्वयं को उसके अनुसार ढालने में मदद कर सकती है। क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य तथा हैती पर हुए अध्ययन में पाया गया कि शिक्षा की कमी और कम साक्षरता दर होने के कारण लोग आपदा चेतावनियों को समझ नहीं सके। फिलीपीन्स में स्थानीय लोगों ने शिक्षा अधिकारियों और उनके भागीदारों के साथ मिलकर युवाओं को जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया जिसने लोगों को इसका सामना करने में मदद की।

समृद्धि

हमारी दुनिया तेजी से बदल रही है। पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक रूप से।
हम केवल लगातार खरीदते जाना, और बिना सावधानी बरते उत्पादन करते जाना जारी नहीं रख सकते। हमारी दुनिया को इस तरह से विकास करना होगा जिसमें हर कोई शामिल हो और भावी पीढ़ी के लिए हमारी पृथ्वी का ख्याल रखे।
इसका अर्थ है नया कौशल सीखना और पूरी जिन्दगी सीखते जाना।
उदाहरण के लिए, किसान सीख सकते हैं कि और अधिक कैसे उगाया जाए, और इस तरह से उगाया जाए कि इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे
शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने से लोगों को मदद मिलेगी – और इससे हमारा आशय सभी लोगों से है! अधिक शिक्षा प्राप्त करने पर, लोगों को अधिक पैसा मिलेगा और वे गरीबी से मुक्त हो जाएंगे।
लेकिन शिक्षा का भी विकास करना होगा – कंप्यूटर आज कई तरह के कार्य कर सकता है, इसलिए छात्रों को अधिक कौशल की जरूरत है, और यह बदलती दुनिया के कार्य के अनुरूप होना चाहिए।

संपन्नता: स्थायी और संपूर्ण अर्थव्यवस्था

यदि 2030 एजेंडा को सफल बनाना है तो विश्व अर्थव्यवस्था को पर्यावरण रूप से स्थायी और संपूर्ण बनना होगा। इस बदलाव में शिक्षा की प्रमुख भूमिका है।

उत्पादन और खपत को स्थायी बनाने के लिए शिक्षा और आजीवन शिक्षा, हरित उद्योग का सृजन करने के लिए दक्षता प्रदान करने और हरित उपायों के लिए खोज करना आवश्यक है। इसमें कृषि जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों को अहम भूमिका निभानी होगी, जिस पर संपन्न और गरीब देश तथा परिवार निर्भर करते हैं।

जिस तरह अर्थव्यवस्था को स्थिर होना चाहिए उसी तरह यह अधिक समावेशी होनी चाहिए तथा इससे असमानता कम होनी चाहिए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तम शिक्षा अहम योगदान दे सकती है। मानव कल्याण पर आधारित समग्र आर्थिक विकास के लिए दक्ष और शिक्षित श्रमबल का होना अनिवार्य है। शिक्षा अच्छा कार्य ढूंढ़ने और पर्याप्त मात्रा में आय कमाने के अवसरों को बढ़ाकर गरीबी को कम करती है तथा स्त्री-पुरुष असमानता, सामाजिक-आर्थिक स्तर तथा भेदभाव के अन्य आधार के कारण मजदूरी के अंतर को समाप्त करने में मदद करती है।

उद्योग को हरा-भरा बनाने से कुशल कर्मचारियों की मांग बढ़ेगी

स्थिर विकास और हरियाली के साथ विकास करने का अर्थ है हरित उद्योग बनाना और मौजूदा उद्योगों को 'हरा-भरा' बनाना। हरित उद्योगों में पहले से ही बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, और कम आय वाले देशों में इनके पर्याप्त रूप से बढ़ने की संभावना है। उदाहरण के लिए, अक्षय ऊर्जा स्रोत 2015 से 2040 के बीच विश्व स्तर पर बिजली के उत्पादन में कुल वृद्धि का लगभग आधा भार उठाएंगे, जिनका विकास मुख्य रूप से चीन, भारत, लेटिन अमेरिका और अफ्रीका में होगा।

हरित उद्योग बनाने के लिए अत्यधिक कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जो विशेष उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं; मौजूदा उद्योगों को हरा-भरा बनाने में कार्यरत निम्न और मध्यम कुशल कामगारों को निरंतर शिक्षित और प्रशिक्षित करने की जरूरत होती है। नीति निर्माताओं और शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि कौन सी दक्षता सिखाई जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव होता रहता है।

स्थिर और हरित विकास के लिए अनुसंधान और विकास में काफी अधिक निवेश करना पड़ता है। उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए विशिष्ट ज्ञान और कौशल वाले विभिन्न क्षेत्रों के काफी अधिक लोगों की जरूरत होती है, जिनके लिए विविध और विशिष्ट पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है तथा इन क्षेत्रों में सहकारी अध्ययन कार्यक्रमों की जरूरत होती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि सरकारों को कार्बन की तीव्रता को कम करने के लिए वर्ष में पांच गुणा अधिक ऊर्जा अनुसंधान और विकास करना होगा।

शिक्षा कृषि का स्वरूप बदलने में मदद कर सकती है

> "साक्षरता और कृषि विस्तार कार्यक्रम किसानों की उत्पादकता को 12% तक बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।"

दुनिया भर में कृषि को 2015-2030 के बीच अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना होगा। यह आर्थिक क्षेत्रों में से एक है जहां पर्यावरण के नुकसान का अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है और यह एक-तिहाई ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। इस दौरान, जनसंख्या वृद्धि के लिए बड़ी मात्रा में खाद्य उत्पादन में स्थायी वृद्धि तथा खाद्य आपूर्ति का और अधिक समान वितरण किए जाने की आवश्यकता होगी।

शिक्षा स्थिर खाद्य उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा भावी किसान फाउंडेशन कौशल तथा कृषि में स्थिरता संबंधी चुनौतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल नीतियां किसानों और नई प्रौद्योगिकी के बीच के फासले को कम करती हैं। साक्षरता और कृषि विस्तार कार्यक्रम किसानों को उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा से संबंधित कृषि अनुसंधान नई खोज में मदद करता है जिससे स्थिरता बढ़ती है। फिर भी कई देश और दानदाताओं ने ऐसे अनुसंधान में निवेश को रोक दिया है या उसमें कमी की है। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक कृषि अनुसंधान पर वैश्विक खर्च में उप-सहारा अफ्रीका अंशदान 1960 में 10% से घटकर 2009 में 6% रह गया है।

शिक्षा और आजीवन शिक्षा दीर्घावधि आर्थिक विकास में योगदान देती है

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का स्तर बढ़ाने से दीर्घावधि आर्थिक विकास होगा। शिक्षा नीति का प्रारंभिक स्तर 1965 से 2010 के बीच पूर्वी एशिया और उप-सहारा अफ्रीका के बीच विकास दर में आधे के अंतर को स्पष्ट करता है। उत्कृष्ट शिक्षा और अत्यधिक कुशल कर्मचारियों से उत्पादकता बढ़ती है और प्रौद्योगिकी में बदलाव आता है। शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में अंतर से पूर्वी एशिया में आर्थिक विकास में हुए 'चमत्कार' और लेटिन अमेरिका में 'व्यर्थ हुए दशकों' को समझने में मदद मिलती है। देशों को संपन्न होने के लिए अच्छी बेहतरीन माध्यमिक और उच्च शिक्षा में निवेश करना जरूरी है। यह विशेषकर उप-सहारा अफ्रीका के मामले में सत्य है, जहां वर्ष 2014 में उच्च शिक्षा में कुल दाखिला अनुपात मात्र 8% था।

> "वर्ष 2020 तक उच्च शिक्षा प्राप्त मात्र 40 मिलियन कर्मचारी होंगे जो दुनिया की मांग के अनुसार काफी कम हैं"

यदि शिक्षा को विकास करना है, तो उसे दुनिया में तेजी से बदलते कार्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। प्रौद्योगिकी ने न केवल उच्च दक्षता वाले कर्मचारियों की मांग बढ़ाई है बल्कि इसने मध्यम दक्षता वाली नौकरियों जैसे क्लर्क और सेल्स वर्करों और मशीन ऑपरेटरों की मांग भी कम की है, जिनका कार्य अब आसानी से मशीनों द्वारा किया जा सकता है। इससे भविष्य में लाखों लोग बेरोजगार होंगे। वर्ष में कुल रोजगार का दो-तिहाई से थोड़ा कम मध्यम स्तरीय कौशल व्यवसायों में था।

साक्ष्यों से पता चलता है कि अधिकांश शिक्षा प्रणालियां बाजार मांग के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रही हैं। वर्ष 2020 तक उच्च शिक्षा प्राप्त मात्र 40 मिलियन कर्मचारी होंगे जो दुनिया की मांग के अनुसार काफी कम हैं और निम्न शिक्षा स्तर पर 95 मिलियन कर्मचारी होंगे जो काफी अधिक हैं।

सामान्य, गहन शिक्षा आधारित दक्षता और योग्यता – गहन विचारधारा, समस्या समाधान, दल और परियोजना कार्य तथा ठोस साक्षरता, संचार और प्रस्तुति कौशल – के श्रम बाजार में अहम बने रहने की संभावना है। इसलिए बदलते और बुनियादी कौशल को प्राप्त करना भावी रोजगार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्रणालियों के लिए चुनौती यह है कि छात्रों को इसे सर्वाधिक प्रभावी ढंग से कैसे दिया जाए।

शिक्षा समाज में समग्रता में सहायता कर सकती है

शिक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य होती है कि आर्थिक विकास स्थायी हो तथा कोई भी इससे पिछड़ न जाए। शिक्षा विकास करती है, सबसे गरीब व्यक्ति की आय को बढ़ा सकती है और यदि इसका समान रूप से वितरण किया जाए तो यह असमानता दूर करती है। यदि हाल के 10 यूरोपीय यूनियन (ईयू) सदस्य राज्य 2020 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रारंभिक चरण में स्कूल छोड़ने की दर पर रोक लगाते हैं और उच्च स्तरीय भागीदारी को बढ़ाते हैं, तो इससे 3.7 मिलियन तक गरीबी का जोखिम कम हो सकता है।

फिर भी, प्रशिक्षण और दक्षता को बढ़ाने से समाज में व्याप्त असमानता में समान रूप से कमी नहीं आई है। शिक्षा का समान रूप से विस्तार करने के प्रयासों के लिए, सरकारों को देशों में आय में असमानता के बढ़ते रुझान को उलटने में मदद करने के लिए सामाजिक नीतियों को फिर से बांटने पर नए सिरे से ध्यान देना होगा।

शिक्षा श्रम बाजार के नतीजों में सुधार लाती है

विशेषकर संपन्न देशों में अधिक शिक्षित लोगों में बेरोजगारी की दर कम है। ओईसीडी में उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले 25 से 64 वर्ष की आयु के केवल 55% वयस्क 2013 में रोजगार प्राप्त थे, जबकि ऊपरी माध्यमिक या गैर-उच्च शिक्षा वाले 73% तथा उच्चतम शिक्षा प्राप्त 83% वयस्क रोजगार प्राप्त थे। गरीब देशों में प्राय: ऐसी स्थिति नहीं होती, जिससे यह पता चलता है कि कुशल श्रम सीमित मात्रा में उपलब्ध है और यह भी कि शिक्षा प्रणाली छात्रों को तर्कसंगत कौशल प्रदान नहीं कर रही है।

शिक्षा में असमानता को कम करने से कमजोर और उपेक्षित वर्गों में अच्छे कार्य बढ़ सकते हैं। वर्ष 2016 जीईएम रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि यदि अमीर और गरीब पृष्ठभूमि वाले कामगार एक-समान शिक्षा प्राप्त करें तो गरीबी में असमानता 39% तक कम हो सकती है।

शिक्षा का संबंध सीधे तौर पर आय से जुड़ा है – 139 देशों में स्कूल में प्रति अतिरिक्त वर्ष लौटने की दर 9.7% है। गरीब देशों, जहां कुशल कामगारों की कमी है, वहां लौटने की दर सबसे अधिक है। फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों को उच्च शिक्षा से सबसे अधिक लाभ हो, शिक्षा में निवेश आर्थिक नीतियों पर आधारित होना चाहिए ताकि कुशल श्रम की मांग बढ़ सके।

चित्र 2

शिक्षा का बढ़ता स्तर न्यून श्रमजीवी गरीबी से जुड़ा है।

12 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में शिक्षा स्तर पर श्रमजीवी गरीबी (मध्यम साप्ताहिक आय के 50% से कम)

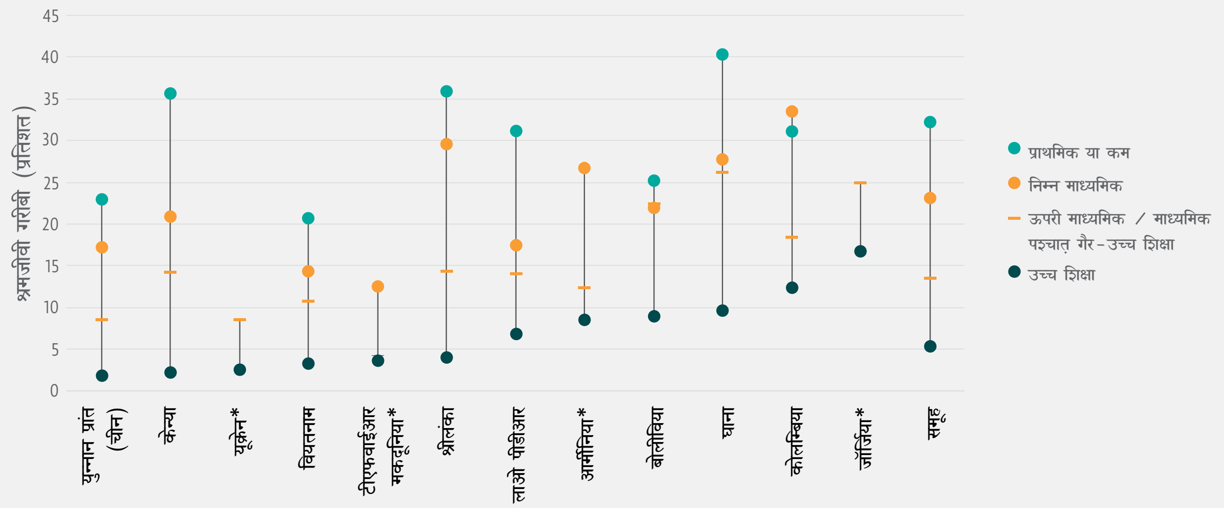

*टिप्पणियों की कम संख्या के कारण शिक्षा के स्तर को शामिल नहीं किया गया है।

नमूना 15-64 वर्ष की आयु के पूर्णकालिक कामगारों (कम से कम 30 घंटे प्रति सप्ताह) तथा शहरी क्षेत्रों में अल्प रोजगार प्राप्त लोगों तक सीमित है।

स्रोत: एसटीईपी कार्यशील आंकड़े। कम अंक की टिप्पणियों के कारण शिक्षा के स्तर में एस्ट्रिक लगे देशों को शामिल नहीं किया गया है।

हालांकि हरित विकास से रोजगार का विकास करके कई अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन इससे पर्यावरण का पालन न करने वाले उद्योग बंद हो जाते है और उनमें नौकरियां समाप्त हो जाती हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए आजीवन सीखने वाली नीतियों की आवश्यकता है ताकि रोजगार छूटने पर कामगार नए कार्यों को अपना सकें।

बोउकाको, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके उगाई गई कसावा की फसल के बीच खड़ा एक व्यक्ति

सौजन्य: रिक्कार्डो गंगाले/एफएओ

लोग

कुछ मामलों में हम काफी अलग हैं, लेकिन दूसरों मामलों में हम एक जैसे हैं: हम सभी चाहते हैं कि हमारा सम्मान किया जाए, हम स्वस्थ और सुरक्षित रहें।
यदि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें स्वस्थ रखना होगा। और यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको यह जानना होगा कि आप अपना ख्याल कैसे रखें।
दुर्भाग्यवश, जिन लोगों को इस शिक्षा की बेहद जरूरत है, वे प्रायः इससे वंचित रह जाते हैं।
और अन्य बुनियादी अधिकार भी
स्त्री–पुरुष असमानता आज भी एक बड़ी समस्या है। जरा सोचिए, दुनिया में व्यवसाय और राजनीति में कितनी महिला नेता हैं! महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उनके घरों में भी, रोज़ाना होती है।
लेकिन महिलाओं को शिक्षित करने से वे गलत निर्णयों के खिलाफ लड़ सकती हैं और उन्हें ऐसा करना चाहिए, तथा इससे उन्हें राजनीति में भाग लेने का बेहतर मौका मिलेगा और अच्छी नौकरी मिलेगी।
महिला को शिक्षित करने से उनके और उनके परिवार के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।
यदि हम स्त्री–पुरुष असमानता और शिक्षा में भेदभाव को समाप्त करना चाहते हैं तो अब समय आ गया है कि हम एक साथ मिलकर काम करें।

जनता : समग्र सामाजिक विकास

सामाजिक विकास से मानव कल्याण और समानता में सुधार होता है और यह लोकतंत्र और न्याय के अनुरूप होता है। शिक्षा, सामाजिक विकास लाने का एक सशक्त माध्यम है, और एक प्रमुख पहलू है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग स्वस्थ जीवन जी सकें और अपने बच्चों के जीवन में सुधार कर सकें। यह उपेक्षित जनसंख्या को सशक्त बनाकर स्त्री-पुरुष में समानता ला सकता है जिनमें से अधिकांश लड़कियां ओर महिलाएं होती हैं।

शिक्षा अन्य क्षेत्रों, जैसे स्वास्थ्य, पोषण, जल और ऊर्जा स्रोतों से परस्पर जुड़ी होती है। बच्चों के स्वस्थ रहने से उनकी सीखने की योग्यता निर्धारित होती है, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का प्रयोग शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, और स्वस्थ शिक्षक शिक्षा जगत का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं।

अंततः गरीबी की बहुआयामी चुनौतियों से निपटने के लिए मानव विकास हेतु एक सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है।

सभी के स्थिर भविष्य के लिए समग्र सामाजिक विकास महत्वपूर्ण होता है

> “महिलाएं, पुरुषों के मुकाबले कम से कम दो गुणा कार्य करती हैं जिसका उन्हें भुगतान नहीं मिलता।”

समग्र और संपूर्ण सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता, ऊर्जा, आवास और परिवहन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं की उपलब्धता अनिवार्य होती है, जिन्हें वर्तमान में हासिल करना संभव नहीं हैं। प्रगति के बावजूद, अधिकांश देशों में पुरुष-महिला असमानता बनी हुई है – उदाहरण के लिए महिलाएं, पुरुषों के मुकाबले कम से कम दो गुणा कार्य करती हैं जिसका उन्हें भुगतान नहीं मिलता, और वे प्रायः अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करती हैं।

समग्र और संपूर्ण सामाजिक विकास के लिए महिलाओं के खिलाफ भेदभाव बरतने, अशक्त लोगों, स्वदेशी जनसंख्या, जातीय और भाषायी अल्पसंख्यकों, शरणार्थियों और विस्थापित जनसंख्या तथा अन्य उपेक्षित समूहों की समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता होती है। भेदभाव के मानदंडों को बदलने तथा महिलाओं और पुरुषों को सशक्त बनाने से दी जाने वाली शिक्षा और ज्ञान, मूल्यों और व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है।

अनेक समूहों को शिक्षा की उपलब्धता और गुणवत्ता के अनुसार बांटा जाता है, जिसमें नस्लीय, जातीय और भाषायी अल्पसंख्यक, विकलांगों, चरवाहे, झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले, एचआईवी पीड़ित बच्चे, ‘लावारिस’ बच्चे और अनाथ शामिल हैं। देशों में शिक्षा निर्धारित करने का तरीका आय, स्थान, जातीयता तथा जेंडर में अंतर से तय होता है। शिक्षा के लिए गरीबी सबसे बड़ी बाधा है। 101 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 20 से 24 वर्ष के लोगों में अमीरों के मुकाबले गरीब लोगों ने औसतन 5 वर्ष की स्कूली शिक्षा कम प्राप्त की थी; शहरी और ग्रामीण लोगों के बीच 2.6 वर्ष तथा महिलाओं और पुरुषों के बीच 1.1 वर्ष का अंतर है।

इसके लिए प्रायः ये तथ्य जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए गरीब, जातीयता या अलग-थलग उपेक्षित पृष्ठभूमि की महिलाएं प्रायः अपने पुरुष सहयोगियों के खराब निष्पादन की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। अधिकांश देशों में, आधी से कम गरीब ग्रामीण महिलाएं बुनियादी रूप से साक्षर होती हैं। अफगानिस्तान, बेनिन, चाड, इथियोपिया, गिनी, पाकिस्तान और दक्षिण सुडान, जहां असमानता सबसे अधिक है, वहां सबसे गरीब युवती ने भी एक वर्ष तक स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी।

शिक्षा सामाजिक विकास के नतीजों में सुधार करती है

शिक्षा अनेक क्षेत्रों, विशेषकर स्वास्थ्य और महिलाओं की स्थिति के बारे में सामाजिक विकास के नतीजों में सुधार कर सकती है। यह स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष दक्षता तथा ज्ञान प्रदान करती है, व्यवहार में बदलाव लाती है ताकि चिकित्सा परिस्थितियों में सुधार हो सके। भारत, इंडोनेशिया, पारागुआ और तंजानिया गणराज्य में गरीब और कम शिक्षित माता-पिता इलाज के लिए नीम-हकीमों की शरण में जाते हैं।

स्कूल आधारित कार्यकलाप, जैसे भोजन और स्वास्थ्य अभियान का स्वास्थ्य पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने से हाजिरी बढ़ सकती है। उत्तरी ग्रामीण बुरकिना फॉसो में स्कूलों में रोजाना भोजन देने और राशन घर ले जाने से एक वर्ष बाद महिलाओं का दाखिला पांच से छह अंक तक बढ़ गया।

स्कूलों में कार्यकलाप स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे सकते हैं और इनसे व्यवहार में परिवर्तन आता है। स्कूलों में जल, स्वच्छता और साफ-सफाई गतिविधियों से स्वास्थ्य, आर्थिक तथा स्त्री-पुरुष समानता में सुधार होता है। फिनलैण्ड में स्कूली भोजन को शिक्षा

> नाइजीरिया में स्कूल में चार अतिरिक्त वर्ष बीताने से प्रजनन दर में प्रति कन्या एक जन्म की कमी हुई

में निवेश के रूप में देखा जाता है तथा यह लम्बे समय तक खाने की आदतों तथा पसंदीदा भोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।

व्यक्ति और समाज को तब फायदा होता है जब कन्याएं और महिलाएं बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करती है। शिक्षा महिलाओं के रोजगार के अवसरों को व्यापक बनाती है। साक्षरता कौशल महिलाओं को सामाजिक और कानूनी अधिकारों और कल्याण सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। शिक्षा महिलाओं को कौशल प्रदान करके उनकी राजनीतिक क्षमता को बढ़ाती है जो उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने में सक्षम बनाती है। शिक्षा का निम्न स्तर घरेलू हिंसा का एक मुख्य जोखिम कारक है।

अधिक शिक्षित माताएं अपने बच्चों को बेहतर ढंग से भोजन करा सकती हैं और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकती हैं। महिलाओं की शिक्षा का उसकी पीढ़ी पर सशक्त प्रभाव पड़ता है, जो परिवार की वरियताओं और सामाजिक मानदण्डों को बदल देता है। नाइजीरिया में स्कूल में चार अतिरिक्त वर्ष बीताने से प्रजनन दर में प्रति कन्या एक जन्म की कमी हुई। अल्पावधि शिक्षा से छोटे बच्चों की माताओं पर स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से काफी प्रभाव पड़ सकता है। लक्षित अनौपचारिक शिक्षा महिलाओं को बच्चे को जन्म देने की योजना बनाने में कारगर भूमिका निभा सकती है।

शिक्षा मातृ मृत्यु दर को कम कर सकती है। महिला शिक्षा को शून्य से 1 वर्ष तक बढ़ाने से प्रति 1,00,000 जन्म दर 174 माताओं की मृत्यु को रोक सकती है।

चित्र 3

अधिकांश देशों में, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा प्राप्त महिलाओं के पतियों द्वारा हिंसा किए जाने की सूचना देने की संभावना कम होती है।

चयनित देशों की विवाहित महिलाएं, जिन्होंने अपने पतियों या जीवन-साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है, का प्रतिशत

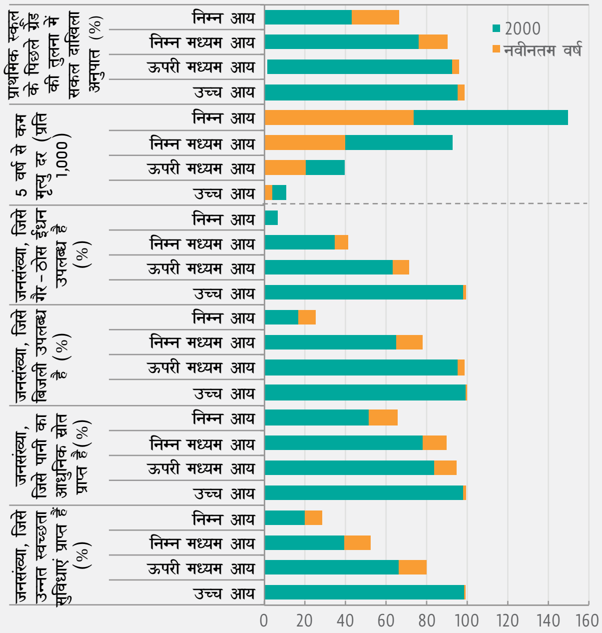

टिप्पणियां: गैर-ठोस ईंधनों और बिजली की उपलब्धता के लिए 'नवीनतम वर्ष' 2012 है, प्राथमिक शिक्षा के अंतिम ग्रेड की तुलना में सकल दाखिला अनुपात के लिए 2014, तथा 5 वर्ष से कम मृत्यु दर और पानी एवं स्वच्छता सुविधाओं के लिए 2015 है।
स्रोत: यूआईएस डेटाबेस तथा विश्व बैंक (2016)

सामाजिक विकास शिक्षा को प्रभावित करता है

जिस प्रकार शिक्षा का सामाजिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार सामाजिक विकास शिक्षा पर सकारात्मक और जहां समग्र और संपूर्ण न हो – नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। शिक्षा प्रणाली के लिए स्वास्थ्य और पोषण मुख्य आधार होते हैं; वे बच्चों को स्कूल जाने और सीखने की योग्यता प्रदान करते हैं, जो उनके परिवार की उन्हें सहायता देने की क्षमता के अधीन होते हैं। केन्या में, जिन कन्याओं ने कृमिनाशी उपचार प्राप्त किया था, उनमें राष्ट्रीय प्राथमिक स्कूल निकास परीक्षा उत्तीर्ण करने की संभावना 25% अधिक थी। शुरुआती बाल्यावस्था में रहने की स्थितियां शिक्षा का आधार उपलब्ध कराती हैं। शिक्षकों के लिए उत्तम स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध होने से शिक्षकों के गैर-हाजिर रहने और स्कूल छोड़ने की दर कम होती है।

जल, स्वच्छता, साफ-सफाई और ऊर्जा का शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घाना में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कन्याओं में पानी लाने के समय के घटने से स्कूल में उपस्थिति बढ़ी थी। ग्रामीण पेरु में, परिवारों में बिजली के 1993 के 7.7% से बढ़कर 2013 में 70% घरों तक पहुंचने से बच्चों के पढ़ने का समय एक दिन में 93 मिनट बढ़ गया।

एकीकृत सामाजिक और शिक्षा कार्यकलापों की आवश्यकता है।

शिक्षा में स्त्री-पुरुष समानता में हुई प्रगति से स्त्री-पुरुष समानता में एक-समान सुधार नहीं किया है। उदाहरण के लिए, एशियाई देशों जैसे जापान और कोरिया गणराज्य, जहां महिलाओं की शिक्षा बढ़ी है, कार्यबल के उम्रदराज होने के कारण शिक्षित श्रम की मांग के बावजूद महिला मजदूर बल भागीदारी सीमित बनी हुई है। इसी प्रकार, केवल शिक्षा गतिविधियों से स्थायी स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में परिवर्तन लाना संभव नहीं है।

ये पैटर्न व्यापक गतिविधियों और नीतियों की आवश्यकता को कम करते हैं जो शिक्षा को कानूनी परिवर्तन या कार्यबल नीतियों जैसी कार्रवाई से जोड़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जैसे पेंशन, नकद अंतरण और माइक्रो फाइनेंस - जिनसे जोखिम और अस्थिरता कम करने की अपेक्षा की जाती है, का अनेक क्षेत्रों में गरीबी को कम करने से लेकर शिक्षा की उपलब्धता में सुधार करने तक व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, परिवार अनुकूल नीतियां और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने में छूट महिला श्रमबल को निरंतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

पुरुष और महिला को एक साथ लाने वाले कार्यक्रम स्त्री-पुरुष में व्याप्त व्यापक भेदभाव को कम करने में कारगर हो सकते हैं। ब्राजील में, कार्यक्रम एच में समूह शिक्षा सत्र, युवाओं द्वारा चलाए जाने वाले अभियान तथा युवाओं में स्त्री-पुरुष के पुराने तौर-तरीकों को बदलना शामिल है; इसे 20 से अधिक देशों द्वारा अपनाया गया है।

द्वितीय वर्ष प्रसूति विद्या की छात्रा सेलिना अखतर मां की भूमिका निभाते हुए, जहां छात्राएं बांग्लादेश में दीनाजपुर नर्सिंग संस्थान में प्रसव के बाद देखभाल प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले रही हैं।

सौजन्य: निकोलस एक्सेलरोड/रूओम

शांति

विवाद या संघर्ष शिक्षा को नष्ट कर देता है। स्कूलों, छात्रों और अध्यापकों पर हमला किया जा रहा है और उन्हें विस्थापित किया जा रहा है।
लेकिन विवाद या संघर्ष शिक्षा को और महत्वपूर्ण बना देता है।
स्कूल उन बच्चों और परिवारों के लिए सुरक्षित स्थल हो सकते हैं जिन्हें उनके घरों से मजबूरन विस्थापित किया जाता है।
जब हम शिक्षित हो जाते हैं, तो हमारे द्वारा मतदान करने, और बंदूक की बजाय शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने की संभावना अधिक रहती है।
हम शांति चाहते हैं!
हम लोकतंत्र चाहते हैं!
और यदि हम दस्तावेज नहीं पढ़ सकते और अपने कानूनी अधिकारों को नहीं समझ सकते, तो हम न्याय प्रणाली से कैसे पार पाएंगे?
सही प्रकार की शिक्षा सशक्त निवारक माध्यम है, भले ही इसका सरकारी शांति समझौतों में उल्लेख न किया जाए।

शांति : राजनीतिक भागीदारी, शांति और न्याय की उपलब्धता

निरंतर हिंसा और सशस्त्र संघर्ष के कारण व्यक्तिगत सुरक्षा और जन कल्याण प्रभावित होता है। हिंसा रोकना तथा स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र तथा प्रतिनिधि संस्थानों तथा बेहतर न्याय प्रणालियों की स्थापना करना आवश्यक होता है। शिक्षा राजनैतिक भागीदारी, समग्रता, परामर्श देने और लोकतंत्र में अहम पहलू होती है। हालांकि शिक्षा संघर्ष का कारण बन सकती है, यह इसे कम या समाप्त भी कर सकती है। शिक्षा शांति कायम रखने तथा इसकी उपेक्षा किए जाने के खतरनाक परिणामों का समाधान करने में मदद कर सकती है। नागरिक समाज संगठनों द्वारा विशेष रूप से किए गए शिक्षा प्रयास उपेक्षित जनसंख्या को न्याय दिलाने में मदद कर सकते हैं।

शिक्षा और साक्षरता राजनीति को अधिक भागीदारीपूर्ण बनाती है

शिक्षा प्रमुख राजनैतिक नेताओं तथा राजनैतिक प्रणाली की कार्यशैली के बारे में जानकारी बढ़ाती है। व्यक्तियों को मतदान करने, दावों को समझने और चुनाव परिणामों में रुचि लेने के लिए जानकारी तथा कौशल की आवश्यकता होती है। पश्चिमी केन्या में, राजनैतिक रूप से उपेक्षित जातीय समूह की लड़कियों को लक्षित करते हुए एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के कारण माध्यमिक स्कूल में उनकी भागीदारी और राजनैतिक जानकारी बढ़ गई। पाकिस्तान में, 2008 के चुनाव से पूर्व मतदाता जागरूकता अभियान के कारण महिलाओं के मतदान में 12% की वृद्धि हुई। नाइजीरिया में, 2007 के चुनावों से पूर्व एक हिंसा-रोधी अभियान ने मतभेदों को कम कर दिया, जिससे मतदाताओं द्वारा 10% अधिक मतदान किया गया।

बेहतर शिक्षा लोगों को अधिक सोच-विचार करने और राजनैतिक रूप से सक्रिय व्यवहार करने में भी मदद करती है, और इससे उपेक्षित समूहों का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। छात्रों के नागरिक शिक्षा प्राप्त करने से राजनीति में अधिक रुचि लेने की संभावना होती है तथा एक खुला शिक्षा परिवेश विवादास्पद विषयों पर चर्चा का समर्थन करता है तथा छात्रों को विभिन्न विकल्पों को चुनने और व्यक्त करने की अनुमति देता है। 35 देशों का अध्ययन करने पर पता चला है कि कक्षाओं में खुलेपन से राजनीति में भागीदारी की मंशा में वृद्धि होती है। इस्राइल और इटली में, एक खुले लोकतांत्रिक कक्षा माहौल ने छात्रों को अधिक सभ्य और राजनीति में सक्रिय भूमिका प्रदान करने में मदद की है।

बेहतर शिक्षा तथा राष्ट्रीय और स्थानीय निर्णय लेने वाले निकायों के बीच महिलाओं की भागीदारी का गहरा संबंध है। राजनीति सार्वजनिक कार्यालय में महिलाओं के व्यापक प्रतिनिधित्व से उन्हें सकारात्मक भूमिका प्रदान करके और उनकी शैक्षणिक आकांक्षाओं को बढ़ाकर शिक्षा में स्त्री-पुरुष भेदभाव को कम किया जा सकता है। भारत के 16 बड़े राज्यों में जिला राजनीति में महिलाओं की संख्या 10% तक बढ़ाने से प्राथमिक स्कूल शिक्षा अभियान में लगभग 6% की वृद्धि होगी, जिनका लड़कियों की शिक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

> “1870 से 2000 के बीच उच्च साक्षरता स्तर वाली आधी आबादी ने लोकतंत्र को चुना था”

शिक्षा से इस बात की अधिक संभावना होती है कि असंतुष्ट नागरिक अपनी समस्याओं को गैर-हिंसक नागरिक आंदोलन जैसे विरोध, बहिष्कार, हड़ताल, रैलियों, राजनैतिक प्रदर्शनों, सामाजिक असहयोग और विरोध के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। 55 वर्षों में 106 देशों में उच्च शिक्षा वाले जातीय समूहों द्वारा गैर-हिंसक विरोध में शामिल रहने की संभावना अधिक थी।

उच्च शिक्षा की व्यापक और एक-समान उपलब्धता लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थानों को बनाए रखने में मदद करती है। 1870 से 2000 के बीच उच्च साक्षरता स्तर वाली आधी आबादी ने लोकतंत्र को चुना था।

शिक्षा और संघर्षः एक जटिल संबंध

अच्छी शिक्षा के अभाव में गरीबी, बेरोजगारी और निराशा सशस्त्र नागरिक सेनाओं के लिए भर्ती एजेंटों के रूप में कार्य कर सकती है। सियरा लिओन में, अशिक्षित युवाओं के माध्यमिक शिक्षा की तुलना में विरोधी गुटों में शामिल होने की कम से कम नौ गुणा संभावना अधिक थी। शिक्षा में असमानता इस समस्या को और गंभीर कर देती है। पिछले 50 वर्षों में 100 देशों से प्राप्त आंकड़ों में पाया गया कि शिक्षा में अत्यधिक अंतर होने वाले देशों के विवाद में पड़ने की ज्यादा संभावना थी। फिर भी उच्च शिक्षा होना नुकसानदायक नहीं हैः जब शिक्षा स्तर उठता है लेकिन श्रम बाजार स्थिर रहता है तो बेचैनी गुस्से में फट सकती है।

> "पिछले 50 वर्षों में 100 देशों से प्राप्त आंकड़ों में पाया गया कि शिक्षा में अत्यधिक अंतर होने वाले देशों के विवाद में पड़ने की ज्यादा संभावना थीं"

जो स्कूल पक्षपात सिखाते हैं, वहां असहिष्णुता और ऐतिहासिक विकृति हिंसा के पनपने हेतु जमीन तैयार हो सकती है। कई देशों में कार्यक्रमों तथा शिक्षा सामग्रियों को घिसी-पिटी और निरर्थक राजनैतिक और सामाजिक शिकायतों के रूप में दर्शाया जाता है। रवांडा में, 1962-1994 की तुलना में शिक्षा नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा से पता चला कि हुतु और तुतसी को विशिष्ट समूहों में बांटने और पृथक करने के लिए वर्गीकृत और कलंकित किया गया। शिक्षा में भाषा भी शिकायतों के बढ़ने का मूल कारण हो सकती है।

सशस्त्र सेना संघर्ष शिक्षा में विकास की एक सबसे बड़ी बाधा है। संघर्ष प्रभावित देशों में 21.5 मिलियन प्राथमिक स्कूल के बच्चों (कुल का 35%) तथा निम्न माध्यमिक के लगभग 15 मिलियन किशोर (25%) स्कूल छोड़ देते हैं। सीरिया अरब गणराज्य में, लगभग 5 लाख बच्चे 2013 में प्राथमिक स्कूल छोड़ गए थे। स्कूलों का प्रयोग प्रायः सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। शिक्षक जोखिम में पढ़ाते हैं: कोलंबिया में 2009 से 2013 के बीच 140 शिक्षक मारे गए। सशस्त्र सेना समूहों में बच्चों को व्यापक रूप से जबरदस्ती भर्ती किया जाता है।

चित्र 4:

शरणार्थी बच्चों की शिक्षा स्थितियां काफी भिन्न होती हैं

प्राथमिक और माध्यमिक दाखिला दरें, चयनित देशों में चुनिंदा शरणार्थी स्थल, 2014

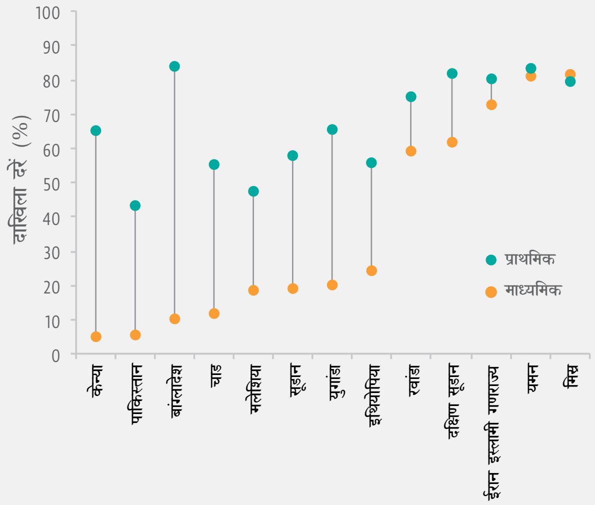

स्रोत: 2014 यूएनएचसीआर आंकड़ों पर आधारित जीईएम रिपोर्ट दल विश्लेषण (2016)

शरणार्थी शिक्षा प्रणालियों के लिए व्यापक चुनौती प्रस्तुत करते हैं। शरणार्थी बच्चों और किशोरों के गैर-शरणार्थी बच्चों की तुलना में स्कूल छोड़ने की संभावना पांच गुना अधिक होती है। कुछ शरणार्थी स्थलों में बच्चों/शिक्षक की दर काफी अधिक 70%1 होती है और कई शिक्षक अयोग्य होते हैं।

शिक्षा जातीय तथा धार्मिक समूहों में मतभेदों को निपटाने में मदद कर सकती है। लेकिन जहां स्कूली पाठ्यक्रमों और स्कूल को पृथक करके यथास्थिति बनाए रखते हैं, वहां वे भेदभाव के बीज बोते हैं। बोसनिया और हेरजेगोबिना में स्कूलों को 1996 में युद्ध के समाप्त होने के बाद जातीय और भाषायी आधार पर पृथक किया गया है। संघर्ष के बाद, पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु अंतर समूह संबंध बनाने में मदद या हानि पहुंचा सकती है। किसी पाठ्यक्रम में सुधार की सफलता प्रेरणादायी, तैनात और प्रशिक्षित अध्यापकों पर निर्भर करती है।

सुव्यवस्थित औपचारिक और अनौपचारिक शांति शिक्षा छात्रों का गुस्सा, हठधर्मिता और हिंसक संघर्ष में भाग लेने को कम कर सकती है। शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम रखने के एजेंडे से जोड़े जाने की आवश्यकता है, लेकिन सुरक्षा मुद्दों को इसकी तुलना में प्राथमिकता देनी होगी। 1989 से 2005 के बीच हस्ताक्षरित 37 सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पूर्ण शांति करारों में से, 11 में शिक्षा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

शिक्षा कार्यात्मक न्याय प्रणाली का निर्माण करने में अहम भूमिका निभा सकती है

शांतिपूर्ण समाज को बनाए रखने के लिए एक कार्यात्मक न्याय प्रणाली महत्वपूर्ण है। फिर भी, कई नागरिकों में जटिल न्याय प्रणाली का लाभ उठाने का कौशल नहीं होता। वर्ष 2011 में भूतपूर्व यूगोस्लाव मैसेडोनिया गणराज्य में न्यायालय प्रयोक्ता सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार 77% उच्चतर शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की तुलना में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त केवल 32% व्यक्तियों को न्यायिक प्रणाली और इसके सुधारों के बारे में उच्च शिक्षा वाले व्यक्तियों की तुलना में अच्छी या आंशिक जानकारी थी। समुदाय आधारित शिक्षा कार्यक्रम विशेषकर उपेक्षित कानूनी अधिकारों की समझ बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

न्यायिक और कानून लागू करने वाले अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना महत्वपूर्ण होता है। अपर्याप्त प्रशिक्षण और क्षमता का न होना न्याय नहीं दिला सकता तथा इससे विलंब और कानूनों का उल्लंघन होगा या साक्ष्य पर्याप्त रूप से नहीं जुटेंगे, प्रवर्तन का अभाव तथा कुप्रथा हो सकती है। हैती में देश की पुलिस ने सात माह के संयुक्त राष्ट्र भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए पांच वर्षों में सर्वाधिक विश्वसनीय सार्वजनिक संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

बोको हरम द्वारा वर्ष 2010 और 2013 के बीच किए गए हमलों में येरवा प्राथमिक स्कूल, मैदुगुरी, बोरनो राज्य में कक्षा की क्षतिग्रस्त खिड़की से झांकते बच्चे। पूर्वोत्तर नाइजीरिया में वर्ष 1915 में स्थापित यह स्कूल पहला प्राथमिक स्कूल था।

सौजन्य: बेडे शेप्पर्ड/ह्यूमन राइट्स वॉच

स्थान

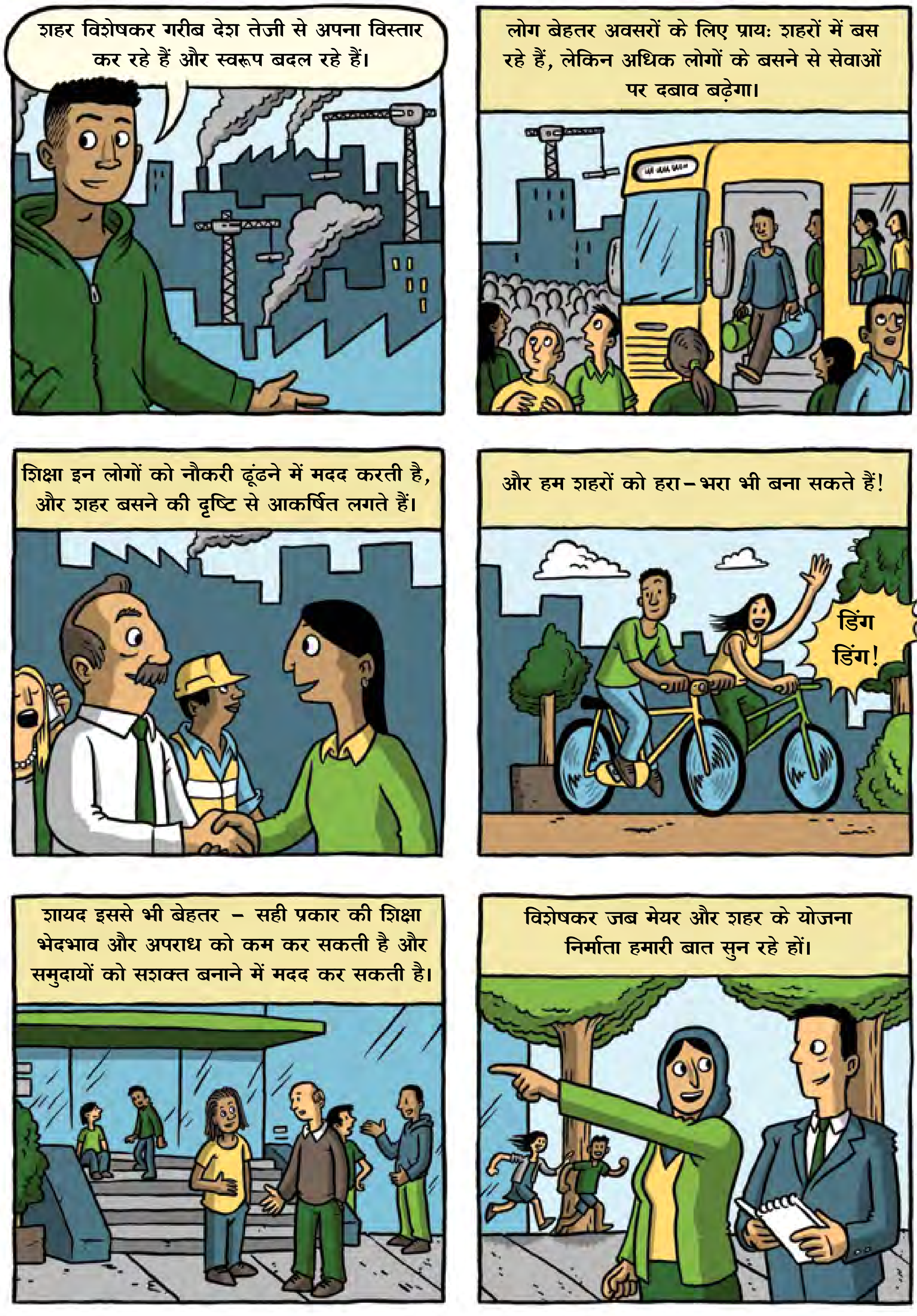

@GEMReport #SDG4All bitly.com/sdg4all

स्थान: नगर और मानव बसावटें

शहरीकरण आज के परिभाषित जनसंख्या अध्ययन के रुझानों में से एक है – नगरों और शहरी क्षेत्रों में लगभग आधी आबादी बसती है, और 2050 तक सबसे अधिक शहरी आबादी में वृद्धि निम्न आय वाले शहरों में होगी। जीईएम रिपोर्ट में नगरों और शहरीकरण से शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव और शिक्षा शहरी मुद्दों को कैसे प्रभावित करती है, को दर्शाया गया है।

शहरी बदलाव जिस मात्रा और तेजी से हो रहा है, उसके लिए सुशासन, लचीला दृष्टिकोण और नयापन आवश्यक है। शिक्षा को शहरी आयोजना में इस प्रकार से शामिल किया जाना चाहिए ताकि सभी की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं और अधिकारों को शहरी जनसंख्या परिवर्तन के रूप में पूरा किया जा सके। लेकिन प्रमुख शहरी विकास चर्चाओं में व्यापक शिक्षा क्षेत्र को शामिल नहीं किया जा रहा है। यदि शिक्षा को भावी नगरों पर होने वाली चर्चा में अपना स्थान प्राप्त करना है तो शिक्षा के हितधारकों और शहरी नेताओं को व्यापक विचार-विमर्श और नेतृत्व की आवश्यकता होगी।

शिक्षा योजना को नगर प्रभावित करते हैं

विश्व स्तर पर लगभग आधा शहरी विकास स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा आधा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करने के कारण हुआ है। ऐसे विकास से बुनियादी शिक्षा, आजीवन अध्ययन, कौशल विकास और शिक्षकों की मांग बढ़ती है, और साथ ही मलिन बस्तियों, प्रवासियों और शरणार्थियों सहित शिक्षा के जरिए सामाजिक एकजुटता और सहिष्णुता को पोषित करने की आवश्यकता बढ़ती है।

निम्न आय वाले देशों में शहरी बसावट का एक-तिहाई से अधिक नगरों के बीचोंबीच या शहरी बसावट के आसपास बसता है। मलिन बस्तियों में शिक्षा सहित बुनियादी सेवाओं की गरीबों को उपलब्धता नहीं होती। यूगांडा के 12 नगरों और शहरों से 130 मलिन बसावटों से एकत्रित आंकड़ों से पता चलता है कि हालांकि अधिकांश बसावटों में स्कूल मौजूद थे, फिर भी शिक्षा प्राप्त करने वालों ने पब्लिक स्कूलों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिया।

> “2014 के अंत तक 10 में से 6 शरणार्थी शहरी क्षेत्रों में रहते थे। विश्व में आधे से अधिक शरणार्थी 18 वर्ष से कम आयु के हैं”

रोजगार की तलाश में नगरों में पलायन करने वाले लोगों को भेदभाव, भाषा समस्या, बेरोजगारी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में शोषण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे निपटने के लिए कौशल विकास पर ध्यान देने की जरूरत है।

शहरी शिक्षा प्रणाली को मजबूरन विस्थापित बच्चों और युवाओं के लिए लम्बे समय तक उनके एकीकरण के लिए सहायता का रास्ता अपनाना होगा – विशेषकर जब विश्व में शरणार्थियों का संकट गहराता जा रहा है। 2014 के अंत तक 10 में से 6 शरणार्थी शहरी क्षेत्रों में रहते थे। विश्व में आधे से अधिक शरणार्थी 18 वर्ष से कम आयु के हैं। तुर्की में शिविरों में रहने वाले 85% सीरियाई शरणार्थी बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसकी तुलना में शहरी क्षेत्रों में 30% ही स्कूल जाते हैं।

सार्वजनिक शिक्षा की चर्चाओं में प्राय: निजी स्कूलों, विशेषकर बड़े नगरों और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों की व्याप्तता को कम आंका जाता है या महत्व नहीं दिया जाता। अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में उनका विकास मुख्यत: अनौपचारिक होता है, प्राय: इसे सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं किया जाता, और इसकी पूरी तरह से उपेक्षा की जाती है। 2010-11 में लागोस राज्य, नाइजीरिया के प्राइवेट स्कूल की जनगणना में पता चला कि लगभग 85% प्राथमिक-पूर्व और 60% प्राथमिक छात्रों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिला हुआ था।

शिक्षा का नगरों पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है. . .

ज्ञान अर्थव्यवस्था में नयापन लाने और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च दाखिला दर बुनियादी आवश्यकता होती है। शहर मानव पूंजी और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को उच्च शिक्षा, कौशल, प्रतिभा, ज्ञान और अभिनवता के वैश्विक केन्द्र के रूप में प्रस्तुत करके आकर्षित करते हैं। शंघाई, चीन जैसे विशाल नगर व्यापक स्तर पर योग्यता को आकर्षित करते हैं, जहां 1,00,000 स्नातक हैं और यहां एक दशक में कॉलेज में शिक्षित श्रमबल का अनुपात दुगुना हो गया है। स्टैनफोड विश्वविद्यालय पर पर्याप्त वैश्विक प्रभाव पड़ा है: इसके छात्रों द्वारा बनाई गई 18,000 फर्में उनके गृह राज्य कैलेफोर्निया में स्थित हैं।

निम्न आय वाले देशों में अनौपचारिक कार्य रोजगार और आय का एक प्रमुख स्रोत है, विशेषकर शहरों में, तथा आर्थिक संकट के दौरान उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त नियोक्ता महत्वपूर्ण होता है। शहरी अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक कार्य समृद्ध नगरों तथा सामाजिक समग्रता के लिए महत्वपूर्ण होता है।

शिक्षा का विशेषकर अपराध को कम करने में भी महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव पड़ता है। इंग्लैण्ड और वेल्स (यूनाइटेड किंगडम) में अनिवार्य लम्बी स्कूली शिक्षा से अपराध और हिंसा में व्यापक कमी आई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरुआती बाल शिक्षा का बाल्यावस्था में अपराध को कम करने का दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा था।

शिक्षा नगरों में पर्यावरणीय चुनौतियां और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता में सुधार ला सकती है। शिक्षा के साधनों ने जनता द्वारा बस रेपिड ट्रांजिट और साइकलिंग को अपनाने में अहम भूमिका निभाई है। लागोस, नाइजीरिया में एक नए बस रेपिड ट्रांजिट पर चलाए गए गहन संचार कार्यक्रम ने कार्यान्वयन में होने वाले विलंब को कम करने में मदद की। साइकिल वाले शहरों जैसे डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैण्ड में शिक्षा एक समन्वित दृष्टिकोण है तथा बच्चों को शुरु से ही गहन प्रशिक्षण दिया जाता है।

. . . लेकिन यह शहरी असमानता भी पैदा करता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षा का सामाजिक स्तर पर विभाजन न हो, सरकारों को शिक्षा संबंधी गतिविधियों में संतुलन लाना होगा ताकि सामाजिक समावेश और शहर में शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जा सके।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में शिक्षा में काफी अधिक – यदि ज्यादा नहीं तो – पर्याप्त असमानता है। असमानता को दूर करने की नीति के अभाव के कारण यह शहरी क्षेत्रों में रहने के संभावित लाभ को कम कर सकता है। भेदभावपूर्ण नीतियां और पद्धतियां, जैसे अच्छे अध्यापकों का असमान वितरण भी असमानता पैदा करता है। चिले के कंसेपशन मेटोपोलिटन क्षेत्र में, अच्छी गुणवत्ता वाले स्कूलों में शिक्षकों के वितरण में प्रमुख अंतर पाया गया।

चित्र 5:

विकासशील देशों में ग्रामीण–शहरी असमानता है लेकिन साथ ही काफी अधिक आंतरिक–शहरी असमानता भी है।

निम्न माध्यमिक शिक्षा पूर्णता दरों में स्थान (ग्रामीण–शहरी) और संपत्ति (निचले और शीर्ष स्तर पर) पर आधारित असमानता

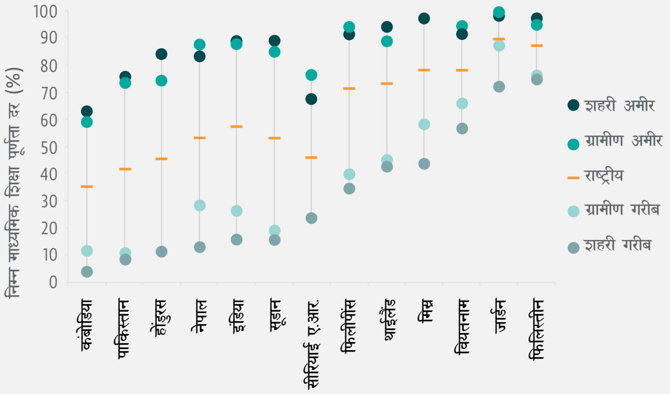

स्रोत: जीईएम रिपोर्ट दल विश्लेषण जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सर्वेक्षणों, बहु संकेतक समूह सर्वेक्षणों और राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित है।

प्राइवेट स्कूल, जो प्राय: खराब सरकारी व्यवस्था के कारण अस्तित्व में आते हैं, असमानता को बढ़ा सकते हैं। स्कूलों का विकल्प होने से माता–पिता पब्लिक, प्राइवेट, चार्टर या अन्य गैर–राज्य संस्थानों के बीच चयन कर सकते हैं – जो प्राय: जनसंख्या की स्थिरता का कारण और प्रभाव दोनों बन सकते हैं।

शिक्षा में असमानता नकारात्मक प्रवृत्ति से पैदा हो सकती है। शिक्षक प्राय: प्रवासी और अल्पसंख्यक बच्चों के प्रति भेदभाव का रवैया अपनाते हैं जो उनकी सामाजिक उपेक्षा का कारण बन सकता है। शंघाई में, पहली कक्षा के शिक्षकों द्वारा यह रिपोर्ट करने की संभावना है कि प्रवासी बच्चों की पृष्ठभूमि विशेषताओं पर नियंत्रण के बावजूद भाषा में उनके ग्रेड का स्तर काफी कम था। यदि स्कूल उपेक्षित बच्चों के प्रति हिंसक हो जाएं तो शिक्षा सामाजिक बहिष्कार का कारण भी बन सकती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका, अधिकांश यूरोप तथा नसली जातियों जैसे दक्षिण अफ्रीका के शहरों में शिक्षा जातीय, सामाजिक वर्ग या नसल को पृथक करने का एक प्रमुख पहलू है। शिक्षा आधारित पृथकता उच्च प्रौद्योगिक ज्ञान आधारित महानगरों में अधिक होती है। 30 सबसे बड़े अमेरिकी महानगरों में, ऊपरी और निम्न आय वाले परिवारों के बीच पृथकता बढ़ी है। 13 प्रमुख यूरोपीय नगरों में हुए शोध से पता चलता है कि सामाजिक–आर्थिक और स्थानिक पृथकता बढ़ रही है क्योंकि और अधिक शिक्षित जनसंख्या ज्ञान आधारित विशिष्ट उद्योगों का विकास करती है।

शिक्षा और आजीवन शिक्षा शहरी योजना को प्रभावित कर सकती है तथा नगरों को बदलने में मदद कर सकती है।

यदि संगठित प्रयास किए जाएं तो शिक्षा में शहरी योजना को प्रभावित करने की क्षमता होती है। बर्लिन में कार्यकलापों, शिक्षा और रोजगार अवसरों के जरिए 'सामाजिक रूप से एकीकृत नगर' का सृजन करने के लिए पड़ोस प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

> "भारत में प्रत्येक 100,000 शहरी निवासियों के लिए लगभग 1 नियोजक है, जिसकी तुलना में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक 5000 के लिए 1 नियोजक है"

इस क्षमता को पहचानने के लिए बेहतर बहुआयामी प्रशिक्षण की जरूरत होती है ताकि अनुशासन के साथ प्रभावी ढंग से कार्य किया जा सके तथा क्षेत्रों द्वारा अधिक स्थायी जीवन परिवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। अधिकांश देशों में, शहरी आयोजना स्कूल तथा कार्यक्रम सीमित हैं। भारत में प्रत्येक 1,00,000 शहरी निवासियों के लिए लगभग 1 नियोजक है, जिसकी तुलना में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक 5000 के लिए 1 नियोजक है।

उपेक्षितों की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षा आधारित भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण शहरी योजना तथा निर्णय लेने में सुधार करता है। झोंपड़ी / मलिन बस्ती अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ने समुदाय के सदस्यों में व्याप्त असमानता को दर्ज करने तथा स्थानीय सरकार से सेवाओं की मांग करने में मदद की है। एसोसिएशन ऑफ अफ्रीकन प्लानिंग स्कूलों की भागीदारी से, विशेषकर अनौपचारिक बसावटों के संबंध में शहरी योजना के महत्व को बढ़ाने के प्रयासों में संलग्न रहा है।

शहरों के जागरूक नेता शिक्षा तथा आजीवन शिक्षा का उपयोग नगरों को बदलने में कर सकते हैं। मेडेलिन, कोलंबिया में महापौर ने दुनिया के सबसे हिंसक नगर को शिक्षा आधारित सामाजिक परिवर्तन नीति के जरिए सबसे अधिक खोज करने वाले शहर में बदलने में मदद की। चूंकि नगर लगातार महत्वपूर्ण बन रहे हैं, अत: स्थानीय स्वायत्तता में सुधार करना, और शिक्षा की कार्यनीतियों पर बल देना उन्हें स्थायी और समग्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है।

रियो डे जैनेईरो में फैवेलास तब अस्तित्व में आया जब बड़ी संख्या में लोगों ने ब्राजीलियन देहात से शहर की ओर पलायन किया।

सौजन्य: अन्ना स्पाईस्ज/जीईएम रिपोर्ट

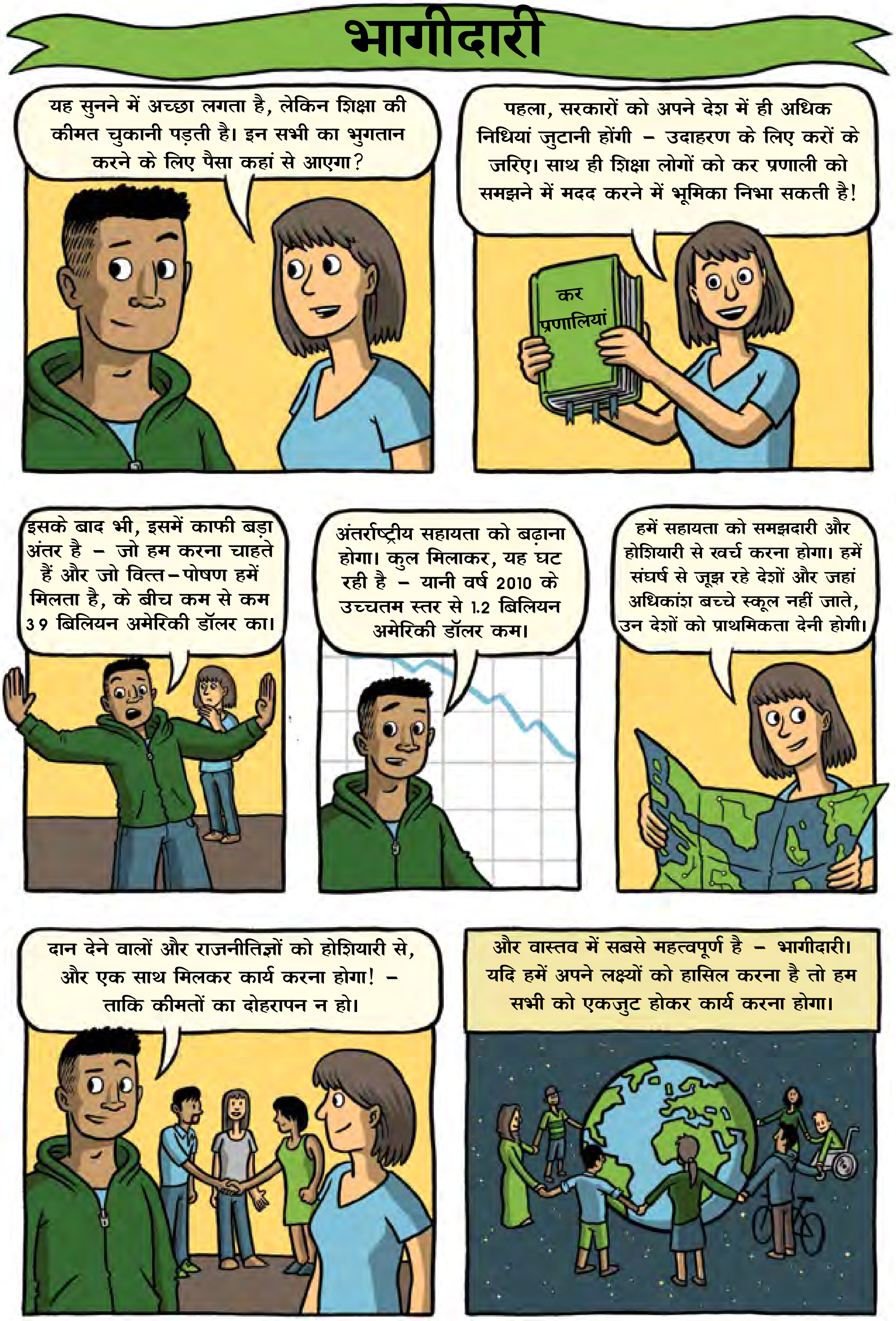

@GEMReport #SDG4All bitly.com/sdg4all

भागीदारी: एसडीजी 4 तथा अन्य एसडीजी प्राप्त करने के लिए स्थितियां अनुकूल बनाना

2030 के एजेंडा में आज की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को पृथक नहीं किया जा सकता, जिनके लिए एकीकृत प्रयासों की जरूरत है। एसडीजी 17 में एसडीजी प्राप्त करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और इसके लिए विश्व स्तरीय भागीदारी को फिर से बनाना होगा। इसके लक्ष्यों में सहयोग की आवश्यकता को उजागर किया गया है ताकि पर्याप्त वित्त-पोषण सुनिश्चित किया जा सके, नीतिगत संबद्धता बढ़ाई जा सके और अन्य लक्ष्यों में बहु हितधारक भागीदारी को बनाया जा सके।

वित्त

जीईएम रिपोर्ट दल ने यह अनुमान लगाया है कि न्यून और मध्यम वर्गीय आय वाले देशों में प्रत्येक बच्चे और किशोर को प्राथमिक-पूर्व शिक्षा से ऊपरी माध्यमिक स्तर तक अच्छी शिक्षा दिलाना सुनिश्चित करने के लिए कुल वार्षिक लागत 149 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक 340 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। जुलाई 2015 में विकास के लिए शिक्षा पर ओसलो शिखर सम्मेलन में घोषित वैश्विक शिक्षा अवसरों के वित्त-पोषण पर एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा वित्त-पोषण की कमी का समाधान करने के उपायों का पता लगाया जाएगा।

शिक्षा 2030 कार्य फ्रेमवर्क ने शिक्षा के लिए घरेलू वित्त-पोषण पर दो बैंचमार्क निर्धारित किए हैं: जीडीपी का 4% से 6% तथा सार्वजनिक व्यय का 15% से 20% । इसके लिए और अधिक घरेलू संसाधनों को जुटाना महत्वपूर्ण होगा। सभी कम आय वाले लगभग आधे देशों में कर अनुपात जीडीपी के 15% से कम है, जिसकी तुलना में उभरती अर्थव्यवस्था में यह 18% तथा अग्रिम अर्थव्यवस्था में यह 26% है। गरीब देशों में कर अनुपात बढ़ाने के लिए घरेलू और वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता होती है। शिक्षा कर अदा करने वाले की सोच में बदलाव ला सकती है तथा इसका अनुपालन बढ़ा सकती है। वर्ष 1996 से 2010 तक के आंकड़ों का अध्ययन करने पर पता चला कि 123 देशों में कर राजस्व की कम दर, कम साक्षरता से जुड़ी थी। जिन लोगों ने कर का भुगतान नहीं किया था, वे प्राय: उच्च शिक्षा प्राप्त थे, लेकिन शिक्षा सकारात्मक कर संबंधी व्यवहार से जुड़ी होती है। लेटिन अमेरिका में, नौ देशों ने शिक्षा मंत्रालयों और कर प्राधिकारियों के बीच संयुक्त प्रयासों के जरिए अपने पाठ्यक्रम में कर शिक्षा को शामिल किया है।

> “बहु-राष्ट्रीय कर न देने से निम्न आय वाले देशों को वर्ष में लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि होती है”

कर बचाने और उसे न देने से निपटना एक वैश्विक जिम्मेदारी है। हाल के अनुमानों से पता चला है कि दूसरे देशों में निवेश करके बहु-राष्ट्रीय कर बचाने से निम्न आय वाले देशों को वर्ष में लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि होती है। कर प्रोत्साहन पर समन्वित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई, संधियों और अहितकारी कॉर्पोरेट निर्णय लेना कम आय वाले देशों के लिए आवश्यक होता है ताकि खोई हुई राजस्व हानि को फिर से प्राप्त किया जा सके।

कई देश शिक्षा के हित में व्यय को फिर से आवंटित कर सकते हैं। शिक्षा के खर्च को प्राथमिकता देने के दो तरीके हैं कि जीवाश्म ईंधन पर राजसहायता को हटाया जाए और शिक्षा निधियां निर्धारित की जाएं। इंडोनेशिया में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय मुख्यत: ईंधन राजसहायता सुधार के कारण 2005 से 2009 के बीच 60% तक बढ़ गया।

हालांकि राजस्व एकत्र करने में सुधार हुआ है, फिर भी, लगभग 39 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय अंतर बना हुआ है। कई कम आय वाले देशों को सहायता दिया जाना आवश्यक होता है। फिर भी, शिक्षा को सहायता देने की मात्रा 2013 से 2014 के बीच लगभग 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर घट गई। इस संदर्भ में तीन विकल्प उम्मीद जगाते हैं: बहु राष्ट्रीय प्रणाली के जरिए शिक्षा हेतु अधिक निधियां निर्धारित करना, घरेलू संसाधनों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकारियों का निर्माण करने के लिए अधिक सहायता का उपयोग करना; तथा जिन देशों में शिक्षा स्तर को बेहतर ढंग से लक्षित करने की आवश्यकता है, उन्हें सहायता देना। शिक्षा में प्रारंभिक निवेश, शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के पर्याप्त लाभ के बावजूद सुधार की काफी गुंजाइश है तथा वर्ष 2014 में शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता के रूप में केवल 106 मिलियन डॉलर ही मिले थे, जो माध्यमिक शिक्षा के बाद मिलने वाली राशि के 3% से कम है।

नीतिगत संबद्धता

स्थायी विकास की परस्पर-निर्भर चुनौतियों को पूरा करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है। व्यापक एसडीजी एजेंडा के लिए बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। शिक्षा में, बहु क्षेत्रीय गतिविधियों में स्कूल में भोजन तथा स्वास्थ्य, शुरुआती

बाल्यकाल विकास तथा दक्षता और आजीविका प्रशिक्षण शामिल है।

चित्र 6:

बुनियादी शिक्षा की सहायता आवश्यकता से संबंधित नहीं है

प्रति प्राथमिक स्कूल जाने वाले बच्चे को बुनियादी शिक्षा के लिए कुल सहायता (2014) और प्राथमिक शिक्षा पूर्णता दर (2008-2014)

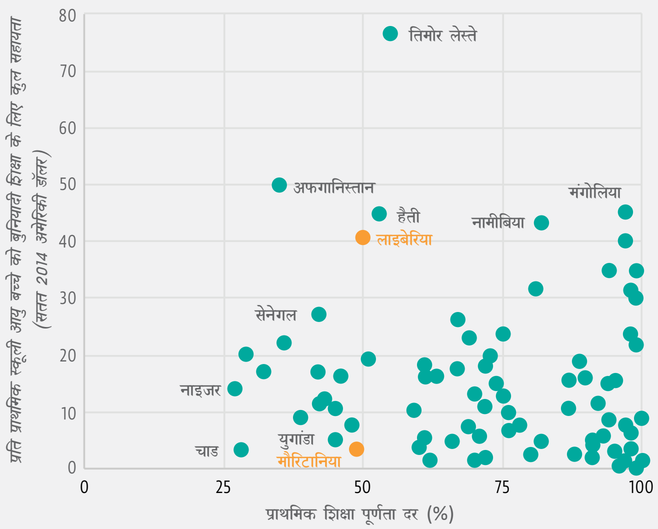

स्रोत: जीईएम रिपोर्ट दल विश्लेषण ओईसीडी क्रेडिटर रिपोर्टिंग प्रणाली आंकड़ों (2016) पर आधारित; शिक्षा पर विश्व असमानता डेटाबेस

राष्ट्रीय स्तर पर बहु क्षेत्रीय योजना में सुधार करने के सफल प्रयास राजनीतिक इच्छा शक्ति, संस्थागत रुपए, पर्याप्त क्षमता तथा पर्याप्त आंकड़ों के महत्व को दर्शाते हैं। नाइजीरिया में, मिलेनियम विकास लक्ष्यों के समर्थन में शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी तथा स्वच्छता में स्थानीय सेवा सुपुर्दगी के लिए ऋण राहत निधियों का उपयोग किया गया। कोलंबिया की राष्ट्रीय विकास योजना में शिक्षा, शांति और इक्विटी राष्ट्रपति की प्राथमिकताओं में है; इसका उद्देश्य 2025 तक लेटिन अमेरिका में सबसे शिक्षित देश बनना है।

सरकारी एजेंसियां अपने संबंधित क्षेत्रों में नीतिगत निर्णय तथा कार्यान्वयन पर विशेष रूप से ध्यान देती हैं, जिससे समन्वय और सहयोग में बाधा पहुंचती है। सुविकसित राष्ट्रीय योजनाएं अच्छी शिक्षा वित्त-पोषण योजनाओं और विकेन्द्रीकृत योजना तथा वित्त-पोषण प्रणालियों से जुड़ी होती हैं और इससे अच्छा विविध क्षेत्र समेकित होता है, जो अधिकांश गरीब देशों में नियम की बजाय अपवाद होता है।

सहायता एजेंसियों को कार्यक्रमों को लागू करने में दो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो एसडीजी की समन्वित योजना आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं; इनमें विकास के प्रति उनके दृष्टिकोण का अभाव होता है, और इनमें बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रमों का समन्वय करने में कठिनाई होती है। देश की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता पूरी तरह से आवंटित नहीं की जा रही है। लाइबेरिया और मॉरिटानिया में लगभग आधे बच्चे प्राथमिक स्कूल शिक्षा पूरा करते हैं, लेकिन लाइबेरिया को प्रति स्कूली बच्चे की बुनियादी शिक्षा के लिए 10 गुणा सहायता राशि प्राप्त होती है।

भागीदारी

स्थानीय और राष्ट्रीय सरकार प्राधिकारी, सिविल सोसायटी, शिक्षा-शास्त्री, वैज्ञानिक समुदाय, निजी क्षेत्र और वैश्विक बहु-शेयरधारक संगठन कुछेक भागीदार हैं जो एसडीजी जैसे वैश्विक एजेंडा को लागू करने में मदद कर सकते हैं। नागरिक सोसायटी की निजी क्षेत्र और बहु-हितधारक भागीदारी वित्त-पोषण, कार्यान्वयन करने और नए एजेंडा की परस्पर जवाबदेही सुनिश्चित करने में पर्याप्त भूमिका है, जिसके राष्ट्रीय सरकारों द्वारा संचालित होने की संभावना है।

सिविल सोसायटी का बढ़ा हुआ कार्यकलाप ईएफए एजेंडा की एक प्रमुख उपलब्धि थी। लेकिन सिविल सोसायटी भागीदारी की अधिक उत्पादकता की दृष्टि से रूपरेखा बनाने में चुनौतियां हैं। दाता वित्त-पोषण पर पूरी तरह निर्भर संगठन स्वतंत्र राय कैसे बनाए रख सकते हैं। सिविल सोसायटी अम्बरेला के अंतर्गत एक अन्य चुनौती असमान तथ्यों का अत्यधिक विविध होना है।

> “एसडीजी एजेंडा की सफलता के लिए समन्वय और वित्त-पोषण निकाय की भूमिका महत्वपूर्ण हैं”

निजी क्षेत्र, एसडीजी में जो गतिशीलता तथा वित्त-पोषण ला सकता है, वह आशावाद के कारण है। हालांकि कुछ लोग वित्त-पोषण, लचीलापन, अभिनवता तथा उन्नत अध्ययन निष्कर्ष के लिए निजी भागीदारी के विकास का स्वागत करते हैं जबकि आशंकित लोग असमानता के बढ़ने और स्कूली शिक्षा में अनुचित बाजार प्रभाव की संभावना देखते हैं।

समन्वय और वित्त-पोषण निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वैश्विक शिक्षा समन्वय प्रणाली में एसडीजी शिक्षा 2030 संचलन समिति, वैश्विक शिक्षा बैठकें, क्षेत्रीय बैठकें तथा सभी के लिए शिक्षा पर एनजीओ का सामूहिक परामर्श शामिल है। संचलन समिति के देशों की सहायता करने, प्रगति की समीक्षा करने और भागीदार कार्यकलापों के समन्वय को प्रोत्साहित करने की आशा है। शिक्षा के लिए वैश्विक भागीदारी, शिक्षा क्षेत्र की प्रधान बहु-शेयरधारक भागीदारी, तपेदिक, एड्स और मलेरिया और गावी के लिए ग्लोबल फंड के रूप में ऐसी स्वास्थ्य क्षेत्र की भागीदारी से सीख ले सकती है, जिससे पर्याप्त निधियां प्राप्त होंगी। नई शिक्षा निधियों का इंतजार नहीं कर सकतीं जिसका उद्देश्य विवाद, प्राकृतिक आपदा और रोग के प्रकोप से प्रभावित लोगों के लिए लक्षित शिक्षा हेतु धनराशि जुटाना है।

अनुमानः शिक्षा विस्तार स्थायी विकास के निष्कर्ष को कैसे प्रभावित करेगा?

2030 और उसके बाद वैश्विक शिक्षा प्राप्ति का अनुमान

2016 जीईएम रिपोर्ट में 2030 तक वैश्विक माध्यमिक शिक्षा के पूरा होने की संभावनाओं का अनुमान लगाया गया है जिसमें वैश्विक रूप से चयनित आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। यह संदेश स्पष्ट है: पिछली दरों पर सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को 2030 तक पूरा करने का ईएफए लक्ष्य पहुंच से परे लगता है। यदि पिछला रुझान जारी रहा तो सार्वभौमिक न्यून माध्यमिक शिक्षा पूरा करने के लक्ष्य को 2059 में प्राप्त किया जाएगा और 2084 में सार्वजनिक ऊपरी माध्यमिक शिक्षा पूरी होगी। कम आय वाले देश सदी के अंत तक लक्ष्य 4.1 को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मुख्य निष्कर्ष यह है कि यदि लक्ष्य 4.1 के प्राप्ति घटक को प्राप्त किया जाना है तो कम और मध्यम आय वाले देशों में एसडीजी परिदृश्य के लिए पिछले रुझानों के अनुसार व्यापक अंतराल पैदा करना होगा।

विकास के परिणामों पर पूर्वानुमान का प्रभाव

हालांकि अनुमान प्रक्रिया सुझाती है कि एमडीजी शिक्षा लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता, यहां तक कि मामूली प्रगति अगली पीढ़ी के लिए एक बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। यह जानने के लिए कि शिक्षा का विस्तार किस तरह अन्य एसडीजी में योगदान दे सकता है, जीईएम रिपोर्ट यह विश्लेषण किया गया है कि शिक्षा किस तरह जीवन बचाने में मदद कर सकती है (शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करके और वयस्क जीवन प्रत्याशा में वृद्धि करके), लोगों और देशों को गरीबी से ऊपर उठा सकती है (कुल राष्ट्रीय आर्थिक विकास में वृद्धि करके और अत्यधिक गरीबी को कम करके) तथा आपदा जोखिम को कम कर सकती है।

यदि बच्चे पैदा करने की उम्र की महिलाएं 2030 तक सार्वभौमिक माध्यमिक स्कूली शिक्षा हासिल कर लेती हैं तो उप-सहारा अफ्रीका में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 2030 तक प्रति 1000 जीवित जन्मों के लिए 68 से घटकर 54 रह जाएगी और 2050 तक प्रति 1000 जीवित जन्मों के लिए 51 से घटकर 38 रह जाएगी । चूंकि समुदाय स्तर के प्रभावों और स्वस्थ प्रथाओं और व्यवहार के प्रसार का बच्चों के स्वास्थ्य को फायदा हो सकता है, अतः बाल मृत्यु दर के इन अनुमानों की तुलना में कहीं अधिक गिरावट आ सकती है।

शिक्षा श्रम उत्पादकता बढ़ाकर और तेजी से तकनीकी विकास करके प्रति व्यक्ति आय बढ़ा सकती है। कम आय वाले देशों में, उच्च माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने से 2050 तक प्रति व्यक्ति आय में 75% तक वृद्धि की जा सकती है। यदि एसडीजी लक्ष्य 4.1 के अनुसार, 2030 तक अत्यधिक गरीबी को दूर करना संभव न हुआ तो गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य 10 साल और आगे बढ़ जाएगा।

चित्र 7:

पिछले रुझानों को देखते हुए निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 2030 तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य भी पूरा नहीं किया सकेगा

शिक्षा स्तर पर और देश के आय समूह द्वारा 15 से 19 वर्ष की आयु में अनुमानित प्राप्ति दर तथा पिछले रुझान, 2010-2080 पर आधारित दो अनुमानों की तुलना

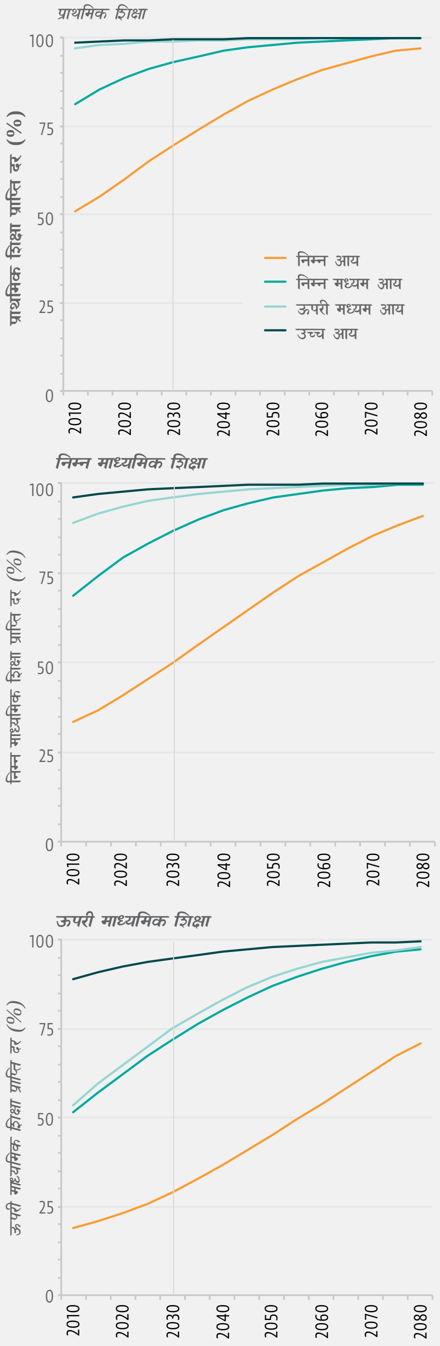

स्रोतः बाराकत (2016)

शिक्षा आपदा से होने वाली मृत्यु को कम करने में मदद कर सकती है, क्योंकि शिक्षित लोग जोखिमों के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, वे इनसे निपटने के लिए अच्छी तरह तैयार रहते हैं और उचित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, और आपदा होने पर उन्हें औसतन कम नुकसान होता है। यदि सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त कर लिया जाता है, तो 2000 से 2010 के बीच 2,50,000 लोगों की मृत्यु की तुलना में आपदा के बार-बार आने के बावजूद 2040-2050 के बीच प्रति दशक आपदा से होने वाली मौतें घटकर 10,000 से 20,000 हो सकती हैं। सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा का एशिया में आपदा से होने वाली मौतों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि यहां काफी अधिक आबादी रहती है और इनमें से अधिकांश नाजुक तटीय इलाकों में रहते हैं।

शिक्षा और स्थिरता – हम क्या जानते हैं और क्या करना चाहते हैं

पिछले अध्याय में शिक्षा और स्थायी विकास के बीच कई संबंध दर्शाए गए हैं। इनसे पता चलता है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरा करना न केवल स्वयं व्यक्तियों के लिए बल्कि उनके परिवारों, समुदायों और कार्यस्थलों के लिए भी लाभदायक होता है। पुरुष और महिलाएं जितने अधिक शिक्षित होंगे, उतने ही अधिक वे पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सजग होंगे, उनकी उत्पादक क्षमता अधिक होगी, वे अधिक आय कमा सकेंगे। इतना ही नहीं वे स्वस्थ जीवन जी सकेंगे, सोच-समझकर कार्य करेंगे और अपने जीवन को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकेंगे। लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करने के अनेक लाभ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं।

चिंताजनक बात यह है कि दुनिया में उभरती नित नई स्थितियों के कारण शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है। उदाहरण के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था ने कुछ के लिए तो अकूत संपत्ति कमाने के अवसर पैदा किए हैं, लेकिन कई लोग ऐसे अवसरों से पिछड़ गए हैं, उनका जीवन और आजीविका इस आर्थिक विषमता के कारण निरंतर गरीबी से प्रभावित हो रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने से राजनीतिक असुरक्षा और संघर्ष तेजी से बढ़ा है, जिससे लाखों लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं। प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापन से सभी युवाओं को सुनिश्चित रूप से कम से कम 12 साल तक शिक्षा प्रदान करने और आजीवन सीखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने के प्रयासों में बाधा पहुंचती है।

> “यदि शिक्षा को नए स्थायी विकास के एजेंडा के अनुसार अपने में बदलाव लाना है तो ‘शिक्षा का वर्तमान स्वरूप’ पर्याप्त नहीं होगा”

यदि शिक्षा को नए स्थायी विकास के एजेंडा के अनुसार अपने में बदलाव लाना है तो ‘शिक्षा का वर्तमान स्वरूप’ पर्याप्त नहीं होगा। शिक्षा से ऐसी सोच विकसित होनी चाहिए जिनसे परस्पर संबंध, एकजुटता, संवेदनशीलता, आशावादिता और व्यवस्था कायम हो। शिक्षा को इस तरह से भूमिका निभानी होगी जिससे समग्रता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, स्वस्थता, कार्बनमुक्त स्थल जैसे स्थिर आयाम स्थापित हों, जो एसडीजी को प्राप्त करने का आधार हैं।

नीचे दी गई नीतिगत सिफारिशें यह सुझाती हैं कि कैसे शिक्षा प्रणाली स्थायी विकास में और अधिक प्रभावी ढंग से योगदान कर सकती है।

- *सभी क्षेत्रों और भागीदारों में सहयोग देना और उन्हें सक्रिय बनाना।* चूंकि व्यवस्थाओं से संबंधित समस्याओं के लिए अनेक तथ्यों और विभिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, इसलिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर मंत्रालयों, शिक्षा विशेषज्ञों, और नागरिक समाज सहित सभी भागीदारों को शामिल करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है।
- *सरकारों को विविध क्षेत्रों की समस्याओं से निपटने के अपने प्रयासों में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा।* शिक्षा सभी क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कई एसडीजी लक्ष्यों के लिए विशेष कौशल और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है जो शिक्षा प्रणाली उपलब्ध कराती है।
- *शिक्षा आय में व्याप्त विषमता को कम करने में मदद कर सकती है, लेकिन अकेले अपने बलबूते पर नहीं कर सकती।* उपेक्षित वर्गों को उत्तम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने से वे अच्छी आय कमा सकेंगे और इससे असमानता को कम करने में भी मदद मिलेगी। श्रम बाजार के विनियमों और तकनीक को, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में बदलने से नौकरियां कम करके मजदूरों को सजा नहीं दी जानी चाहिए।

- *शिक्षा प्रणालियों को (क) प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक स्तर पर पूरा करने;* (ख) योग्य, जानकार और प्रेरित शिक्षकों की संख्या बढ़ाने; (ग) उपेक्षित वर्गों के लोगों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने; और (घ) जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और लम्बे संघर्ष की संभावना के लिए तैयार करने के लिए अधिक और अपेक्षा के अनुसार धनराशि की जरूरत है।

इक्विटी में सुधार लाना

- *यूनिवर्सल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, महिलाओं की स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाती है।* इस लक्ष्य को हासिल करने से जनसंख्या वृद्धि में कमी होगी, पीढ़ियों में सामाजिक मान्यताएं और रिवायतें बदलेंगी, और इस धरती का बोझ कम होगा।
- *अल्पसंख्यकों, शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित आबादी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीतियों को उनकी भाषा में निर्देश देने को प्राथमिकता देनी चाहिए और बिना पक्षपात के पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।* संबंधित भाषाओं में योग्य और दक्ष शिक्षकों का एक पूल बनाना उन देशों के लिए महत्वपूर्ण होता है जिनमें जातीय अल्पसंख्यकों और प्रवासी आबादी का अनुपात काफी अधिक होता है।
- *शहरी योजना बनाते समय शिक्षा की योजना को भी शामिल किया जाना चाहिए और इसमें ग्रामीण क्षेत्र पीछे नहीं छूटने चाहिए।* झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए अन्य बुनियादी सुविधाओं सहित शिक्षा की योजना बनाना महत्वपूर्ण होता है। सार्वजनिक सुविधाओं सहित योग्य और दक्ष शिक्षकों को स्कूलों में समान रूप से बांटा जाना चाहिए, और स्कूलों को सुरक्षित और हिंसा मुक्त बनाना चाहिए। घटती जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण स्कूल को सदृढ़ करने के लिए योजना पर ध्यान देने और लोगों को शामिल करने की आवश्यकता होती है।

शिक्षा के फोकस को बदलना

- *दक्षता नीतियां बनाने के लिए, शिक्षा प्रणाली में मध्यम और दीर्घावधि आवश्यकताओं दोनों पर तथा स्थायी विकास के प्रभावों पर विचार करना चाहिए।* छात्रों को नया कौशल सिखाने और उसे बेहतर बनाने के लिए पर्यावरण अनुकूल कौशल सिखाए जाने की जरूरत है, जैसा कि माध्यमिक और तृतीयक स्तर के पाठ्यक्रमों किया गया है। व्यापार और उद्योग के साथ बेहतर सहयोग बनाने से शिक्षा के महत्वय और गुणवत्ता में सुधार होगा।

- *नागरिक, शांति और स्थिरता शिक्षा कार्यक्रम एसडीजी की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं।* यदि इन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो वे अधिक न्यायसंगत न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं; न्यायिक और कानून लागू करने के क्षेत्र में क्षमता बढ़ा सकते हैं; कम हिंसक और अधिक रचनात्मक समाज बना सकते हैं; संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच समझ बढ़ा सकते हैं; और ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं जिनसे भावी पीढ़ियों के हालत में काफी सुधार होगा।

स्थायी विकास लक्ष्यों में शिक्षा की निगरानी करने की चुनौतियां

एसडीजी4 के 10 लक्ष्य हैं जो अगले 15 वर्षों के लक्ष्यों को दर्शाते हैं और इनमें पिछले वैश्विक शिक्षा करार के सभी लक्ष्य शामिल हैं। जीईएम रिपोर्ट में वर्ष 2030 के एजेंडा में शिक्षा पर प्रगति की निगरानी की चुनौतियां प्रस्तुत की गई हैं। इसमें सभी एसडीजी4 लक्ष्यों का विश्लेषण किया गया है – इनमें से कुछ ढंग से नहीं बनाए गए हैं – और इनमें संबंधित सूत्रों की निगरानी करने संबंधी तकनीकी चुनौतियों पर चर्चा की गई है। इसमें वैध, विश्वसनीय और मापे जाने वाले समकक्ष उपकरण विकसित करने के प्रयासों की जांच की गई है।

जीईएम रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक शिक्षा निगरानी की प्राथमिकताएं क्यों हैं तथा देशों और संगठनों को किन संसाधनों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें संस्थागत, राजनैतिक और तकनीकी दृष्टि से जांच की जाती है जिन पर संकेतकों को आंका जाता है।

जीईएम रिपोर्ट की भूमिका

जीईएम की रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह समझने में मदद करने का आदेश दिया गया है कि दुनिया शिक्षा और आजीवन सीखते रहने की दिशा में क्या और कैसे प्रगति कर रही है। हालांकि *ईएफए वैश्विक निगरानी रिपोर्ट* को उसका आदेश पूरा होने के रूप में देखा जाता है, यह परिदृश्य 2030 के एजेंडा का विस्तार किए जाने के कारण तेजी से बदल रहा है और उसके सामने नई चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं।

> जीईएम की रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि दुनिया शिक्षा और आजीवन सीखते रहने की दिशा में क्या और कैसे प्रगति कर रही है

निगरानी करने के बिंदुओं का एक सेट तैयार किया गया है (बाक्स 1), हालांकि उनमें से कई के मापने की पद्धति अभी भी विकसित की जा रही है। कई संकेतकों में प्रत्येक लक्ष्य में अवधारणाओं को केवल आंशिक रूप से कवर किया गया है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर लक्ष्यों को मापने और निगरानी करने के वैकल्पिक तरीकों का भी पता लगाया जाना चाहिए।

आने वाले वर्षों में, जीईएम रिपोर्ट उपलब्ध संकेतकों का उपयोग करके, उनकी उपयोगिता पर सवाल उठाकर, स्रोतों की गुणवत्ता को दर्शाकर, सुधार के लिए साक्ष्यों पर नए तरीके से प्रस्तुत करके और उनमें सुधार करने की वकालत करके शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक प्रगति पर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

बाक्स 1

शिक्षा पर एसडीजी4 के लक्ष्य तथा प्रस्तावित वैश्विकी / विषय से संबंधित सूचक फ्रेमवर्क

लक्ष्य 4. *समग्र और एक-समान बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को प्रोत्साहित करना।*

लक्ष्य 4.1 *2030 तक, यह सुनिश्चित करें कि सभी लड़कियों और लड़कों को मुफ्त, न्यायसंगत और बेहतरीन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाए जिससे औचित्यपूर्ण और सीखने के प्रभावी परिणाम सामने आएं।*

1. बच्चों और युवा लोगों का प्रतिशत: (क) ग्रेड 2/3 में; (ख) प्राथमिक शिक्षा के अंत में; और (ग) निम्न माध्यमिक शिक्षा के अंत में (i) पढ़ने और (ii) लिंग द्वारा गणित में न्यूनतम प्रवीणता स्तर पर। **[वैश्विक सूचक 4.1.1]**
2. राष्ट्रीय रूप से शिक्षा का आकलन (i) प्राथमिक शिक्षा के दौरान (ii) प्राथमिक शिक्षा के अंत में, और (iii) निम्न माध्यमिक शिक्षा के अंत में।
3. अंतिम ग्रेड में कुल दाखिला अनुपात (प्राथमिक, निम्न माध्यमिक)
4. समापन दर (प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, ऊपरी माध्यमिक)
5. स्कूल छोड़ने की दर (प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, ऊपरी माध्यमिक)
6. ग्रेड में अधिक उम्र के बच्चों का प्रतिशत (प्राथमिक, निम्न माध्यमिक)
7. कानूनी ढांचे के अनुसार (i) मुफ्त और (ii) अनिवार्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के वर्षों की संख्या

लक्ष्य 4.2. *2030 तक, यह सुनिश्चित करें कि सभी लड़कियों और लड़कों के बचपन का बेहतरीन विकास और देखभाल हो तथा उन्हें प्राथमिक-पूर्व शिक्षा मिले ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें।*

8. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का अनुपात जो लैंगिक आधार पर स्वास्थ्य, शिक्षा और मानसिक-सामाजिक कल्याण से विकसित हो **[वैश्विक सूचक 4.2.1]**
9. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रतिशत जिन्हें घर पर सीखने का सकारात्मक माहौल और अनुभव मिल रहा हो।
10. लैंगिक आधार पर व्यवस्थित ढंग से सीखने की भागीदारी दर (सरकारी प्राथमिक प्रवेश उम्र से पहले एक वर्ष), **[वैश्विक सूचक 4.2.2]**
11. सकल प्राथमिक-पूर्व नामांकन अनुपात
12. कानूनी ढांचे के अनुसार (i) मुफ्त और (ii) अनिवार्य प्राथमिक-पूर्व शिक्षा के वर्षों की संख्या।

लक्ष्य 4.3. *2030 तक, विश्वविद्यालय सहित सभी महिलाओं और पुरुषों को सस्ती और उत्तम तकनीकी, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना।*

13. उच्च शिक्षा के लिए कुल नामांकन अनुपात
14. तकनीकी-व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में भागीदारी दर (15 से 24 वर्ष के बच्चे)
15. लैंगिक आधार पर युवाओं और वयस्कों की पिछले 12 महीनों में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण में भागीदारी दर **[वैश्विक सूचक 4.3.1]**

लक्ष्य 4.4. *2030 तक ऐसे युवाओं और वयस्कों की संख्या काफी अधिक बढ़ जाएगी, जिनमें रोजगार, अच्छी नौकरी और उद्यमिता के लिए तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सहित संबंधित कौशल भी है।*

16.1 ऐसे युवाओं और वयस्कों का प्रतिशत जिन्होंने डिजिटल साक्षरता कौशल में दक्षता का कम से कम न्यूनतम स्तर हासिल कर लिया है।

16.2. ऐसे युवाओं और वयस्कों का प्रतिशत जिन्होंने कौशल के अनुरूप सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) दक्षता हासिल की है **[वैश्विक सूचक 4.4.1]**

17. ऐसे युवा / वयस्कों की शिक्षा प्राप्ति दर, जिन्होंने आयु समूह, आर्थिक कार्यकलाप स्थिति, शिक्षा और कार्यक्रम उन्मुखीकरण के स्तर की शिक्षा प्राप्त की है।

लक्ष्य 4.5. *2030 तक, शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को समाप्त करें और विकलांग व्यक्तियों, स्वदेशी लोगों और उपेक्षित वर्गों के बच्चों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के हर स्तर की एक-समान उपलब्धता सुनिश्चित करें।*

इस सूची में सभी शिक्षा संकेतकों के लिए समानता सूचकांक (महिला/पुरुष, ग्रामीण/शहरी, निम्न/उच्च धनराशि समूह और अन्य जैसे विकलांगता की स्थिति, स्वदेशी लोग और संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) सूची जिसे अलग-अलग किया जा सकता हो। **[वैश्विक सूचक 4.5.1]**

18. प्राथमिक शिक्षा में छात्रों का प्रतिशत, जिनकी पहली या मातृ भाषा, शिक्षा की भाषा है।
19. स्पष्ट सूत्र-आधारित नीतियों के अनुसार उपेक्षित वर्गों को किस सीमा तक शिक्षा संसाधनों को पुनः आवंटित किया गया है।

बाक्स 1

20. शिक्षा के स्तर के अनुसार प्रति छात्र शिक्षा व्यय और वित्त-पोषण का स्रोत।
21. निम्न आय वाले देशों को शिक्षा के लिए आवंटित कुल सहायता का प्रतिशत।

लक्ष्य 4.6. *2030 तक, यह सुनिश्चित करें कि सभी युवाओं और वयस्कों, पुरुषों और महिला दोनों का काफी बड़ा अनुपात, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर लें।*

22. किसी निर्धारित आयु समूह में जनसंख्या का प्रतिशत जिसने लैंगिक आधार पर कार्यात्मक (क) साक्षरता और (ख) संख्यात्मक कौशल में एक निश्चित स्तर की दक्षता प्राप्त कर ली है **[वैश्विक सूचक 4.6.1]**
23. युवा / वयस्क साक्षरता दर
24. साक्षरता कार्यक्रमों में युवाओं / वयस्कों की भागीदारी दर

लक्ष्य 4.7. *2030 तक, यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षार्थियों सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित ज्ञान और कौशल प्राप्त कर लें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सतत विकास और सतत् जीवन शैली, मानवाधिकार, स्त्री-पुरुष समानता, शांति और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने, वैश्विक नागरिकता और सांस्कृतिक विविधता की सराहना और सतत विकास में संस्कृति का योगदान शामिल है।*

25. (i) वैश्विक नागरिकता शिक्षा, और (ii) स्त्री-पुरुष समानता और मानवाधिकारों सहित सतत विकास के लिए शिक्षा किस सीमा तक सभी स्तरों (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां; (ख) पाठ्यक्रम; (ग) शिक्षक शिक्षा और (घ) छात्र मूल्यांकन पर मुख्यधारा में शामिल है **[वैश्विक सूचक 4.7.1]**
26. आयु समूह (या शिक्षा स्तर) द्वारा वैश्विक नागरिकता और स्थिरता से संबंधित मुद्दों की पर्याप्त समझ दिखाने वाला छात्रों का प्रतिशत।
27. पर्यावरण विज्ञान और भू-विज्ञान के ज्ञान में प्रवीणता दर्शाने वाले 15 वर्ष की आयु के छात्रें का प्रतिशत।
28. स्कूलों का प्रतिशत जो जीवन कौशल आधारित एचआईवी और यौन शिक्षा प्रदान करते हैं।
29. विश्व मानवाधिकार शिक्षा कार्यक्रम संबंधी ढांचे को राष्ट्रीय स्तर पर किस सीमा तक लागू किया जाता है (यूएनजीए संकल्प) 59/113 के अनुसार)।

लक्ष्य 4.क. *शिक्षा सुविधाओं का निर्माण और उन्नयन जो बच्चों, विकलांगों और लिंग के प्रति संवेदनशील हों तथा सभी के लिए सुरक्षित, अहिंसक, समावेशी और प्रभावी शिक्षा माहौल प्रदान करते हैं।*

30-32. ऐसे स्कूलों का प्रतिशत जिनमें (क) बिजली, (ख) शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए इंटरनेट, (ग) शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर, (घ) विकलांग छात्रों के लिए बुनियादी ढांचे और सामग्री अनुकूलन; (ड़) बुनियादी पेयजल (च) एकल लैंगिक आधारित स्वच्छता सुविधाएं, और (छ) हाथ धोने की बुनियादी सुविधाएं (पानी, साफ-सफाई और स्वच्छता (वॉश) सूचक परिभाषाओं के अनुसार) **[वैश्विक सूचक 4.क.1]**
33. डराना-धमकाना, शारीरिक दंड, उत्पीड़न, हिंसा, यौन भेदभाव और शोषण का सामना करने वाले छात्रों का प्रतिशत।
34. छात्रों, कर्मियों और संस्थानों पर हुए हमलों की संख्या।

लक्ष्य 4.ख. *2020 तक, विश्व स्तर पर विशेषकर अल्प विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्तियों; विकसित देशों और अन्य विकासशील देशों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तकनीकी, इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्यक्रमों सहित सहित उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए छोटे महाद्वीप विकासशील देशों और अफ्रीकी देशों की संख्या को बढ़ाया जाए।*

35. लाभार्थी देश द्वारा प्रदत्त उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति की संख्या
36 क्षेत्र और अध्ययन के प्रकार द्वारा छात्रवृत्ति के लिए दी जाने वाली सरकारी विकास सहायता की मात्रा। **[वैश्विक सूचक 4.ख.1]**

लक्ष्य 4.ग. *2030 तक विकासशील देशों, विशेष रूप से कम विकसित देशों और छोटे से द्वीप विकासशील राज्यों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से योग्य शिक्षकों की संख्या3 को बढ़ाया जाए, सहित।*

37. राष्ट्रीय मानकों के अनुसार शिक्षा के स्तर और संस्था के प्रकार द्वारा योग्य शिक्षकों का प्रतिशत।
38. शिक्षा के स्तर के अनुसार छात्र /योग्य शिक्षक अनुपात।
39. शिक्षकों का अनुपात: (क) प्राथमिक-पूर्व, (ख) प्राथमिक, (ग) निम्न माध्यमिक और (घ) उच्च माध्यमिक शिक्षा, जिन्होंने किसी निर्धारित देश में प्रासंगिक स्तर पर शिक्षण के लिए अपेक्षित सेवा-पूर्व और सेवाकालीन कम से कम न्यूनतम संगठित शिक्षक प्रशिक्षण (उदाहरण के लिए शैक्षणिक) प्राप्त किया है **[वैश्विक सूचक 4.ग.1]**
40. शिक्षा के स्तर के अनुसार छात्र / प्रशिक्षित शिक्षक अनुपात।
41. अन्य व्यवसायों की तुलना में औसत शिक्षक वेतन जो शिक्षा योग्यता के तुलनात्मक स्तर के लिए अपेक्षित हो।
42. शिक्षा के स्तर के अनुसार शिक्षकों द्वारा नौकरी छोड़ने की दर।
43. शिक्षकों का प्रतिशत, जिन्होंने प्रशिक्षण के प्रकार के अनुसार पिछले 12 महीनों में सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

स्रोत: अनुलग्नक, यूनेस्को (2016)। *शिक्षा 2030 इंचियोन घोषणा और कार्रवाई के लिए ढांचा: समग्रता और न्यायसंगत गुणवत्ता शिक्षा और सभी के लिए आजीवन शिक्षा। पेरिस, यूनेस्को (अद्यतन किया गया संस्करण)।*

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा

लक्ष्य 4.1

लक्ष्य 4.1 में सभी को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना एक आवश्यक और कारगर शिक्षा के माध्यम के रूप में की गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति को मुख्य रूप से एसडीजी के प्रति सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता से आंका जाएगा। इससे जुड़े आलोचकों का मानना है कि सभी के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य पर ज्यादा जोर देने से हम सभी को कम से कम नौ वर्ष की बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के प्राथमिक लक्ष्य से भटक जाएंगे।

शिक्षा प्रदान करना, उसका हिस्सा बनना और उसे पूरा करना

नए एजेंडे में शिक्षा प्रदान करने पर गहन नजर रखे जाने की जरूरत है। यद्यपि एजेंडा का लक्ष्य वर्तमान में वर्ष 2030 तक 12 वर्ष तक की शिक्षा प्रदान करना है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2 करोड़ 50 लाख बच्चे प्राथमिक स्कूल भी नहीं जाते। कम आय वाले देशों के सबसे गरीब परिवारों के बच्चों में से लगभग 30% कभी स्कूल नहीं गए।

लक्ष्य 4.1 प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित है और, पहली बार, उच्च माध्यमिक शिक्षा को इसमें शामिल किया गया है। वर्ष 2014 में, 91% बच्चे प्राथमिक स्कूल, 84% किशोर माध्यमिक स्कूल में तथा 63% युवा उच्च माध्यमिक स्कूल जा रहे थे। इन अनुमानों से पता चलता है कि कुल 26 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे अर्थात् प्राथमिक स्कूल की आयु के 6 करोड़ 10 लाख बच्चे, माध्यमिक विद्यालय की आयु के 6 करोड़ बच्चे और उच्च माध्यमिक स्कूजाने की आयु के 14 करोड़ 20 लाख बच्चे।

चित्र 8:
अधिकांश देशों के लिए सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है
शिक्षा के स्तर द्वारा लक्ष्य प्राप्ति दर, चयनित देश, 2008 – 2014

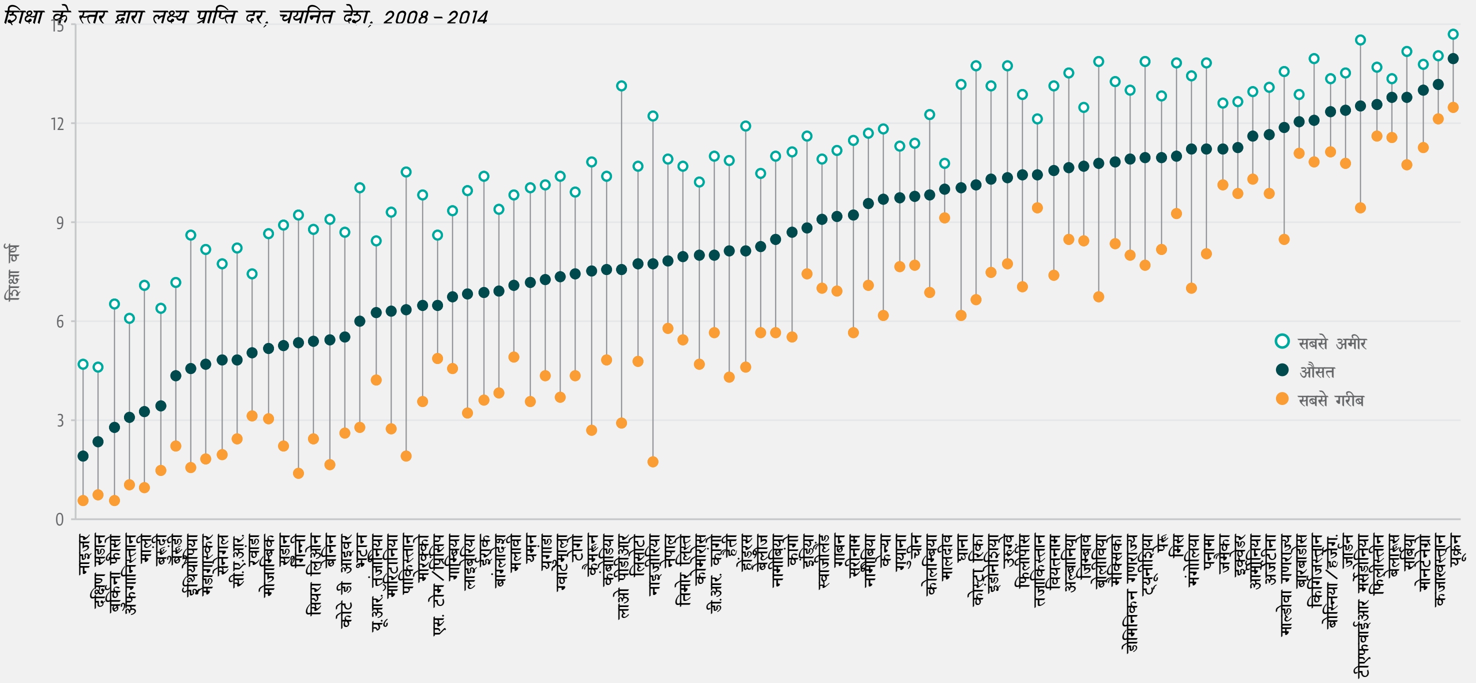

स्रोत: घरेलू सर्वेक्षणों के आधार पर जीईएम रिपोर्ट दल विश्लेषण

नया एजेंडा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसमें भागीदारी से कहीं अधिक शिक्षा पूर्ण करने पर बल दिया गया है। वर्ष 2008–2014 के दौरान, उच्च मध्यम आय वर्ग में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की दर 92%, निम्न मध्यम आय वर्ग में 51% और कम आय वाले देशों में 84% थी और आखिर में, सबसे गरीब लड़कियों में यह 25% थी। उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने की दर, उच्च आय वर्ग में 84%, उच्च मध्यम आय वर्ग में 43%, निम्न मध्यम आय वर्ग में 38% और कम आय वाले देशों में 14% थी। यहां तक कि उच्च आय वाले सबसे अमीरों देश भी सभी के लिए शिक्षा पूरा करने की दर 93% ही प्राप्त कर सके थे। कम आय वाले देशों में सबसे गरीब लड़कियों में से सिर्फ 1 प्रतिशत ही उच्च माध्यमिक विद्यालय तक की शिक्षा पूरी कर पाई थीं।

अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा

> "अनिवार्य शिक्षा पर 190 देशों से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि 23% देशों में अनिवार्य शिक्षा नौ वर्ष से कम थी"

प्रमुख विषयों में से एक विषय कानून में निर्धारित वर्षो तक (i) मुफ्त और (ii) अनिवार्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने की गारंटी देना है। अनिवार्य शिक्षा पर उपलब्ध 190 देशों के आंकड़ों में से 44 देश (23%) नौ वर्ष से कम अवधि की अनिवार्य शिक्षा दे रहे हैं।

अनिवार्य शिक्षा औसतन 9 वर्ष और निःशुल्क शिक्षा 11 वर्ष तक दी जाती है। लेकिन लक्ष्य की प्रगति को आंकने की दृष्टि से मुफ्त शिक्षा की अवधारणा में अड़चने हैं क्योंकि जहां फीस समाप्त कर दी गई है, वहां भी शिक्षा से संबंधित अनेक प्रकार के दूसरे खर्चों का बोझ परिवारों पर पड़ सकता है। परिवारों द्वारा प्रत्येक स्तर पर शिक्षा पर किए जा रहा कुल खर्च इस बात का ठोस प्रमाण है कि शिक्षा किस हद तक मुफ्त है।

गुणवत्ता

प्रस्तावित निगरानी ढांचे में शिक्षा के नतीजे और समानता से संबंधित निर्देशों को छोड़कर गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है।

गुणवत्ता पर विचार-विमर्श करने के लिए सांकेतिक ढांचे के आधार पर दो बातों का चयन किया गया है: कक्षा से संबंधित जानकारी और प्रक्रिया। पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता और उसका उपयोग गुणवत्ता के महत्वपूर्ण पहलू हैं, फिर भी स्कूल का दौरे करने और कक्षाओं को देखने से पता चलता है कि सरकारी आंकड़े बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं हैं। चाड में, कक्षा 2 और कक्षा 6 के लगभग 90% छात्रों को पढ़ने और गणित के छात्रों को कम से कम 2 अन्य लोगों के साथ पाठ्यपुस्तकों को साझा करना पड़ा था।

शिक्षा प्रणाली की तुलना करने के लिए कक्षाओं की वास्तविक स्थिति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। फिर भी, व्यापक तौर पर लगातार निगरानी रखने से शिक्षण अभ्यास और अध्यापन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर नीति-निर्माताओं का ध्यान जाता है। ब्राजील, कोलंबिया, होंडुरास, जमैका और पेरू की 15,000 कक्षाओं का सर्वेक्षण करने से पता चला है कि शिक्षक शिक्षा से संबंधित निर्देशों पर अपना 60-65% समय देते हैं जो की गई 85% सिफारिश से काफी कम है। हमें ऐसे साधनों और उपायों की खोज निरंतर जारी रखनी होगी जिन्हें अपनाया जा सकता हो और साथ ही ये विश्वसनीय, वैध, किफायती और आसानी से इस्तेमाल करने के लायक हों।

शिक्षा के परिणाम

शिक्षा के परिणामों में सुधार लाने के लिए एक मानक का होना आवश्यक है जिससे यह पता चल सके कि क्या प्रगति हो रही है। फिर भी, कुछ प्रश्न उठते हैं कि शिक्षा के प्रासंगिक और कारगर परिणाम क्या हैं, उन्हें कैसे मापा जाए तथा उनके निष्कर्षों का कैसे उपयोग किया जाए।

प्रस्तावित विश्व स्तरीय मानक -पढ़ने और गणितीय कौशल को मापने के लिए, आकलन किए जाने वाले शिक्षा के परिणामों की विषय-वस्तु, पूरा किए जाने वाले आवश्यक गुणवत्ता मानकों का आकलन करने और इस्तेमाल किए जाने वाले मानकों की रिपोर्टिंग करने और उसे परिभाषित करने पर आम सहमति की आवश्यकता होती है।

सीखने के परिणाम हेतु उपाय: सामग्री का निर्धारण

पढ़ने और गणित जैसे क्षेत्र में एक न्यूनतम प्रवीणता स्तर निर्धारित करने के आकलन हेतु बुनियादी मानकों की आवश्यकता होती है। जब विभिन्न पाठ्यक्रम के बीच साझा आधार का पता लगाने की आवश्यकता होती है, तब क्या होता है? पूरे पाठ्यक्रम में सीखने की संभावित प्रगति क्या है? किन प्रश्नों से पता चलता है कि एक शिक्षार्थी प्रवीणता के एक खास स्तर तक पहुँच गया है? प्रवीणता के स्तर को कैसे परिभाषित किया जाता है?

दो विवादित मुद्दों से तनाव उत्पन्न होता है। पहला है, पढ़ने और गणित का प्रारंभिक ग्रेड में आकलन, राजनीतिक और तकनीकी कारणों से विभाजन उत्पन्न करने वाला है। फिर भी जमीनी स्तर पर यह प्रमुख चुनौतियों की ओर ध्यान खींचता है। मलावी में वर्ष 2012 में, ग्रेड 2 के 90% छात्र चिचेवा में एक भी शब्द नहीं पढ़ सकते थे, लगभग 40 प्रतिशत ग्रेड 4 में भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे।

दूसरा, पढ़ने और गणित के ज्ञान में प्रवीणता के संबंध में वैश्विक सूचक में विद्यालय नहीं जा रहे बच्चों को शामिल नहीं किया जाता है। ग्रामीण पाकिस्तान में, ग्रेड 10 के 89% छात्र उर्दू, सिंधी या पश्तो में ग्रेड 2 की कहानी को ही पढ़ सके, लेकिन यदि सभी 14 वर्ष की आयु के बच्चों की बात करें तो केवल 64% बच्चे ही ऐसा कर सके।

शिक्षा परिणाम को मापने का तरीका: मूल्यांकन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना

इस विषय से संबंधित एक संकेतक यह है कि क्या प्राथमिक शिक्षा के दौरान, प्राथमिक शिक्षा के अंत में और माध्यमिक शिक्षा के अंत में, देश ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा संबंधी प्रतिनिधि मूल्यांकन कराया है। मूल्यांकन के लिए, स्पष्ट मानकों के साथ एक सुदृढ़ तंत्र का होना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्यांकन इन मानकों को पूरा करते हैं अथवा नहीं।

मूल्यांकन गुणवत्ता के दो पहलू महत्वपूर्ण हैं: (क) किसी सक्षम संस्थागत संदर्भ द्वारा स्थिरता और शिक्षा प्रणाली के साथ सशक्त संबंध सुनिश्चित किया जाए; और (ख) राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि मूल्यांकन वैध और विश्वसनीय होना चाहिए, जिसमें नीति निर्माताओं और लोगों के लिए प्रासंगिक जानकारी हो। राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रतिनिधि मूल्यांकन को शिक्षा के लक्ष्यों और छात्रों के सीखने के उद्देश्यों के साथ-साथ शिक्षकों को पेशेवर रूप में तैयार करने के अवसरों के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि निगरानी के लिए कौन सा मूल्यांकन उचित है। इससे दो प्रश्न उठते हैं। पहला, अत्यधिक सख्त तकनीकी मानदंड रखने से, अपेक्षित क्षमता कई देशों की पहुंच से परे हो सकती है और इसका परिणाम यह होगा कि सेवा प्रदान करने वालों का एक छोटा सा समूह ही अधिकतर मूल्यांकन का कार्य करेगा, जिससे देश के संबंध में उसकी प्रासंगिकता और उपयोग में कमी आएगी। दूसरा, सीखने से संबंधित सशक्त मूल्यांकन करने के लिए, राष्ट्रीय क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए संसाधनों को अधिक कुशलता से आवंटित किया जाना चाहिए।

शिक्षा परिणाम मापक: विभिन्न मूल्यांकनों के माध्यम से परिणामों की रिपोर्टिंग

शिक्षा के परिणाम प्राप्त करने के वैश्विक मापक निर्धारित करने के लिए रिपोर्टिंग और स्तर (या आयु) और विषय के मानकों के निर्धारण में तालमेल होना आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न मूल्यांकनों के माध्यम से ऐसी सामग्री का एक सेट तैयार किया जाएगा, जिसे कठिनाई के स्तर का विश्लेषण करके जोड़ा जा सके। फिर भी सामग्री के साथ मूल्यांकन को जोड़ना एक तकनीकी मामला नहीं है बल्कि इसे संकेतक के तौर पर कार्य करना चाहिए।

वैश्विक रूप से शिक्षा के तुलनात्मक परिणाम को दर्शाने वाले संकेतकों का उद्देश्य सिर्फ वैश्विक स्तर पर निगरानी करना नहीं होना चाहिए बल्कि उसे देश की अपेक्षाओं को भी पूरा करना चाहिए। हाल में स्थापित 'ग्लोबल एलायंस टू मॉनिटर लर्निंग' से दोनों उद्देश्यों को साथ लेकर चलने में मदद मिलेगी।

शुरुआती बचपन

लक्ष्य 4.2

लक्ष्य 4.2 अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के इस तथ्य की प्रतिबद्धता को दोहराता है कि बचपन की देखभाल और शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चों का आधार सुदृढ़ किया जाए। लक्ष्य में निर्धारित दृष्टिकोण की निगरानी करने में तीन चुनौतियां सामने आएंगी: (क) इस संबंध में यह पूरी जानकारी नहीं है कि कम से कम एक वर्ष की प्राथमिक-पूर्व शिक्षा का लाभ कितने बच्चे ले रहे हैं (ख) प्रस्तावित संकेतकों से गुणवत्ता का पता नहीं चलता; और (ग) जबकि लक्ष्य में देखभाल और शिक्षा से आगे बढ़कर बच्चों के विकास की बात की गई है, लेकिन इसके लिए निगरानी तंत्र आरंभ किए जाने की व्यावहारिकता के बारे में अभी कुछ निश्चित नहीं है।

> "प्राथमिक-पूर्व शिक्षा 50 देशों में अनिवार्य है तथा 38 देशों में कम से कम एक वर्ष के लिए यह निःशुल्क और अनिवार्य है"

शिक्षा तक पहुंच और शिक्षा प्राप्त करना

अलग-अलग देशों में, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के मुकाबले प्राथमिक-पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वालों की तुलना करना अत्यधिक कठिन है। प्राथमिक-पूर्व शिक्षा की आयु समूहों तथा प्राथमिक शिक्षा आरम्भ करने की आयु का अन्य स्तरों की तुलना में मानक नहीं बनाया गया है। तुलनात्मक रूप से बहुत कम देशों में प्राथमिक-पूर्व शिक्षा निःशुल्क और/अथवा अनिवार्य है: यह 50 देशों में अनिवार्य है तथा 38 देशों में कम से कम एक वर्ष के लिए यह निःशुल्क और अनिवार्य है।

विश्व भर में 67% बच्चे प्राथमिक स्कूल में प्रवेश लेने की आयु से एक वर्ष पहले प्राथमिक–पूर्व या प्राथमिक शिक्षा में अपना दाखिला कराते हैं। यह अनुमान पहली कक्षा के छात्रों के बीच प्राथमिक–पूर्व शिक्षा के संबंध में पिछले अनुभव के घरेलू सर्वेक्षण अनुमानों के अनुरूप नहीं है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति के द्वारा स्कूल में उपस्थिति का पता लगाया जा सके। कम और मध्यम आय वाले देशों के 3 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों में से सबसे गरीब बच्चों की तुलना में सबसे अमीर घरों के बच्चों द्वारा बचपन में शिक्षा प्राप्त करने की संभावना लगभग 6 गुना अधिक होती है।

गुणवत्ता

इस लक्ष्य के अंतर्गत अच्छी और उत्तम शिक्षा का प्रावधान करने पर बल दिया गया है। गुणवत्ता से अभिप्राय यह है कि कौन सा स्कूल और कक्षा की व्यवस्था (आधारभूत ढांचा और अध्यापन प्रक्रिया सहित) तथा प्रणाली, किस हद तक बच्चों, विशेष रूप से समाज से बहिष्कृत होने की कगार पर बैठे बच्चों, के संपूर्ण विकास में योगदान दे सकती है। हालांकि देशों को स्वयं अपने लक्ष्यों तथा गुणवत्ता मानदण्डों का निर्धारण करने की जरूरत है, फिर भी, ऐसे अनेक तरीके हैं जिनसे गुणवत्ता की तुलनात्मक ढंग से निगरानी की जा सकती है, यद्यपि इससे नीति संबंधी बहस छिड़ जाती है। बाल्यावस्था संबंधी नीतियों की विश्व बैंक समीक्षा में शामिल कम और मध्यम आय वाले 21 देशों में से 13 देशों ने छात्र/शिक्षक अनुपात के संबंध में बुनियादी मानदंड निर्धारित किए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 देशों ने ही इसे लागू किया है।

चित्र 9:

परिवारों और स्कूलों के बीच बचपन की शुरुआती देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों में भागीदारी का लेखा–जोखा

पिछले वर्ष प्राथमिक–पूर्व शिक्षा में प्राथमिक–पूर्व शिक्षा समायोजित निवल दाखिला अनुपात तथा प्राथमिक स्कूल के पहले ग्रेड में छात्रों का प्रतिशत, चयनित देश, 2010–2015

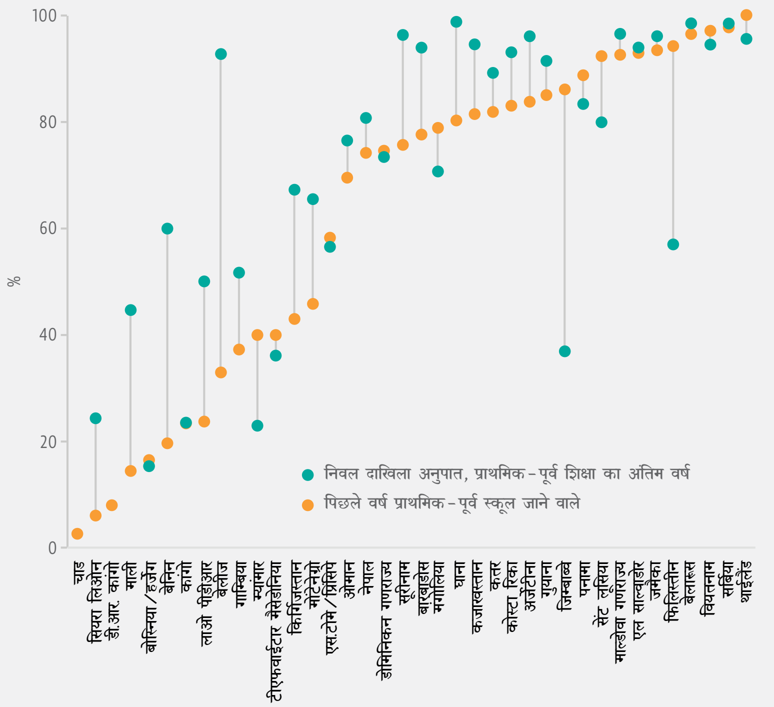

स्रोत: निवल और समायोजित निवल दाखिला अनुपात के लिए यूआईएस डेटाबेस; प्राथमिक स्कूल के पहले ग्रेड में छात्रों, जो पिछले स्कूल वर्ष के दौरान प्री–स्कूल गए थे, के प्रतिशत से संबंधित एमआईसीएस की अंतिम और मुख्य निष्कर्ष रिपोर्टें

बच्चों के विकास के परिणाम

लक्ष्य 4.2 में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि बच्चे औपचारिक स्कूली शिक्षा को व्यवस्थित ढंग से पूरा करें और 'प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार' रहें। यह समग्र दृष्टिकोण में बाल विकास के पिछले मानदंड से भिन्न, विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों को आधार बनाया गया है। बच्चों के विकास को तय करने की प्रक्रिया जटिल है। अलग–अलग संस्कृतियों के बीच मानदण्डों के विकास पर नज़र रखने और निष्कर्षों के आधार पर मापने के तरीकों का विकास किए जाने की आवश्यकता है।

यूनीसेफ की शुरुआती बाल विकास निर्देशिका (ईसीडीआई) में मानदंडों को मापने के लिए सबसे अधिक मौजूदा कवरेज दी गई है। वर्ष 2010–2015 के दौरान ज्यादातर कम और मध्यम आय वाले 56 देशों में यह पाया गया कि 3 वर्ष की आयु के लगभग 70% और 4 वर्ष की आयु के 80% बच्चों का सही ढंग से विकास हो रहा था। इस सूची में चार पहलू हैं, लेकिन इसे केवल एक सुदृढ़ पहलू से ही तय किया जाता है – साक्षरता और गणित का ज्ञान – जिसमें ज्ञान संबंधी क्षमता की बजाय प्रारंभिक शिक्षा के मानदण्डों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

बच्चों को उनकी अधिकतम क्षमता प्राप्त करने में सहायक एक प्रमुख पहलू घर का माहौल है जहां संवाद होता है और सीखने के लिए सामग्री उपलब्ध होती है। यूक्रेन में परिवार के वयस्क सदस्य 3 से 4 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को कम से कम चार गतिविधियों में शामिल करते हैं जबकि इसकी तुलना में घाना में सिर्फ 40% बच्चों के मामले में ऐसा किया जाता है। वर्ष 2010–2015 के दौरान ज्यादातर कम और मध्यम आय वाले 54 देशों में से 19% परिवारों के पास ही बच्चों के उपयोग की 3 पुस्तकें और 7.5% के पास ही 10 पुस्तकें थीं। सबसे गरीब 20% में से, 1% से कम परिवारों के पास ही 10 पुस्तकें थीं।

लक्ष्य 4.3

तकनीकी, व्यावसायिक, उच्च और प्रौढ़ शिक्षा

लक्ष्य 4.3 के द्वारा वैश्विक विकास एजेंडे में तकनीकी, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा को शामिल किया गया है। इन्हें 'सभी के लिए शिक्षा' का हिस्सा माना गया था, लेकिन इसकी भूमिका वैकल्पिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक की ही थी।

लक्ष्य के वैश्विक सूचक-पिछले 12 माह के दौरान औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण में भाग लेने वाले युवाओं और वयस्कों के प्रतिशत में प्रौढ़ शिक्षा को भी शामिल किया गया है। अत: जीईएम रिपोर्ट में लक्ष्य 4.3 के अंतर्गत तकनीकी, व्यावसायिक, उच्च और प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में उनके निर्माण पर तीन दृष्टिकोण: उपलब्धता, वहनीयता और गुणवत्ता की दृष्टि से विचार किया गया है।

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण

संस्थानों, कार्यस्थल या दोनों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) प्रदान किया जाता है। विभिन्न नीतिगत आधारभूत ढांचे, संस्थागत व्यवस्था और संगठनात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए राष्ट्रीय आंकड़ा प्रणाली केवल आंशिक तस्वीर ही पेश करती है, जिससे देशों में टीवीईटी प्रावधान का तुलनात्मक अध्ययन करना कठिन हो जाएगा।

> "12 देशों की जीईएम रिपोर्ट का विश्लेषण दर्शाता है कि लगभग 20% युवाओं ने कार्यस्थल आधारित कार्यक्रमों में भाग लिया था"

वर्तमान निगरानी व्यवस्था, विशेष रूप से शिक्षा मंत्रालयों की निगरानी वाले संस्थानों में दाखिले पर बल देती है। यह लक्ष्य की निगरानी की संभावना को काफी कम कर देता है। कार्यस्थल-आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण को शामिल करने के लिए श्रमिकों, उपक्रमों या घरेलू सर्वेक्षणों के आंकड़े अपेक्षित हैं, जिसमें उनकी परिभाषाओं और प्रश्नावली को और अधिक समन्वित किए जाने की आवश्यकता है। 12 देशों की जीईएम रिपोर्ट का विश्लेषण दर्शाता है कि लगभग 20% युवाओं ने कार्यस्थल आधारित कार्यक्रमों में भाग लिया था।

सामर्थ्य के प्रश्न पर इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार की कौन सी नीति, टीवीईटी में दाखिले में व्याप्त असमानता का किस हद तक समाधान करेगी। सेवा प्रदायकों, लागत ढांचों, सार्वजनिक नीतियों और राष्ट्रीय संदर्भ में अत्यधिक विविधता के कारण इस बात की संभावना नहीं रहती कि किसी एक संकेतक द्वारा सामर्थ्य की व्याख्या की जा सके। एक संभावित तरीका यह हो सकता है कि छात्र से संस्थान को प्राप्त होने वाली आय की तुलना, छात्रों को प्राप्त होने वाली सरकारी वित्तीय सहायता की राशि से की जाए।

टीवीईटी गुणवत्ता का मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि क्या राष्ट्रीय योग्यता फ्रेमवर्क में विश्वसनीय मानकों को शामिल किया गया है। कम से कम 140 देशों के पास ऐसे फ्रेमवर्क हैं। इनके प्रभाव में अंतर हो सकता है, लेकिन यह शिक्षार्थियों, सेवा प्रदायकों और नियोक्ताओं की योग्यता किस प्रकार प्राप्त हुई, के स्थान पर, परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करने में मदद कर सकता है।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा में अल्पकालिक पाठ्यक्रम से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम शामिल होते हैं। संस्थानों में आकार, लागत, पाठ्यक्रमों, प्रक्रियाओं और गुणवत्ता के अनुसार काफी अंतर है। जहां तक इसके न्यायसंगत होने का प्रश्न है, तो इस संबंध में प्रवेश से लेकर स्नातक तक विभिन्न चरणों में आने वाली कई बाधाओं को ध्यान में रखना होगा। उच्च शिक्षा में विश्व स्तरीय दाखिला वर्ष 2000 के 10 करोड़ से दोगुना हो कर वर्ष 2014 में 20 करोड़ 70 लाख हो गया है, लेकिन देशों के बीच और देश के अंदर इस स्थिति में काफी अंतर है। वर्ष 2013 में फिलीपींस में, 25 से 29 वर्ष की आयु के सबसे अमीर 52% व्यक्तियों ने उच्च शिक्षा के कम से कम चार वर्ष पूरे किए, लेकिन सबसे निर्धन व्यक्तियों में से सिर्फ 1% ही ऐसा कर पाए।

उच्च शिक्षा के मामले में सामर्थ्य, लागत और आय के बीच संबंध पर निर्भर करती है। कुल लागत की तुलना घरेलू सर्वेक्षण से प्राप्त परिवार की औसत आय स्तरों से की जा सकती है। यद्यपि यह एक उपयोगी मार्गदर्शिका है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि कितने युवा उच्च शिक्षा का बोझ नहीं उठा सकते। इसे मापने का एक संभावित तरीका यह है कि शिक्षा के कारण

चित्र 10:

गरीब और अमीर लोगों के बीच उच्च शिक्षा प्राप्त करने में व्यापक अंतर है।

25–29 वर्ष की आयु के छात्रों का प्रतिशत जिन्होंने उच्च शिक्षा में कम से कम चार वर्ष पूरे किए हैं, चयनित देश, 2008–2014

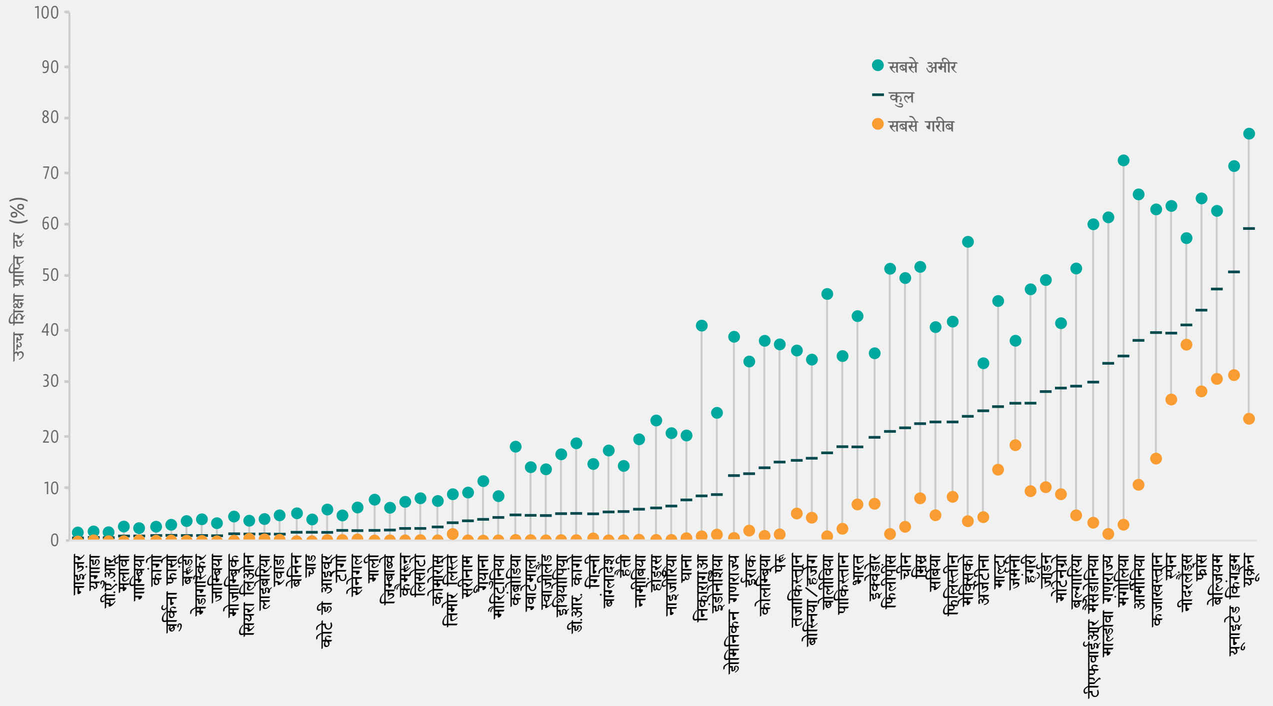

स्रोत: घरेलू सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर जीईएम रिपोर्ट दल विश्लेषण

किसी परिवार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ की तुलना ऐसे परिवार से की जाए, जिसे सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई हो। सबसे जरूरतमंद लोगों तक सहायता सफलतापूर्वक पहुंचे, इस बात की भी निगरानी की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय नीतिगत ढांचों और संसाधनों तथा विश्वविद्यालय के मिशन में विरोधाभास, उच्च शिक्षा में अर्थपूर्ण विश्व स्तरीय गुणवत्ता मानदंडों को प्राप्त करने में काफी बाधाएं उत्पन्न करता है। विश्वविद्यालयों की रैंकिंग ज्यादा ध्यान आकृष्ट करती है, क्योंकि उन्हें समझना आसान होता है लेकिन वे शिक्षण की गुणवत्ता या विद्यार्थियों के शिक्षण पर आधारित न हो कर, वहां कितना शोध हो रहा है, इस पर आधारित होती हैं।

प्रौढ़ शिक्षा

एजुकेशन 2030 फेमवर्क फॉर एक्शन” के अनुसार, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर लक्ष्य 4.3 प्राप्त करने के लिए एक रणनीति बनाते हैं। प्रौढ़ शिक्षा औपचारिक (संस्थागत) या अनौपचारिक हो सकती है।

प्रावधानों में विविधता के कारण विशेष रूप से भागीदारी की निगरानी रखना कठिन बना देती है। यद्यपि औपचारिक शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षार्थियों के संबंध में कुछ जानकारी मौजूद होती है, लेकिन यह काफी कम होती है। यूरोपीय संघ के 28 देशों में, वर्ष 2011 में, लगभग 6% वयस्कों ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और 37% ने अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त की। एक सर्वेक्षण के अनुसार इससे हमें विश्व स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा में भागीदारी को मापने के साधन विकसित करने में मदद मिल सकती है।

सामर्थ्य का आकलन करना कठिन है, ऐसा न सिर्फ निजी वित्त–पोषण की बढ़ी हुई भूमिका के कारण है बल्कि सार्वजनिक वित्त पोषण के संबंध में सूचना के अभाव के कारण भी ऐसा हो रहा है। 6 में से 1 से भी कम देश, अपनी जीडीपी का 0.3 प्रतिशत से अधिक प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय करते हैं। कुल मिलाकर, सार्वजनिक व्यय के संबंध में अधिक जानकारी यह जानने के लिए जरूरी है कि जरूरतमंद लोगों तक इसे कैसे पहुंचाया जाए।

प्रौढ़ शिक्षा की गुणवत्ता के सभी आयामों की निगरानी करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। प्रौढ़ शिक्षा पर तीसरी वैश्विक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि आंकड़ों में सुधार लाने के लिए ‘प्राथमिकताओं को सावधानी से तय करने तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके लक्ष्य उपलब्ध संसाधनों के अनुसार हों’।

रोजगार के लिए दक्षता

लक्ष्य 4.4

लक्ष्य 4.4 में तीन महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं: विभिन्न संदर्भों में विश्व स्तर पर निगरानी हेतु कौन सी दक्षता "रोजगार, अच्छी नौकरी और उद्यमी बनने" के लिए विशेष रूप से आवश्यक हैं? क्या दक्षता मुख्यत: शिक्षा और प्रशिक्षण से ही प्राप्त की जा सकती है या कहीं और से भी प्राप्त की जा सकती है? क्या उपलब्ध मानदंड वैध हैं और कम लागत पर व्यावहारिक हैं?

प्रस्तावित संकेतकों में इन प्रश्नों का कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलता। पहला है प्रौढ़ जनसंख्या में शिक्षा प्राप्त करने की दर, जो कि दक्षता का मानदंड नहीं है? दूसरा है, सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और डिजिटल साक्षरता दक्षता, जिसमें एजेंडा के सीमित होने का जोखिम है लेकिन इसमें ठोस और आंकी जा सकने वाली दक्षता पर ध्यान दिए जाने का प्रयास भी किया गया है।

> "यूरोपीय संघ में वर्ष 2014 में 44% वयस्कों ने स्प्रेडशीट पर मूल अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग किया

ज्ञान संबंधी दक्षता

बुनियादी ज्ञान संबंधी दक्षता में साक्षरता और गणित की जानकारी शामिल है। जीईएम रिपोर्ट का नया विश्लेषण दर्शाता है कि उच्च साक्षरता दक्षता अच्छी नौकरी पाने की संभावना को लगभग दोगुना कर देती है।

सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी दैनिक जीवन और कार्यों के लिए अनिवार्य बन गई है। यूरोपीय संघ में वर्ष 2014 में 44% वयस्क स्प्रेडशीट पर मूल अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग कर पाए थे, जिसमें से रोमानिया में 16% और फिनलैण्ड में 63% ऐसे लोग थे जो ऐसा कर पाए थे।

डिजिटल साक्षरता दक्षता एक बेहतर संकेतक है, क्योंकि उनका प्रत्यक्ष रूप से आकलन किया जा सकता है। वर्ष 2013 में, चेक गणतंत्र में 8वीं कक्षा के 88% छात्र कंप्यूटर के उपयोग का कार्यसाधक ज्ञान रखते थे, जिसकी तुलना में थाईलैण्ड के 13% और तुर्की के 9% छात्रों को ही इसका ज्ञान था। समय के साथ प्रौद्योगिकी में हो रहे तेजी से परिवर्तन और विशेष रूप से, वर्तमान प्रश्नों में मौजूद सांस्कृतिक रुझान से निपटने के लिए एक विश्व स्तरीय साधन की आवश्यकता होगी।

गैर-ज्ञान संबंधी दक्षता . . .

ऐसी दक्षता के संबंध में लगातार रुचि बढ़ रही है जिसमें अधिक ज्ञान की जरूरत नहीं होती, यद्यपि व्यवहार में, कार्यस्थल में इस्तेमाल होने वाली कई महत्वपूर्ण दक्षता - जैसे कि मूलभूत लेकिन रचनात्मक दक्षता, गहन सोच और सहयोग दक्षता -जिसका श्रेणीकरण करना संभव नहीं है।

ऐसे साक्ष्य मौजूद नहीं जिनसे अध्यावसाय, स्व-नियंत्रण, या सामाजिक और भावनात्मक कौशल जैसे गैर-ज्ञान संबंधी दक्षता के स्तर का पता चल सके, और रोजगार की सकारात्मक संभावनाओं का बेहतर तरीके से पूर्वानुमान लगा सके। इसका अंतिम उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना होता है।

गैर-ज्ञान संबंधी दक्षता के संबंध में देशों के बीच तुलना करने के किसी मापदंड का विकास करना चुनौतीपूर्ण है। जीईएम रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर तुलना के लिए बड़े पैमाने वाले मापदंडों के प्रयोग से बचने की सिफारिश करती है तथा उन्हें हासिल करने के मापदंड का अनुसंधान करने पर बल देती है।

. . . और रोजगार के साथ उनका संयोजन

रोजगार के लिए ज्ञान और गैर-ज्ञान संबंधी दक्षता के दो उदाहरण वित्तीय जानकारी तथा उद्यम दक्षता का होना है। हाल के वर्षों में वित्तीय जानकारी के अनुभव आधारित मापदंडों का विकास करने के प्रयासों में तेजी आई है। एक परिभाषा के अनुसार दुनिया भर के 33% वयस्कों को वित्तीय जानकारी है जिनमें यमन में 13% से लेकर नार्वे में 71% तक ऐसे व्यस्क हैं। उद्यमशीलता दक्षता अभी अधिकतर अनुसंधान स्तर पर है, इसलिए उसका मूल्यांकन करने से यह प्रश्न उठता है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में इससे संबंधित कौन से विषयों को शामिल किया जाए।

लक्ष्य 4.5

समानता

सतत विकास के 2030 के एजेंडा में 'किसी भी पिछड़ न जाए' का लक्ष्य शामिल है और उम्मीद है कि इससे विश्व स्तर पर निगरानी करने तथा असमानता की सूचना देने की मांग बढ़ेगी। जीईएम रिपोर्ट में तीन प्रमुख मुद्दों का समाधान किया गया है: असमानता और इसके उद्भव को मापने का उचित तरीका क्या है, कमजोर वर्ग के सदस्यों के संबंध में जानकारी किस प्रकार एकत्र की जाए तथा समानता के अतिरिक्त, शिक्षा में समता के किन व्यापक पहलुओं को आंका जा सकता है।

असमानता के मापदंड

तीन प्रमुख कारक शिक्षा में असमानता को मापना कठिन बना देते हैं। पहला, ऐसे अनेक संकेतक हैं जिनसे असमानता की जांच की जा सकती है, उदाहरण के लिए शिक्षा की उपलब्धता अथवा शिक्षा प्राप्त करना। दूसरा, असमानता को मापने के लिए विभिन्न मापदंड, जिसका उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि एक संकेतक को जनता में किस प्रकार बांटा जाता है और प्रत्येक को इससे क्या फायदा या नुकसान हुआ। समय के साथ विभिन्न मापदंडों से असमानता की मात्रा और परिवर्तन के बारे में विभिन्न निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं। तीसरे, नीति-निर्माताओं को यह पता होना चाहिए कि किस प्रकार एक संकेतक संपत्ति आदि जैसी व्यक्तिगत विशेषता की दृष्टि से भिन्न होता है, लेकिन देशों के बीच प्राय: इन विशेषताओं की तुलना करना मुश्किल होता है।

> "निम्न आय वाले देशों में प्राथमिक, माध्यमिक और ऊपरी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक सबसे अमीर 100 युवाओं की तुलना में सबसे गरीब युवाओं में क्रमश: 36, 19 और 7 ही शिक्षा पूरी कर पाए थे"

आंतरिक-एजेंसी और एसडीजी संकेतकों के विशेषज्ञ समूह ने शिक्षा में असमानता के विश्व स्तरीय मानक के तौर पर समता के सूचकांक का प्रस्ताव किया है। यह मापदंड ज्यादा श्रोताओं तक बात पहुंचाने का आसान तरीका है तथा दो दशकों से चल रही लैंगिक असमानता की व्याख्या करने में प्रभावी रहा है। जिन लक्षणों के संबंध में इस मापदंड को लागू किया जा सकता है, उनमें संपत्ति से संबंधित असमानता सबसे प्रमुख है। उच्च मध्य आय वाले देशों में संपत्ति की समानता के सूचकांक के अनुसार प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की दर 0.90, माध्यमिक शिक्षा में 0.71 तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा में 0.44 है। कम आय वाले देशों में संपत्ति की समानता के सूचकांक के अनुसार प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की दर 0.36, माध्यमिक शिक्षा में 0.19 तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा में 0.07 है।

शिक्षा की असमानता के संकेतों के संबंध में आंतरिक-एजेंसी समूह की स्थापना सही दिशा में उठाया गया कदम है, क्योंकि इससे सर्वेक्षण आंकड़ों का निरंतर विश्लेषण करना संभव हो जाता है तथा यह उपयोग न किए गए आंकड़े के स्रोतों की पूलिंग करता है। विश्व स्तर पर समन्वय में हुई प्रगति का लाभ देश के स्तर पर पहुंचाए जाने की आवश्यकता है।

जेंडर

वर्ष 2014 में विश्व स्तर पर प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा समानता प्राप्त कर ली गई थी, लेकिन फिर भी, इन स्थलों पर शिक्षा में सिर्फ 63%, 46% और 23% देशों ने संबंधित स्तरों पर समानता प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय औसत से देश के अंदर तथा विशेष समूहों के बीच व्याप्त अंतर छिप जाता है। उप-सहारा अफ्रीका ने सूचित किया है कि सबसे अमीर 20% व्यक्तियों के बीच प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वालों में स्त्री-पुरुष समानता है, जबकि सर्वाधिक गरीब 20% व्यक्तियों के बीच प्रति 100 पुरुषों पर सिर्फ 83 महिलाओं ने प्राथमिक शिक्षा पूरी की। यह असमानता निम्न माध्यमिक शिक्षा के मामले में बढ़कर 73 महिलाएं तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा के मामले में 40 महिलाएं है।

लक्ष्य 4.5 के जेंडर पहलुओं की निगरानी करने के लिए समता सूचकांक को अपनाने से इसका उपयोग दाखिला अनुपात के अलावा शिक्षण परिणामों सहित शिक्षा के सभी संकेतकों के लिए किया जा सकता है। यद्यपि यह सकारात्मक संकेत है, लेकिन यह सूचकांक शिक्षा में स्त्री-पुरुष समानता के विभिन्न पहलुओं में से सिर्फ एक पहलू का ही समाधान करता है। शिक्षा में स्त्री-पुरुष समानता की निगरानी में सुधार लाने के लिए, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, मूल्यांकन और शिक्षकों की शिक्षा के स्त्री-पुरुष पहलुओं पर और अधिक व्यापक आंकड़े एकत्र किए जाने के प्रयास करने चाहिए तथा शिक्षा और अन्य मामलों में स्त्री-पुरुष समानता के संकेतकों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहिए।

तालिका 2:

स्त्री – पुरुष समानता सूचकांक प्रांत और देश के आय समूह, 2014 पर आधारित

	प्राथमिक शिक्षा		निम्न माध्यमिक शिक्षा		ऊपरी माध्यमिक शिक्षा	
	स्त्री – पुरुष समानता सूचकांक	समानता वाले देश (%)	स्त्री – पुरुष समानता सूचकांक	समानता वाले देश (%)	स्त्री – पुरुष समानता सूचकांक	समानता वाले देश (%)
विश्व	0.99	63	0.99	46	0.98	23
निम्न आय	0.93	31	0.86	9	0.74	5
निम्न मध्यम आय	1.02	52	1.02	33	0.93	17
ऊपरी मध्यम आय	0.97	71	1.00	60	1.06	22
उच्च आय	1.00	81	0.99	59	1.01	37
काकेशस और मध्य एशिया	0.99	100	0.99	83	0.98	29
पूर्वी और दक्षिण – पूर्वी एशिया	0.99	86	1.01	57	1.01	37
यूरोप और उत्तरी अमेरिका	1.00	93	0.99	67	1.01	31
लेटिन अमेरिका और कैरिबियन	0.98	48	1.03	39	1.13	19
उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया	0.95	56	0.93	46	0.96	33
प्रशांत	0.97	64	0.95	44	0.94	0
दक्षिणी एशिया	1.06	29	1.04	25	0.94	38
उप – सहारा अफ्रीका	0.93	38	0.88	19	0.82	6

टिप्पणी: सभी दर्शाए गए मूल्य मध्यम स्तर के हैं।
स्रोत: यूआईएस डेटाबेस

चित्र 11:

स्त्री – पुरुष असमानता सबसे गरीब में सबसे अधिक होती है

प्रांत के आधार पर चयनित शिक्षा संकेतकों के लिए स्त्री – पुरुष समानता सूचकांक, अमीरों के साथ परस्पर कार्रवाई, 2008 – 2014

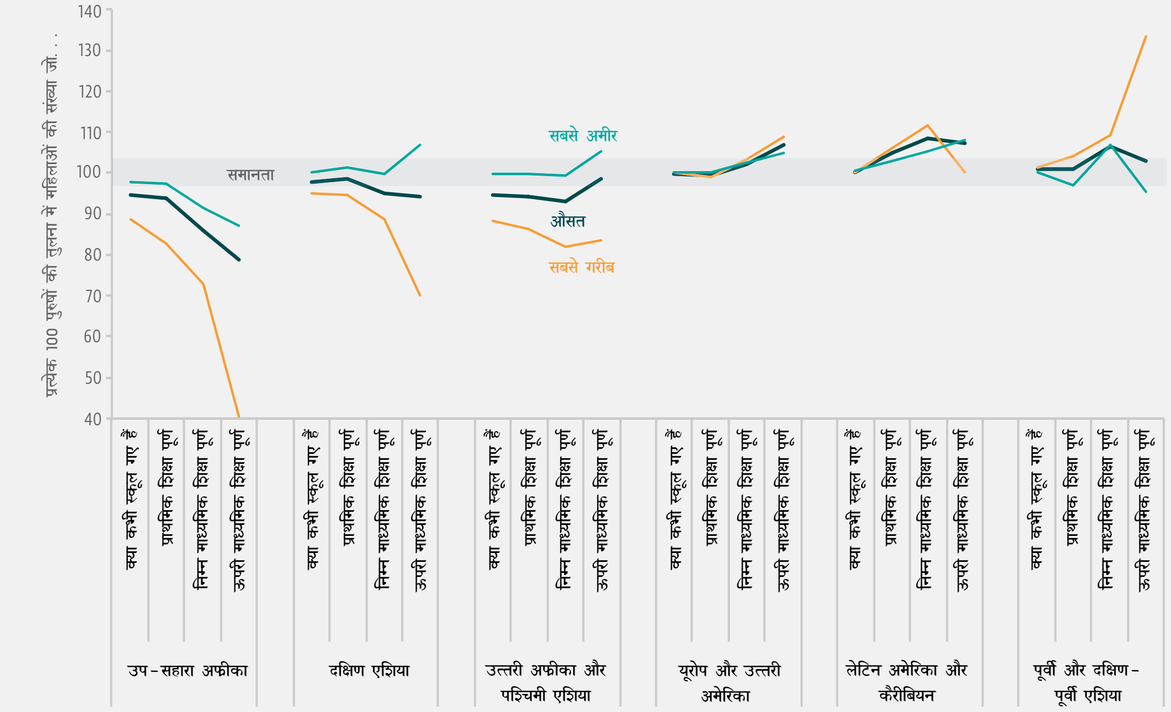

टिप्पणी: पूर्वी और दक्षिणी – पूर्वी एशिया और उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के लिए मूल्य केवल निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए हैं।
स्रोत: घरेलू सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर जीईएम रिपोर्ट दल विश्लेषण (2016)

अपंगता

अपंग व्यक्तियों को शिक्षा समान रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए अपंगता की अंतर्राष्ट्रीय रूप से तुलना किए जाने की आवश्यकता है, वैसे अपंगता के विभिन्न रूप और स्तर हैं। वर्ष 2010 में यूरोप की 30 शिक्षा प्रणालियों में किए गए अध्ययन से यह पाया गया कि अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों में से 3.7% को विशेष शिक्षण की आवश्यकता

थी। यूनिसेफ और अपंगता के आंकड़ों से संबंधित वाशिंगटन समूह, अपंगता के संबंध में एक प्रचालन संबंधी मापदंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात की भी निगरानी किया जाना आवश्यक है कि शिक्षकों को भली-भांति तैयार किया जाए और स्कूल का बुनियादी ढांचा अपंग व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुरूप हो।

भाषा

मातृभाषा आधारित बहुभाषायी शिक्षा की निरंतर उपेक्षा से शिक्षा के परिणामों में व्यापक असमानता को समझा जा सकता है। शिक्षा में भाषा संबंधी नीतियों की निगरानी के लिए और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। एक मापदंड के अनुसार, दुनिया भर के लगभग 40% व्यक्तियों को, उनके बोलने या समझने की भाषा में शिक्षा उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय नीति संबंधी दस्तावेजों की निगरानी से यह जाना नहीं जा सकता कि क्या छात्रों को उनकी अपनी भाषा में पढ़ाया जा रहा है या शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, बुनियादी स्तर पर इस बात के लिए शिक्षक तैयार किए जाते हैं या सरकारी नीतियां कार्यान्वित की जा रही हैं। माली के मोप्ती क्षेत्र में राष्ट्रीय नीति के बावजूद सिर्फ 1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में उचित भाषा में द्विभाषी और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा था।

पलायन और जबरन विस्थापन

देश के ग्रामीण प्रवासी, जो झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं या शहर के बाहर स्थित ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पब्लिक स्कूल सीमित हैं, उनको होने वाली समस्याओं के बावजूद, उनका शहरी क्षेत्रों में प्रवास उन्हें सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने में मददगार होता है। अन्तर्राष्ट्रीय पलायन के मामलों में, नीति-निर्माताओं के लिए एक चुनौती यह है कि ऐसे छात्रों की संख्या इन सुविधाओं से वंचित स्कूलों में अधिक हो जाती है।

> “विश्व भर में प्राथमिक स्कूल जाने की आयु वाले 50% शरणार्थी तथा माध्यमिक स्कूल जाने की आयु वाले 75% शरणार्थी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं”

जबरन विस्थापन एक प्रमुख चुनौती है। देश के भीतर विस्थापित व्यक्तियों का अपेक्षाकृत कम पता चलता है। जून, 2015 में नाइजीरिया के 6 राज्यों के 42 विस्थापन शिविरों में से 19 में, बच्चों को औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। शरणार्थी सर्वाधिक कमजोर समूह होता है। विश्व भर में प्राथमिक स्कूल जाने की आयु वाले 50% शरणार्थी तथा माध्यमिक स्कूल जाने की आयु वाले 75% शरणार्थी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। पलायन और जबरन विस्थापित व्यक्तियों की शैक्षिक स्थिति की निगरानी करना कठिन है। उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराने में होने वाली असमानता के कारणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

साक्षरता और गणित का ज्ञान

Sustainable Development Goal 4.6

लक्ष्य 4.6

लक्ष्य 4.6 में प्रौढ़ साक्षरता पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जो कि चौथे ईएफए के लक्ष्य का भाग था और इसमें दो महत्वपूर्ण प्रयास भी किए गए हैं। पहला, विशेष रूप से कौशल में प्रवीणता के आधार पर, साक्षरता और गणित के ज्ञान पर विश्व स्तरीय संकेतक तैयार करना। यह इस दृष्टिकोण के करीब है कि साक्षरता मात्र कुछ बुनियादी ज्ञान संबंधी कौशल नहीं है बल्कि वह क्षमता है, जिससे हम इसका उपयोग समाज, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत बदलाव में योगदान के लिए कर सकते हैं। दूसरा, विशेष रूप से गणित का ज्ञान, इसकी विशेषताओं पर ध्यान दिए जाने की मांग करता है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में भागीदारी

औपचारिक और अनौपचारिक साक्षरता कार्यक्रमों में प्रौढ़ शिक्षार्थियों की भागीदारी को आंकना काफी कठिन साबित हुआ है। ‘प्रौढ़ शिक्षा पर वैश्विक रिपोर्ट’ को कम से कम सरकारी स्तर पर या उसके द्वारा प्रायोजित साक्षरता कार्यक्रमों में प्रौढ़ शिक्षार्थियों की भागीदारी को दर्ज करने के लिए एक मानकीकृत रिपोर्टिंग टेम्पलेट का विकास करना चाहिए।

जीईएम रिपोर्ट के नए विश्लेषण में आंकड़ों और स्वास्थ्य सर्वेक्षण में नियमित रूप से शामिल किया जाने वाला एक प्रश्न पूछा जाता है; जो दर्शाता है कि वर्ष 2004 और 2011 के बीच कम और मध्यम आय वाले 29 देशों के 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग के सिर्फ 6% वयस्कों ने ही किसी साक्षरता कार्यक्रम में भागीदारी की है। निरक्षरों में ज्यादातर महिलाएं और निर्धन व्यक्ति थे, जबकि पुरुषों और अपेक्षाकृत धनी वयस्कों ने इसमें अधिक संख्या में भाग लिया था।

साक्षरता दरें

हालांकि एसडीजी एजेंडे में अब साक्षरता कौशल में प्रवीणता को आंकने की ओर ध्यान देना आरंभ कर दिया है लेकिन मापने के लिए आवश्यक साधन व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए युवा और वयस्क साक्षरता की सूचना परंपरागत साक्षरता दरों के आधार पर ही दी जा रही है। वर्ष 2005–2014 के दौरान, विश्व के लगभग 758 मिलियन या 15% वयस्कों में साक्षरता के अनुप्रयोग संबंधी कौशल की कमी पाई गई।

साक्षरता और गणित के ज्ञान में प्रवीणता

प्रौढ़ साक्षरता और गणित के ज्ञान की प्रवीणता के स्तरों की सूचना, जिसका प्रत्यक्ष रूप से आकलन किया जाता है, कई उच्च आय वाले देशों के संबंध में उपलब्ध हैं। प्रौढ़ व्यक्तियों के शिक्षा संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय आकलन हेतु ओईसीडी कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों में से 15% बुनियादी साक्षरता क्षमता मानक तक पहुंच नहीं सके, जिसमें पाठ से मामूली निष्कर्ष निकालना शामिल था; यह दर जापान के मामले में 5% और इटली के मामले में लगभग 28% थी।

तुलनात्मक साक्षरता और गणित के ज्ञान का आकलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। वर्ष 2030 तक उपयोगी निगरानी आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए, देश की क्षमता में संतुलन लाने हेतु एक सफल दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है ताकि वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए आकलन की आवश्यकता को वे स्वयं पूरा कर सकें।

चित्र 12:

सतत पैमाने पर साक्षरता का आकलन वयस्क कौशल को दर्शाता है।

वयस्क जनसंख्या का साक्षरता निपुणता स्तर, 2011–2014

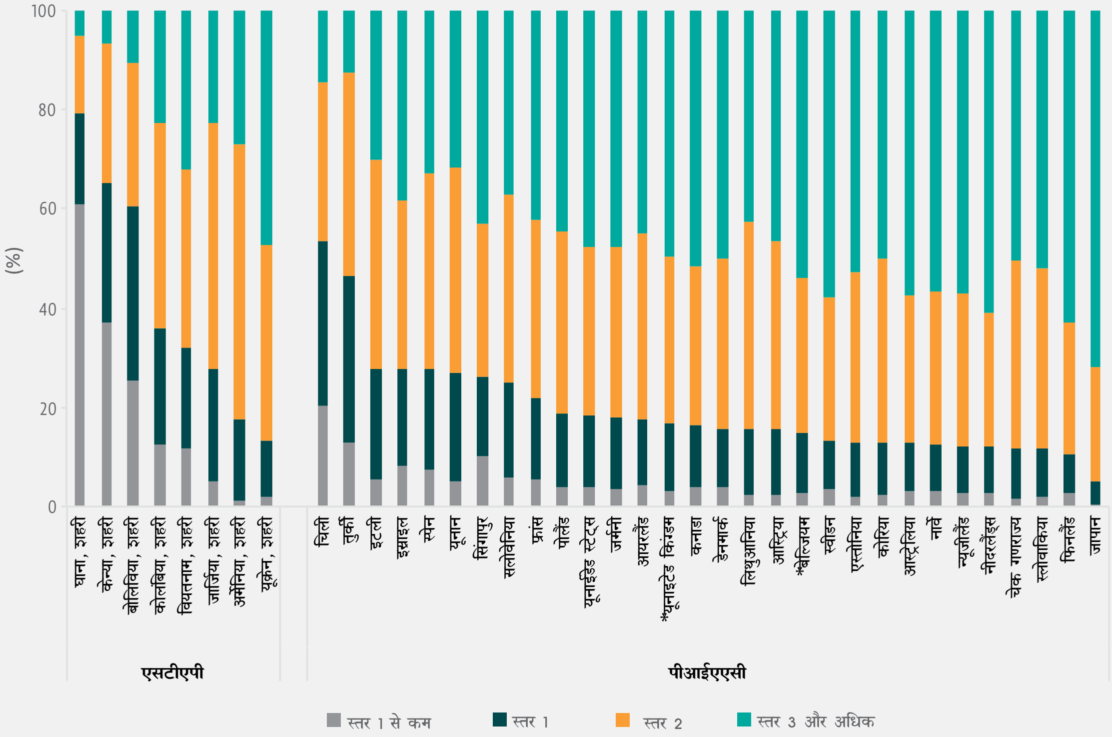

टिप्पणी: एस्ट्रिक लगे देशों के लिए, पीआईएसी डेटा केवल व्यक्तिगत क्षेत्रों से संबंधित है: इंडोनेशिया के लिए जर्काता, यूनाईटेड किंगडम के लिए इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, और बेल्जियम के लिए फलैण्डर्स

स्रोत: विश्व बैंक एसटीईपी डेटा के आधार पर ओईसीडी (2013; 2016) और जीईएम रिपोर्ट दल विश्लेषण.

लक्ष्य 4.7

सतत विकास और वैश्विक नागरिकता

किसी अन्य लक्ष्य के मुकाबले 4.7 लक्ष्य शिक्षा के सामाजिक, मानवीय और नैतिक उद्देश्य से जुड़ा है। यह विशेष तौर पर अन्य एसडीजी से शिक्षा को जोड़ता है तथा नए वैश्विक विकास एजेंडा की बदलती आकांक्षाओं को दर्ज करता है।

जीईएम रिपोर्ट प्रस्तावित वैश्विक संकेतक पर ध्यान केन्द्रित करती है तथा यह जांच करती है कि किस प्रकार वैश्विक नागरिकता तथा सतत विकास को सभी प्रणालियों के कार्यकलापों, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचों तथा पाठ्य पुस्तकों जैसी पाठ्यक्रम सामग्रियों और शिक्षक के शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

सतत विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता वाले ज्ञान, कौशल तथा जज्बे की निगरानी के संकेतकों की पहचान करना अत्यंत कठिन है। यह रिपोर्ट ऐसी पहल का पता लगाने का प्रयास कर रही है जिसका उपयोग संगत ज्ञान और कौशल प्राप्त किए जाने के साथ-साथ युवाओं तथा व्यक्तियों के व्यवहार की निगरानी के लिए किया जा सके।

लक्ष्य 4.7 को आजीवन शिक्षा ढांचे से काफी हद तक जोड़ा गया है तथा इसमें शिक्षा के स्तरों अथवा आयु समूहों का उल्लेख नहीं किया गया है कि इसके विषय किस पर लागू होंगे। प्रस्तावित वैश्विक तथा विषय संकेतक मुख्यत: औपचारिक शिक्षा में बच्चों और किशोरों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। प्रस्तावित विषय का कोई भी संकेतक विशेष रूप से अनौपचारिक शिक्षा में प्रौढ शिक्षार्थियों के आंकड़े दर्ज नहीं करता।

पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम सतत् विकास और वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा देने के ज्ञान और कौशल से अवगत कराए जाने का प्रमुख माध्यम है। एक विषयगत संकेतक में विश्व मानवाधिकार शिक्षा फेमवर्क कार्यक्रम के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन को आंकने का प्रस्ताव किया गया है। जहां तक मानवाधिकार, मूलभूत स्वतंत्रता और सहनशीलता का संबंध है, यह संकेतक लक्ष्य 4.7 के मूल तत्वों के अनुरूप है।

लक्ष्य 4.7 के लिए एक अन्य प्रस्तावित विषयगत संकेतक है - एचआईवी/एड्स और यौन संबंधी जीवन-कौशल आधारित शिक्षा प्रदान कर रहे स्कूलों का प्रतिशत - लक्ष्य 4.7 के पांचों घटकों के संबंध में उनका जवाब है: मानवाधिकार, स्त्री-पुरुष समानता, शांति बनाए रखने की समझ, अहिंसा और सतत् विकास को बढ़ावा देने वाले कौशल तथा जीवन शैली। शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली में इस संकेतक को शामिल करते हुए और कुछ देशों में स्कूल आधारित प्रायोगिक सर्वेक्षण आरंभ किए गए हैं, जिससे बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सकेगा।

> “वर्ष 2005-2015 के दौरान 78 देशों में से तीन-चौथाई देशों में सतत्-विकास के मुद्दों पर कुछ बल दिया गया था”

विषयों के पाठ्यक्रम के संबंध में आगे और अनुसंधान, लक्ष्य 4.7 की प्रगति को समझने में सहायक होगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क और संबंधित सामग्रियों की व्यवस्थित सूची की आवश्यकता है। वर्ष 2005-2015 के दौरान 78 देशों में प्राथमिक और द्वितीयक शिक्षा हेतु लगभग 110 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फेमवर्क दस्तावेजों का जीईएम रिपोर्ट विश्लेषण दर्शाता है कि तीन-चौथाई देशों में सतत्-विकास के मुद्दों पर तो कुछ बल दिया गया था, लेकिन बहुत कम देशों ने विश्व नागरिकता के विचाराधीन मामले पर ध्यान दिया। स्त्री-पुरुष समानता पर भी कम ध्यान दिया गया था: 15% से कम देशों ने स्त्री-पुरुष सशक्तता, स्त्री-पुरुष समानता या स्त्री-पुरुष संवेदनशीलता जैसे शब्दों को शामिल किया, जबकि आधे देशों ने स्त्री-पुरुष समानता का उल्लेख किया।

पाठ्यपुस्तकें

पाठ्यपुस्तक की सामग्री के संबंध में हाल में हुए विश्लेषण से पाठ्यक्रम सामग्री का मूल्यांकन किए जाने की आशा बंधी है। जीईएम रिपोर्ट के लिए, इतिहास, नागरिकशास्त्र, सामाजिक अध्ययन और भूगोल विषय में माध्यमिक स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के आंकड़ों से संबंधित तीन सेटों का समेकन किया गया। विश्लेषण में पाया गया कि वर्ष 1890-1913 के लगभग 5% की तुलना में, वर्ष 2000-2013 के दौरान, लगभग 50% पाठ्यपुस्तकों में मानवाधिकार का उल्लेख था। पिछले दशक में

चित्र 13 :
मानवाधिकार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में सर्वाधिक प्रचलित अवधारणा है।
ऐसे देशों का प्रतिशत, जिसमें उनके राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, 2015 में प्रत्येक मुख्य शर्त शामिल है।

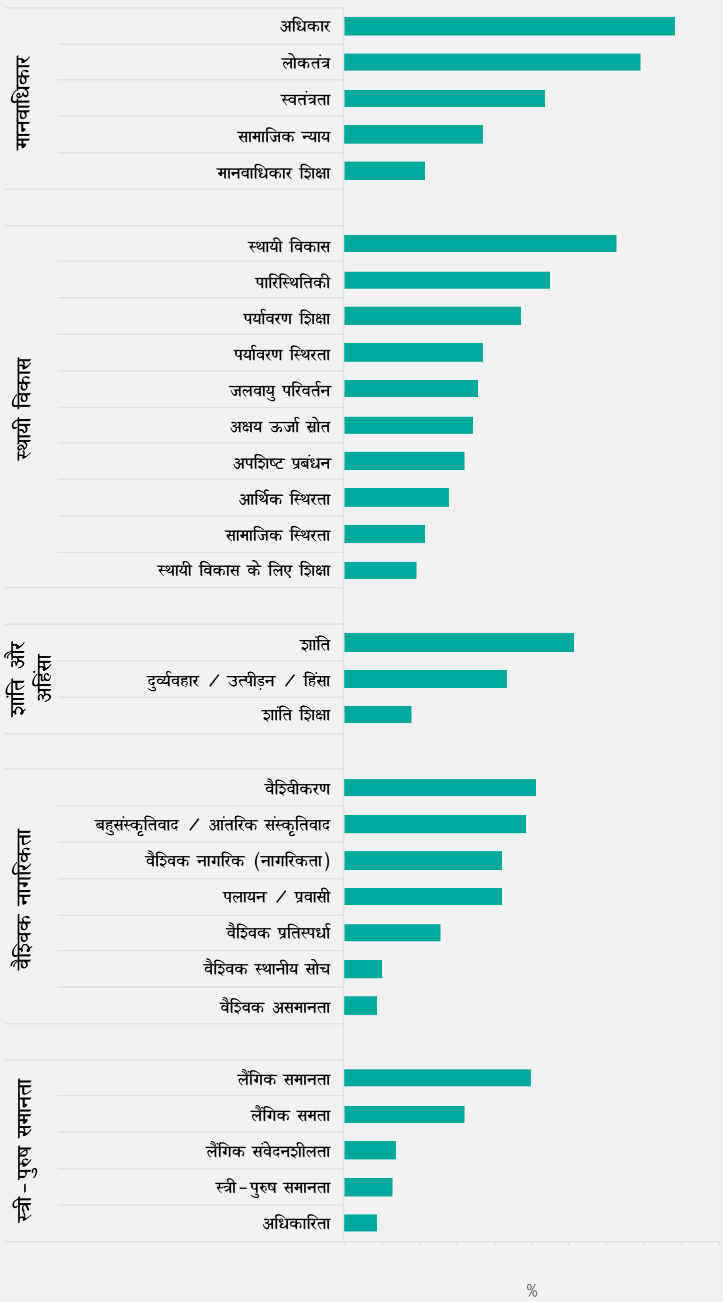

टिप्पणी: विश्लेषण 78 देशों के नमूनों पर आधारित है।
स्रोत: आईबीई (2016)

उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया की लगभग 10% पाठ्यपुस्तकों में महिला-अधिकारों का उल्लेख था। ऐसे विश्लेषण दर्शाते हैं कि पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करके वैध और विश्वसनीय मानकों का विकास करना संभव है। पाठ्यपुस्तक सामग्री के संबंध में विश्व स्तर पर तुलना योग्य आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए एक नियमित निगरानी तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

शिक्षकों की शिक्षा

शिक्षकों को सतत् विकास और विश्व नागरिकता से संबंधित क्षेत्रों के बारे में सीखाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। वर्ष 2013 में, सर्वेक्षण किए गए 66 देशों में से शिक्षकों की शिक्षा में, सतत् विकास का विषय सिर्फ 8% देशों में शामिल पाया गया, जोकि वर्ष 2005 के 2% से अधिक है। शिक्षकों के शिक्षा कार्यक्रम की सामग्री शायद ही कभी आसानी से उपलब्ध होती है, लेकिन कुछ जानकारी एकत्र की गई है जो अधिकतर क्षेत्रीय है। शिक्षकों को तैयार करने और प्रशिक्षण देने के लिए लक्ष्य 4.7 की अवधारणा का आकलन करने के तत्काल प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम पर एक मानक कोडिंग प्रोटोकॉल लागू करने से विभिन्न समुदाय के छात्रों से संवाद करने के लिए शिक्षकों को तैयार करने में पेशेवर विकास के प्रभाव का विश्लेषण करना संभव हो पाएगा।

कक्षा से बाहर की गतिविधियां

सतत् विकास और वैश्विक नागरिकों के मुद्दे से छात्रों का परिचय न सिर्फ स्कूल में, बल्कि शैक्षणिक क्लबों, छात्र संघों, खेल-कूद, वाद-विवाद क्लबों, रंगमंच, संगीत समूहों, स्वैच्छिक कार्यो और अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी होता है। जीईएम रिपोर्ट के एक विश्लेषण में पाया गया कि सभी प्रकार के वाद-विवाद निपटारे और सामाजिक एकता के लिए भली-भांति तैयार समावेशी गतिविधियों से मानवाधिकार से संबंधित विधिक ढांचे तथा अवधारणाओं के बारे में जागरूकता बढ़ी है तथा इससे विश्व नागरिकता की भावना को बढ़ावा मिला है। आंकड़े एकत्र करने के मौजूदा साधन ऐसी गतिविधियों के अनुभवों और विकास प्रक्रियाओं की गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। साझा रिपोर्टिंग हेतु मानकों का अभाव विश्व स्तर पर तुलना योग्य तथा विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने की संभावनाओं को कम कर देता है।

परिणाम

लक्ष्य 4.7 की प्रमुख अपेक्षाओं–सतत् विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त किए जाने की निगरानी करना आसान नहीं है। विश्व इतिहास, भूगोल, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों और वैश्विक प्रक्रियाओं की बुनियादी और परस्पर समझ, एक आरंभिक बिंदु का कार्य कर सकते हैं लेकिन इस संबंध में ज्ञान संबंधी कुछ आकलन मौजूद हैं। कई देशों में, सिर्फ दो–तिहाई छात्र ही मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा से परिचित हैं।

एक प्रमुख चुनौती स्थानीय जीवन–मूल्यों और बढ़ती वैश्विक प्रतिबद्धताओं के बीच व्याप्त तनाव है। हाल में की गई पहल में, विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे किशोरों से संबंधित लक्ष्य 4.7 के निगरानी तंत्र में सुधार की अपेक्षा की गई है। वर्ष 2016 में विश्व नागरिकता और सतत् विकास संबंधी ज्ञान को मापने के लिए यूनेस्को और *इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट* (अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन संघ) ने अधिकारिक रूप से मिलकर कार्य करना आरंभ किया है। दक्षिण–पूर्व एशिया प्राथमिक प्रिाथमिक शिक्षा मेट्रिक्स ने कक्षा में विश्व नागरिकता पर ध्यान केन्द्रित किया है जिसका लक्ष्य ऐसे तुलनात्मक आकलन का विकास करना है जो स्थानीय स्थितियों के अनुरूप हो।

शिक्षा सुविधाएं और सीखने का माहौल

लक्ष्य 4.क

लक्ष्य 4.क के अनुसार बच्चों के स्कूल, लोकतांत्रिक भागीदारी तथा समावेशी सिद्धांतों वाले होने चाहिए जिनमें बच्चों को उनके अनुसार सुविधाएं मिलें। हालांकि ये सभी सिद्धांत वैश्विक निगरानी के अनुसार जवाबदेह नहीं हो सकते, लेकिन इनके तीन पहलू हैं – स्कूल का आधारभूत ढांचा, सूचना और सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा स्कूलों में हिंसा और हमले।

स्कूल का आधारभूत ढांचा

> “वर्ष 2013 में सबसे कम विकसित देशों में केवल 52% प्राथमिक स्कूलों में ही पर्याप्त जल आपूर्ति थी”

शैक्षणिक संस्थानों में पानी, स्वच्छता की सुविधाओं में सुधार का स्वास्थ्य और शैक्षिक परिणामों पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। फिर भी, वर्ष 2013 में सिर्फ 71% प्राथमिक स्कूलों में पानी पर्याप्त रूप से उपलब्ध था, और 49 सबसे कम विकसित देशों में यह आकड़ा मात्र 52% था।

जब स्कूल असुरक्षित होते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव भी कई गुणा बढ़ जाता है। कुछ देश स्कूलों की सुरक्षा पर अत्यधिक ध्यान रखते हैं लेकिन सभी इस तरह की निगरानी का बोझ नहीं उठा सकते। स्कूल की स्थिति के संबंध में सूचना प्रदान करने में छात्रों और समुदाय की मदद करने के लिए सहायक उपकरणों का विकास किया गया है।

अपंग व्यक्तियों को स्कूल पहुंचाने के लिए कई शारीरिक और सामाजिक बाधाओं को पार करना होता है। इस बात का पता लगाना मुश्किल है कि स्कूल की सुविधाएं अपंग बच्चों के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि उनके लिए सुलभ स्कूल की परिभाषा का अभाव है तथा अक्सर, निगरानी की क्षमता भी सीमित होती है।

स्कूलों में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी

शिक्षा में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी की निगरानी का आधार 2003 *जिनेवा प्लान ऑफ एक्शन ऑफ दि वर्ल्ड समिट ऑन द इंफार्मेशन सोसायटी'* है, जिसके शिक्षा से संबंधित दो लक्ष्य थे।

स्कूलों में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए बिजली आसानी से और नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाए। कई उप–सहारा अफ्रीका देशों में बिजली की कमी से सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में बाधा आती है। मध्य अफ्रीका गणतंत्र में वास्तव में किसी भी प्राथमिक या माध्यमिक स्कूल में बिजली नहीं थी। गिनी और मेडागास्कर में एक कम्प्यूटर पर 500 से अधिक शिक्षार्थियों का अनुपात है।

स्कूलों में हिंसा और हमले

स्कूल से संबंधित हिंसक कृत्य या धमकी के मामले स्कूल परिसर के भीतर होते हैं लेकिन ऐसा स्कूल आने के दौरान, घर पर या साइबर स्पेस में भी होता है। यद्यपि सामान्यत: गोली से मारने जैसे गंभीर मामलों पर ही ध्यान जाता है, लेकिन आम तौर पर होने वाले हिंसा के ज्यादातर मामलों का बच्चों और किशोरों के शैक्षणिक अनुभव पर सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। उनके संबंध में पर्याप्त सूचना नहीं मिलती क्योंकि इस संबंध में बात करना वर्जित माना जाता है।

स्कूलों में डराना-धमकाना हिंसा का सबसे आम रूप है। वर्ष 2011 में *ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी* में कक्षा 8 के लगभग एक-तिहाई छात्रों ने पिछले माह में कम से कम एक बार डराने-धमकाने की बात बताई। शारीरिक हिंसा बहुत ही आम है। वर्ष 2009-2012 के दौरान, 37 देशों के 13 से 15 वर्ष की आयु समूह वाले लगभग 40% बच्चों ने मारपीट में शामिल होने की बात बताई। स्कूलों में यौन हिंसा, हिंसा का सबसे विध्वंसक रूप है, जिसकी संख्या और रूप ज्यादातर छिपा ही रहता है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में उन शंकाओं के संबंध में बेहतर समन्वय की आवश्यकता है, जिनका उपयोग विश्व भर में स्कूल आधारित हिंसा के रुझान का नियमित आकलन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

> “वर्ष 2009-2012 के दौरान, 37 देशों के 13 से 15 वर्ष के आयु समूह वाले लगभग 40% बच्चों ने मारपीट में शामिल होने की बात बताई”

शिक्षा से जुड़े हमलों की निगरानी करना, प्रभावी ढंग से इसका समाधान करने और ऐसा करने वालों को जवाबदेह ठहराने के लिए भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2005-2015 के दौरान 26 देशों में स्कूलों का सैनिक उपयोग किया गया। वर्ष 2009-2012 के दौरान 6 देशों में, हर एक देश पर औसतन 1000 से अधिक शिक्षा से जुड़े हमले हुए।

चित्र 14:

कुछ सबसे गरीब देशों के अधिकांश प्राथमिक स्कूलों में बिजली नहीं है।

बिजली की सुविधा वाले प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों का अनुपात, 2009-2014

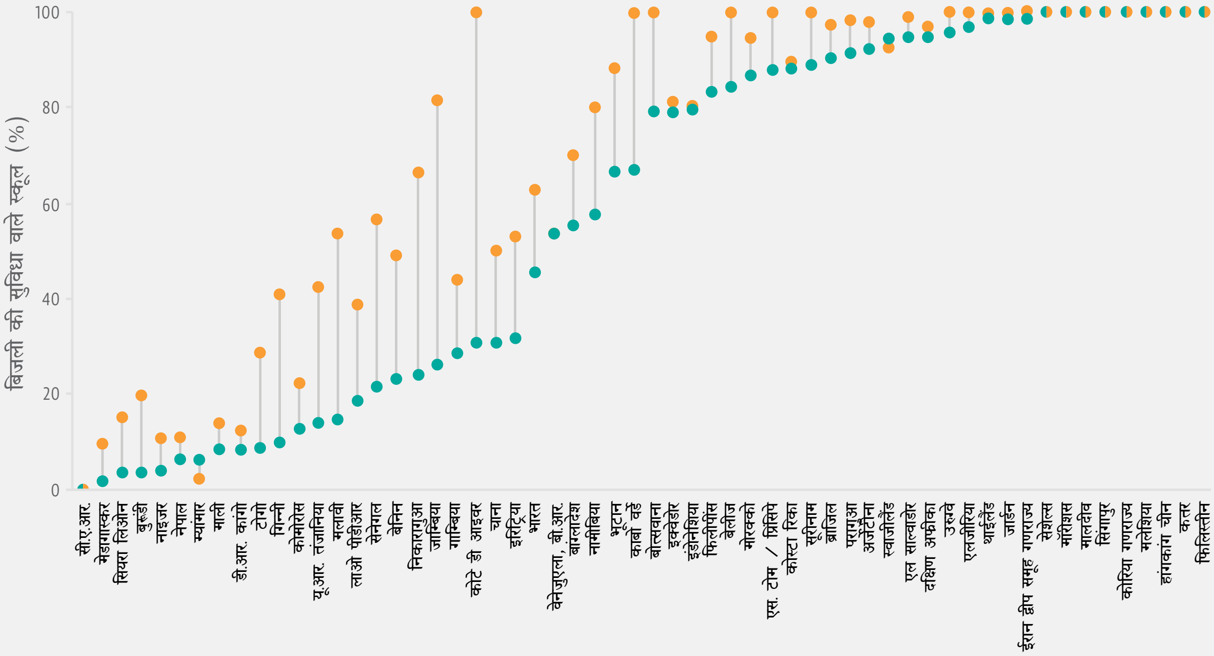

स्रोत: यूआईएस डेटाबेस

Sustainable Development Goal 4.B

छात्रवृत्तियां

लक्ष्य 4.ख

लक्ष्य 4.ख विशिष्ट देशों पर ध्यान केन्द्रित करता है जोकि सार्वभौमिक एजेंडा के अनुकूल प्रतीत नहीं होता। सभी लक्ष्यों की भांति इसमें देशों के बीच असमानता को कम करने की आकांक्षा जताई गई है, लेकिन यह देशों के बीच असमानता को बढ़ा सकता है, क्योंकि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लाभार्थी अच्छी पृष्ठभूमि के होते हैं। इसके अतिरिक्त, कई छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता अपने देश वापस नहीं लौटते हैं। इससे ज्ञात होता है कि छात्रवृत्तियां से निर्धन देशों को लाभ होने के स्थान पर अमीर देशों के उच्चतर शिक्षण संस्थानों को लाभ होता है।

> “54 सरकारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमों से इस रिपोर्ट के लिए एकत्रित सूचना दर्शाती है कि 2015 में लगभग 25,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं”

लक्ष्य 4.ख को पूरा करने में कई प्रकार की कमियां हैं। यह सिफारिश की गई है कि छात्रवृत्तियों के लिए तभी पात्र माना जाए, यदि वह छात्र अपने देश के अलावा दूसरे देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन के लिए जाएँ और उनकी छात्रवृत्ति आंशिक रूप से सरकार से वित्त-पोषित होनी चाहिए।

देश से बाहर जाने का अनुपात, अर्थात अध्ययन के लिए देश से बाहर जाने वाले छात्रों की संख्या, जिसे उस देश में कुल उच्च दाखिला के प्रतिशत के तौर पर दर्शाया जाता है, कम

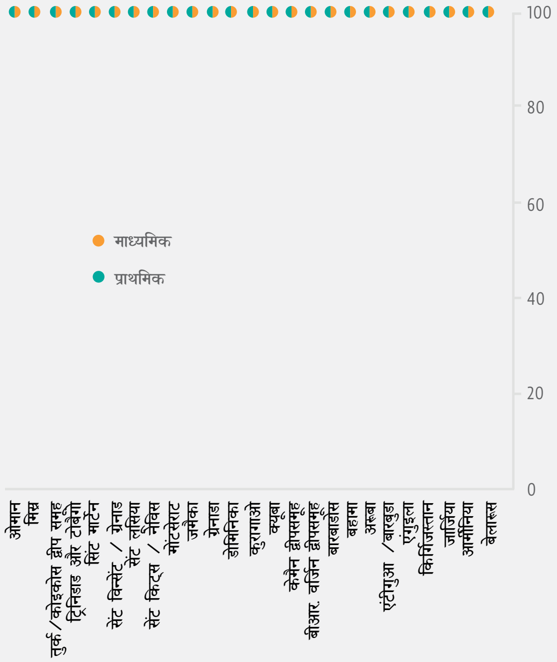

चित्र 15:

छात्रवृत्तियों के लिए पूर्ण सहायता का आधा तथा अध्यारोपित छात्र लागत 13 मध्यम आय वाले देशों को दी जाती है।

छात्रवृत्तियों का वितरण और प्राप्तकर्ता देश द्वारा अध्यारोपित छात्र लागत, 2014

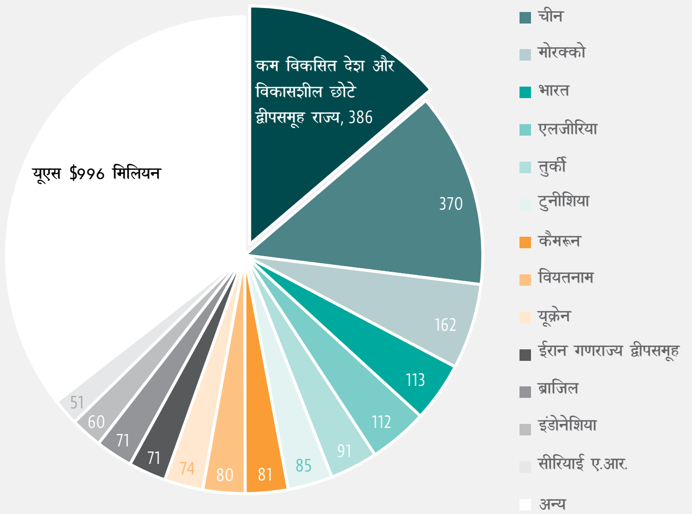

स्रोत: ओईसीडी डीएसी डेटा के आधार पर जीईएम रिपोर्ट दल विश्लेषण (2016)

और मध्यम आय वाले देशों में यह 1.8% है। फिर भी, कुछ देशों में छोटे द्वीप वाले विकसित राज्य में यह काफी अधिक है। सेंट लूसिया में देश के प्रत्येक 10 छात्रों में से 5 छात्र देश के बाहर अध्ययन करते हैं।

यह आश्चर्यजनक है कि छात्रवृत्तियों की संख्या के संबंध में कोई समेकित विश्व स्तरीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, देशों और अध्ययन के क्षेत्रों से अलग-अलग छात्रवृत्तियां प्राप्त की जाती हैं। 54 सरकारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमों से जीईएम रिपोर्ट के लिए एकत्रित सूचना में पाया गया है कि वर्ष 2015 में 22,500 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं जबकि इस दौरान कम और मध्यम आय वाले देशों के देश से बाहर जाने वाले छात्रों की संख्या 1% थी।

छात्रवृत्तियों की निगरानी के लिए एक वैश्विक तंत्र की आवश्यकता है जो प्रदान की गई छात्रवृत्तियां की संख्या, जिन वर्षों में छात्रवृत्ति प्रदान की गई उनकी संख्या, उन प्राप्तकर्ताओं की संख्या जिन्होंने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है तथा उन प्राप्तकर्ताओं की संख्या जो वापस घर लौट आए हैं, के बारे में सूचना दे सके।

सहायता की राशि के आंकड़े छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के संबंध में आंशिक सूचना दे सकते हैं। वर्ष 2014 में छात्रवृत्तियों के लिए 2.8 बिलियन यूएस डॉलर की सहायता राशि आवंटित की गई थी। इसमें से 386 मिलियन यूएस डॉलर की राशि सबसे कम विकसित देशों और छोटे द्वीप वाले विकासशील राज्यों को प्रदान की गई थी।

शिक्षक

लक्ष्य 4.ग

यह असंतोषजनक है कि एसडीजी शिक्षकों को 'कार्यान्वयन का साधन' मानता है, जोकि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने तथा शिक्षा का माहौल तैयार करने में इस पेशे के बुनियादी योगदान को कम करके आँकने जैसा है। शिक्षक के प्रमुख मुद्दों से संबंधित सीमित अवधारणा के कारण यह लक्ष्य कमजोर बन गया है।

जीईएम रिपोर्ट 'एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन' में शिक्षकों तथा शिक्षा प्रदान करने वालों को सशक्त करने, पर्याप्त संख्या में भर्ती करने, भली-भांति प्रशिक्षण देने, पेशेवर रूप से योग्य बनाने, प्रेरित करने और सहायता प्रदान करने की आम प्रतिबद्धता की निगरानी किए जाने के मुद्दे का समाधान होता है।

योग्य शिक्षकों की पर्याप्त आपूर्ति

ज्यादातर सबसे गरीब देशों में भीड़ भरी कक्षाएं आम हैं जोकि शिक्षकों की अपर्याप्त आपूर्ति की ओर इशारा करती हैं। शिक्षकों की कमी को निर्धारित करने में दो प्रमुख चुनौतियां हैं: शिक्षकों की औसत उपलब्धता के आंकड़े देश के भीतर इसकी अत्यधिक असमानता को छिपा देते हैं और शिक्षकों की संख्या को उनकी गुणवत्ता से अलग नहीं किया जा सकता है। नीति-निर्माता अक्सर शिक्षकों की नियुक्ति के मानकों को कम करके नामांकन की संख्या बढ़ाकर तथा कक्षा का आकार बढ़ाकर इस समस्या से निपटने का प्रयास करते हैं।

इस संबंध में बहुत ही कम आंकड़े हैं कि योग्य शिक्षकों की आपूर्ति से लक्ष्य का क्या अर्थ है, जिसे प्रमुख रूप से शैक्षिक योग्यता ही माना जाता है। वर्ष 2014 में औसत तौर पर, प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाने वाले 82%, प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने वाले 93% तथा

माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले 91% शिक्षकों के पास न्यूनतम अपेक्षित योग्यता थी।

लक्ष्य 4.ग हेतु वैश्विक संकेतक–न्यूनतम प्रशिक्षण वाले शिक्षकों के प्रतिशत में काफी व्यापक क्षेत्र कवर किया गया है लेकिन इस संकेतक में एक मानक की कमी है जिसके आधार पर राष्ट्रीय मानकों की तुलना की जाए। इसके बावजूद, इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि कई शिक्षकों को न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है। कैरेबियाई देशों में, प्राथमिक स्कूलों के 85% शिक्षक प्रशिक्षित हैं। उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में, माध्यमिक स्कूल के 73% शिक्षक हैं। उप–सहारा अफ्रीका में, प्राथमिक–पूर्व और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के आधे शिक्षक प्रशिक्षित हैं।

चित्र 16:

उप–सहारा अफ्रीका में प्राथमिक–पूर्व के आधे से अधिक और माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों का एक–तिहाई प्रशिक्षित नहीं है।

शिक्षा स्तर और क्षेत्र, 2014 द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत

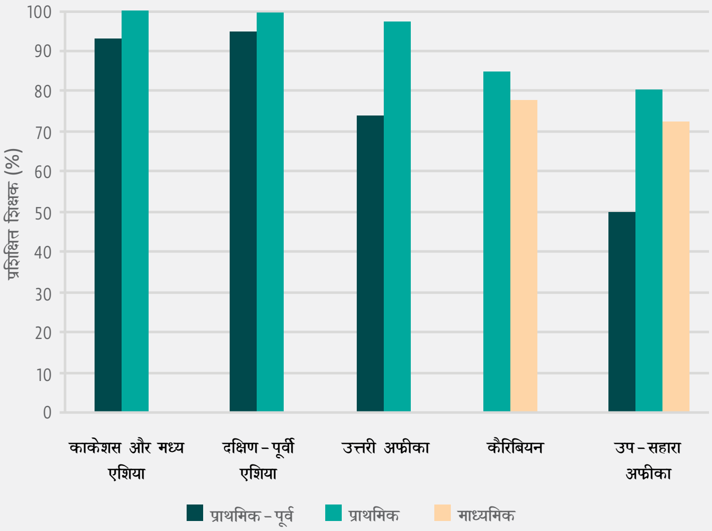

स्रोत: यूआईएस डेटाबेस

वर्ष 2002–2014 के दौरान, शिक्षकों के प्रशिक्षण की सहायता राशि तीन गुनी बढ़कर 251 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो कि शिक्षा को मिलने वाली कुल प्रत्यक्ष सहायता राशि के 2% के बराबर है। सबसे कम विकसित देशों को शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु, कुल सहायता राशि का 41% तथा छोटे द्वीप वाले विकासशील राज्यों को 7% प्राप्त होता है।

शिक्षकों को प्रेरणा और सहायता

शिक्षकों को किस प्रकार प्रेरित किया जाए और सहायता प्रदान की जाए, यह 'एजुकेशन 2030 फेमवर्क फॉर एक्शन' की नीतिगत चिन्ता का सबसे प्रमुख विषय है। प्रेरणा और शिक्षण के कार्य से संतुष्टि जैसे कारकों पर शिक्षकों से प्रत्यक्ष सूचना एकत्र करने में काफी चुनौतियां हैं।

रिपोर्ट में मुख्यत: सरकारी नीति से संबंधित बाह्य कारकों पर विचार किया गया है जिसमें उनकी भर्ती, मार्गदर्शन, सतत् पेशेवर विकास, कार्य की स्थितियां और पारिश्रमिक शामिल है। वर्ष 2013 के *'टीचिंग एण्ड लर्निंग इंटरनेशनल सर्वे'* के अनुसार माध्यमिक स्कूलों के लगभग 25% शिक्षक, जिनका पांच वर्ष से कम अनुभव था, ने बताया कि उन्हें मार्गदर्शक उपलब्ध कराया गया था, और यह दर चिली के मामले में काफी कम 6% और इटली के मामले में 9% थी।

नियुक्त करने तथा सर्वोत्तम व्यक्तियों को इस पेशे में बनाए रखने के लिए एक प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक पैकेज प्रदान किया जाना एक अनिवार्य पहलू है। डोमिनियन गणतंत्र में, अन्य पेशों की तुलना में शिक्षकों को लगभग 70% ही वेतन प्राप्त होता है जबकि उरूग्वे में शिक्षकों की स्थिति इससे बेहतर है।

कुल मिलाकर वेतन, कार्य की स्थितियों और इस पेशे के प्रति आकर्षण के संबंध में विश्वसनीय आकड़े प्राप्त होने तक का मार्ग काफी लंबा है।

वित्त

लक्ष्य 4.5

वर्ष 2030 के एजेंडा में कार्यान्वयन के साधनों से संबंधित तीन लक्ष्य शामिल हैं, लेकिन इनमें से कोई शिक्षा के वित्त- पोषण से संबंधित नहीं है-इस बात के बावजूद कि विश्व द्वारा वर्ष 2015 में ईएफए लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलता का प्रमुख कारण समान और पर्याप्त वित्त-पोषण का अभाव था।

वित्त-पोषण के लक्ष्य के न होने के बावजूद, शिक्षा के व्यापक और नियमित वित्त-पोषण संबंधी आकड़ों का होना, शिक्षा क्षेत्र के प्रभावी नियोजन और विश्व के शिक्षा संबंधी एजेंडे के सभी भागीदारों की प्रतिबद्धता की निगरानी की पूर्व-शर्त है।

राष्ट्रीय शिक्षा लेखा

शिक्षा के वित्त-पोषण से संबंधित बहस के दौरान शायद ही इस बात पर विचार किया जाता है कि किस प्रकार शिक्षा पर व्यय के स्रोत-सरकारी व्यय, बाह्य सहायता तथा परिवार द्वारा व्यय-आपस में जुड़े हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार की चुनौती का सामना करते हुए, स्वास्थ्य क्षेत्र ने स्वास्थ्य संबंधी व्यय आंकड़े एकत्र करने तथा प्रोसेस करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा का निर्माण किया।

हाल की एक परियोजना का लक्ष्य, आठ देशों में राष्ट्रीय शिक्षा लेखा (एनईए) पद्धति आरंभ करना है। उदाहरण के लिए, नेपाल सरकार शिक्षा पर जीडीपी का 3.5% व्यय करती है, जोकि वियतनाम की तुलना में 2.6% कम है। लेकिन जब परिवार और अन्य स्रोतों को शामिल करें तो क्रम उल्टा हो जाता है-वियतनाम की तुलना में नेपाल शिक्षा को 1.5% अधिक राशि आवंटित करता है।

वित्तीय आंकड़ों में सुधार

राष्ट्रीय शिक्षा लेखा को मजबूत बनाने के लिए, सरकार को सहायता राशि के भागीदारों तथा पारिवार की व्यय से संबंधित सूचना में सुधार लाने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक व्यय

'द एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन' ने 'महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदुओं' के तौर पर दो मानकों का प्रस्ताव किया है: शिक्षा हेतु जीडीपी का कम से कम 4% से 6% का आवंटन, और/या शिक्षा हेतु सार्वजनिक व्यय का कम से कम 15% से 20% आवंटन। दुनिया भर के देश शिक्षा पर जीडीपी का 4.6% व्यय करते हैं तथा शिक्षा सार्वजनिक व्यय का 14.2% आवंटन करते हैं। कम से

तालिका 3:
क्षेत्र और देश के आय समूह, 2014 द्वारा सार्वजनिक शिक्षा व्यय

	जीडीपी के % के रूप में सार्वजनिक शिक्षा व्यय	<4% से कम खर्च करने वाले देशों के नाम	सार्वजनिक व्यय के % के रूप में सार्वजनिक शिक्षा व्यय	<15% से कम सार्वजनिक व्यय करने वाले देशों के नाम	<4% से कम जीडीपी और <15% से कम सार्वजनिक व्यय करने वाले देशों के नाम
विश्व	4.6	51	14.2	70	35
निम्न आय	3.9	13	16.7	9	9
निम्न मध्यम आय	4.1	13	15.6	13	10
ऊपरी मध्यम आय	4.6	9	15.7	11	7
उच्च आय	4.9	16	11.9	37	9
काकेशस और मध्य एशिया	2.8	4	12.9	3	3
पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया	3.9	7	15.4	6	4
यूरोप और उत्तरी अमेरिका	5.0	7	12.1	31	5
लेटिन अमेरिका और कैरिबियन	4.9	7	16.1	6	3
उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया	...	3	...	5	3
प्रशांत	...	2	...	2	1
दक्षिणी एशिया	3.8	5	15.3	4	4
उप-सहारा अफ्रीका	4.3	16	16.6	13	12

टिप्पणी: सभी दर्शाए गए मूल्य मध्यम स्तर के लिए हैं।
स्रोत: यूआईएस डेटाबेस

चित्र 17:

शिक्षा को मिलने वाली सहायता द्वारा अभी 2010 का स्तर प्राप्त किया जाना है।

शिक्षा वितरण के लिए कुल सहायता, 2002–2014

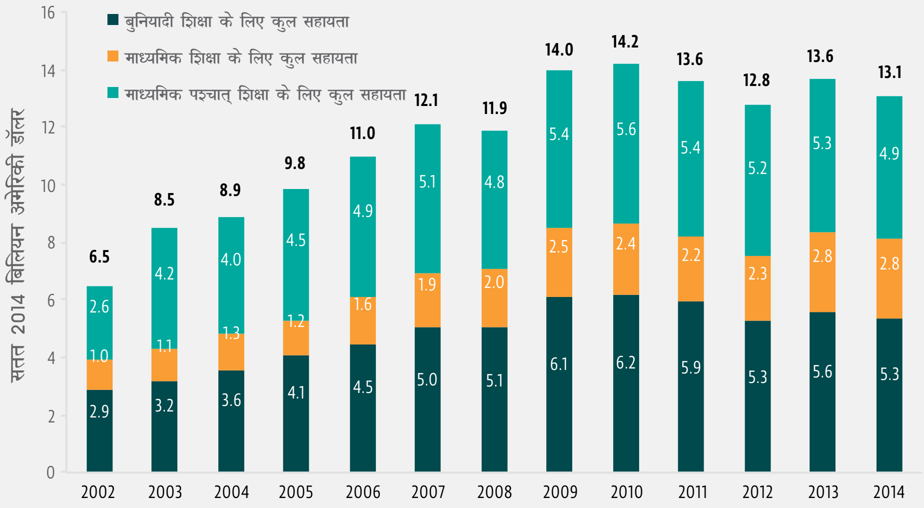

स्रोत: जीईएम रिपोर्ट दल विश्लेषण ओईसीडी सीआरएस डेटाबेस में दी गई सूचना पर आधारित है।

कम 35 देश शिक्षा पर जीडीपी का 4% से कम व्यय करते हैं तथा शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय का 15% से कम आवंटन करते है।

सार्वजनिक शिक्षा के वित्त पोषण के प्रमुख संकेतकों के विश्लेषण से गलत सूचना प्राप्त होती है। वर्ष 2000 से, किसी भी वर्ष के जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर शिक्षा पर कुल व्यय के आंकड़े, सिर्फ 60% देशों के पास ही हैं। शिक्षा पर व्यय के संबंध में बेहतर आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर सार्वजनिक व्यय प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

सार्वजनिक व्यय की समीक्षा में शिक्षा की हिस्सेदारी पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए तथा इस बात पर कि शिक्षा पर व्यय की कमी की किस हद तक क्षतिपूर्ति की जा सकती है। देशों के बीच तुलना संभव है लेकिन इसके लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनाए जाने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है जो इसके आधारभूत ढांचे तथा वास्तविक आकलन के अनुकूल हो। देशों को समान आधार पर लाने के लिए, एक ऐसे समान समीक्षा तंत्र की स्थापना पर बल दिया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से वे एक-दूसरे से सीख सकें।

सहायता राशि का व्यय

39 बिलियन यूएस डालर के वित्त पोषण की वार्षिक कमी को पूरा करने के लिए सहायता राशि को कम से कम छः गुना बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन वर्ष 2014 में, वर्ष 2010 की उच्चतम स्थिति की तुलना में सहायता राशि का स्तर 8% कम हो गया था। यह कमी पूरी की जा सकती है, यदि दानकर्ता जीएनआई का 0.7% सहायता राशि को समर्पित कर दें तथा सहायता राशि का 10% बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा को आवंटित कर दें, वर्ष 2005 से कुल सहायता राशि का प्रवाह, दानकर्ता देशों की राष्ट्रीय आय के लगभग 0.3% के आस-पास रहा है।

निर्धन देशों को सहायता-राशि में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन वर्ष 2014 में कम आय वाले देशों को बुनियादी शिक्षा हेतु कुल सहायता राशि का 28% प्राप्त हुआ था, जबकि प्राथमिक स्कूल की शिक्षा पूरी न करने वाले कुल बच्चों का 43% हिस्सा इन देशों में रहता है।

मानवीय सहायता राशि के स्तरों का भी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2015 में, शिक्षा को कुल मानवीय सहायता राशि का 1.9% से कम हिस्सा प्राप्त हुआ जो कि 198 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

परिवार का व्यय

शिक्षा पर होने वाले कुल व्यय में परिवार के व्यय का हिस्सा अमीर देशों की तुलना में निर्धन देशों में अधिक पाया जाता है। शिक्षा में समानता के नए लक्ष्यों की प्राप्ति में, इस हिस्सेदारी का कम किया जाना महत्वपूर्ण कड़ी है। ज्यादातर देशों में परिवार द्वारा व्यय के संबंध में सूचना उपलब्ध है। जीईएम रिपोर्ट का विश्लेषण दर्शाता है कि कम और मध्यम आय वाले कम से कम 99 देशों ने वर्ष 2008 और 2014 के दौरान राष्ट्रीय व्यय सर्वेक्षण में संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है। 67 देशों ने व्यक्तिगत व्यय की मदों से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है। फिर भी, ऐसे आकड़ों का उपयोग शायद ही किया जाता है। हो सकता है कि नीति-निर्माताओं को इन आंकड़ों की उपलब्धता और महत्व की जानकारी न हो या इसका विश्लेषण करने और इससे उचित निष्कर्ष निकालने की उनकी क्षमता सीमित हो।

शिक्षा प्रणालियां

> "यद्यपि शिक्षा प्रणालियों और नीतियों के लिए एक वैश्विक फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी, लेकिन वास्तव में एक क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय दृष्टिकोण ज्यादा व्यावहारिक है"

शिक्षा-2030 के एजेंडा की निगरानी के लिए, शिक्षा प्रणाली और नीतियों के प्रमाणित और विविध प्रकार के गुणात्मक संकेतकों की आवश्यकता है। यद्यपि एक वैश्विक फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी, लेकिन वास्तव में एक क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय दृष्टिकोण ज्यादा व्यावहारिक है।

शिक्षा प्रणालियों की निगरानी के लिए वैश्विक उपकरण

वर्ष 1996 में, यूनेस्को इंटरनैशनल ब्यूरो ऑफ एजूकेशन (आईबीई) ने शिक्षा श्रृंखला पर वर्ल्ड डाटा स्थापित किया। यह विश्व स्तर पर शिक्षा प्रणालियों पर सूचना एकत्र करने का एक मूल्यवान स्रोत है, लेकिन संसाधनों की कमी ने इसके विकास को बाधित किया है और इस श्रृंखला को अद्यतन करने की कोई योजना नहीं है जिसे अंतिम बार वर्ष 2011 में प्रकाशित किया गया था।

यूनेस्को, अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा से संबंधित शिक्षा प्रणालियों या टीवीईटी प्रणाली के अन्य वैश्विक डाटाबेस उपलब्ध नहीं कराता।

वर्ष 2011 में, आरंभ किए गए, 'वर्ल्ड बैंक सिस्टम्स एप्रोच फॉर बेटर एजुकेशन रिजल्टस (एसएबीईआर)' द्वारा नीतियों के संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के 13 पहलुओं की जांच करता है। वैश्विक निगरानी उपकरण बनने के लिए, इसे कम से कम इन दो मुद्दों का समाधान करना चाहिए: कार्यक्षेत्र, कवरेज और समीक्षा में नियमितता में अनुकूलता होनी चाहिए तथा इसमें देश की व्यापक हिस्सेदारी होनी चाहिए।

शिक्षा प्रणालियों की निगरानी के क्षेत्रीय साधन

विश्व स्तर के स्थान पर निगरानी का कार्य क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर तरीके से होता है। किसी क्षेत्रीय संस्थान के सदस्यों द्वारा अपनी शिक्षा प्रणाली के संबंध में स्वैच्छिक रूप से सूचना के आदान-प्रदान किए जाने की संभावना अधिक होती है। इसके तीन उदाहरण महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 1980 में *स्थापित 'यूरीडाइस नेटवर्क ऑन एजूकेशन सिस्टम एण्ड पॉलिसीज इन यूरोप'* ने 36 देशों में 40 राष्ट्रीय इकाइयों का एक नेटवर्क तैयार कर लिया है। ओईसीडी का *'इंडीकेटर्स ऑफ एजूकेशन सिस्टम्स (आईएनईएस) कार्यक्रम'* वर्ष 1992 में आरंभ किया गया था। इसके तीन नेटवर्कों में से एक का विकास, वर्ष 2009 में, *'आईएनईएस नेटवर्क फॉर सिस्टम-लेवल इंडीकेटर्स (एनईएसएलआई)'* के रूप में हुआ। *'आर्गेनाइजेशन ऑफ इबेरो-अमेरिकन स्टेट्स'* की एक शिक्षा कार्यनीति है और एक विशेषज्ञ निकाय है, जो संकेतकों के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करता है, जिनमें से कुछ प्रणाली से संबंधित हैं।

इस संबंध में बातचीत कायम रखने तथा क्षेत्रीय स्तर पर एक दूसरे से सीखने के लिए सरकारों को प्रोत्साहित करने के लिए जीईएम रिपोर्ट, शिक्षा प्रणाली के संकेतकों की निगरानी किए जाने का समर्थन करती है।

सतत् विकास के अन्य लक्ष्यों में शिक्षा

सतत विकास के वर्ष 2030 के ऐजेंडा में, न सिर्फ शिक्षा को एक अलग लक्ष्य के तौर पर महत्व दिया गया है बल्कि शिक्षा के माध्यम से अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को भी महत्व दिया गया है। एसडीजी-4 के अलावा एसडीजी लक्ष्यों के बीच ऐसे संकेतक हैं, जो शिक्षा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में देखते हैं।

> "एसडीजी-4 के अलावा पांच स्थायी विकास लक्ष्यों के लिए वैश्विक संकेतकों में शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया गया है"

शिक्षा से प्रत्यक्ष संदर्भ

एसडीजी-4 के अलावा पांच वैश्विक संकेतकों में शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया गया है: शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर सरकारी व्यय स्त्री-पुरुष समानता प्राप्त करने के साधन के तौर पर शिक्षा (ऐसे युवा जो शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण से नहीं जुड़े हैं; और वैश्विक नागरिकता शिक्षा तथा सततद्य विकास पर शिक्षा।

शिक्षा से अप्रत्यक्ष संदर्भ

विशेष रूप से शिक्षा के संदर्भ वाले संकेतकों की निगरानी के अतिरिक्त, भविष्य में जीईएम रिपोर्टें अन्य एसडीजी में शिक्षा के अप्रत्यक्ष संदर्भों पर भी ध्यान देंगी। इस संबंध में तीन उदाहरण हैं: अन्य विकास संबंधी परिमाणों के साथ एक कारक के तौर पर शिक्षा को शामिल करना; मानव संसाधन क्षमता के संदर्भ वाले संकेतक, जो व्यवसाय या उच्चतर शिक्षा से संबंधित हैं और प्रौढ़ शिक्षा की संभावित भूमिका।

शिक्षा के स्तरों के आधार पर संबंधित वैश्विक संकेतकों को अलग-अलग करने से, असमानता लाने वाले कारण उजागर होंगे जो एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार, जिन वैश्विक संकेतकों की निगरानी की जा सकती है, वे संकेतक, निर्धनता, कुपोषण, बाल-विवाह, बेहतर सफाई उपलब्ध होना, बिजली की उपलब्धता, बेरोजगारी, मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों, पुनर्चक्रण, आपदा से होने वाली मौतों, हिंसा और जन्म के पंजीकरण से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए कम और मध्यम आय वाले 54 देशों के वर्ष 2008-2015 के आंकड़ों के अनुसार, प्रति एक हजार महिलाओं पर जन्म दर की औसत, अशिक्षित महिलाओं के मामले में 176 थी, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं के मामले में 142, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं के मामले में 61 और उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त महिलाओं के मामले में 13 थी।

चित्र 18:
शिक्षा वांछित विकास नतीजों से सकारात्मक रूप से जुड़ी है।
किशोर जन्म दर (15 से 19 वर्ष की आयु की प्रति 1,000 महिला द्वारा शिशु जन्म), 1997-2014

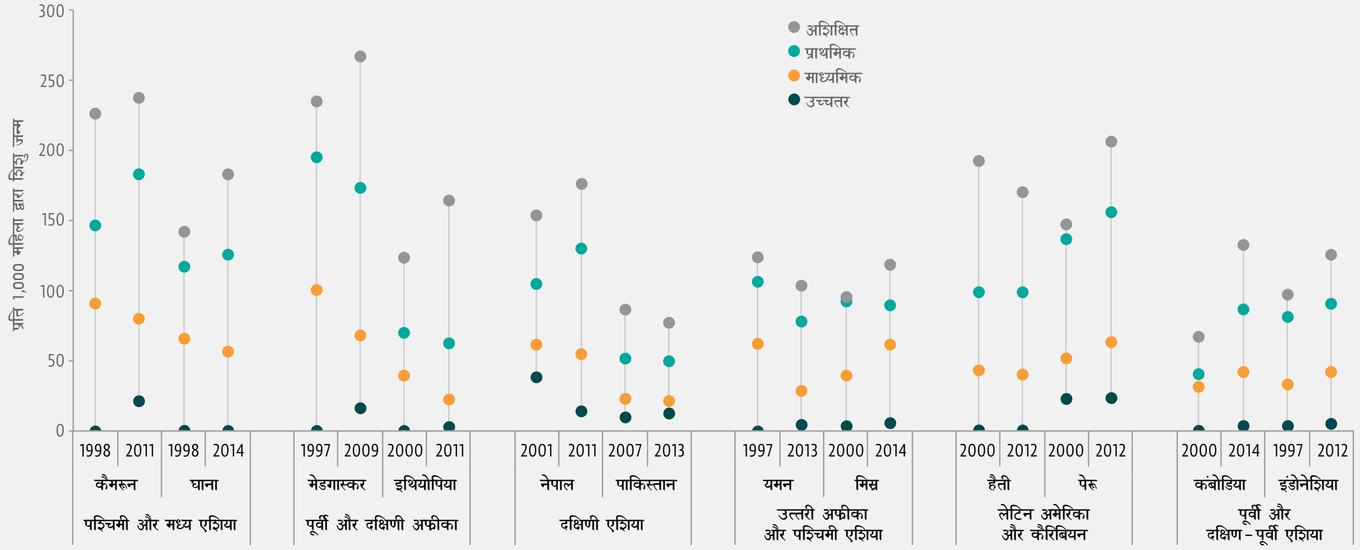

स्रोत: जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सर्वेक्षण एसटीएटी संकलनकर्ता (2016).

सतत विकास लक्ष्य में शिक्षा की निगरानी हेतु प्राथमिकताएं

प्रत्येक एसडीजी-4 लक्ष्य की चुनौतियां की निगरानी की समीक्षा, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्रवाई हेतु प्राथमिकताओं का निर्धारण करने की ओर संकेत करती हैं। इसका आशय यह सुनिश्चित करना है कि एसडीजी-4 की ओर प्रगति करने के लिए विश्व स्तर पर बातचीत हेतु तुलना योग्य पर्याप्त सूचना उपलब्ध हो। ऐसा करने से शिक्षा के संबंध में हुई अपनी प्रगति, जिसका फोकस अपने राष्ट्रीय संदर्भ तथा विशिष्ट आवश्यकता से है, की निगरानी करने में देश को कठिनाई नहीं होगी।

प्रस्तावित निगरानी ढांचा, प्रगति और मापक चुनौतियों से संबंधित सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय एजेंसियों को एक मंच उपलब्ध कराता है। नए स्थापित तकनीकी सहयोग समूह जिसमें देशों का सशक्त प्रतिनिधित्व है, इस ढांचे को और विकसित करने तथा इसे कार्यान्वित करने में मदद करेगा, जिससे शिक्षा की निगरानी पर अंतर्राष्ट्रीय बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय स्तर परः 6 प्रमुख क्षेत्रों में क्षमता निर्माण

अगले 3 से 5 वर्षों में अपनी राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति करने के साथ शिक्षा की विश्व स्तर पर निगरानी में योगदान देने के लिए, देशों हेतु छह प्रमुख कदमों का प्रस्ताव किया गया है।

समानता. बुनियादी असमानताओं पर प्रकाश डालने तथा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के स्रोतों का उपयोग करने के लिए, शिक्षा मंत्रियों तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसियों के बीच सहयोग आवश्यक है।

शिक्षा के परिणाम. देशों द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है, कि नमूना-आधारित राष्ट्रीय शिक्षण आकलन की एक ठोस प्रणाली स्थापित की जाए जिसका उपयोग समय के साथ शिक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति की निगरानी के लिए किया जा सके।

गुणवत्ता. लक्ष्य 4.7 के उद्देश्यों के प्रति पर्याप्त प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए देशों द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षकों के शिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी किए जाने की आवश्यकता है।

जीवन पर्यंत शिक्षा. देशों द्वारा अपनी प्रौढ़ जनसंख्या की शिक्षा आवश्यकताओं, अवसरों तथा उपलब्धियों की गहन निगरानी किए जाने की आवश्यकता है जिन्हें सतत् विकास के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे।

प्रणाली. क्षेत्रीय संगठन देशों को उनकी शिक्षा प्रणाली के लक्षणों मे संबंध में सूचना का आदान-प्रदान करने तथा एक-दूसरे से सीखने के लिए उपयुक्त फोरम उपलब्ध कराते हैं।

वित्त. देशों को एनईए दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे बेहतर ढंग से समझ सकें कि किस प्रकार सरकारों, दानकर्ताओं और परिवारों के बीच शिक्षा पर व्यय को साझा किया जाता है।

क्षेत्रीय स्तर परः समकक्ष से शिक्षा में सहायता

क्षेत्रीय नेटवर्क का उपयोग समकक्ष से शिक्षा ग्रहण करने के तंत्र रूप में करते हुए, देश सूचना को साझा कर सकते हैं, उदाहरण के लिए नीति के क्षेत्र में, वे शिक्षा की कमियों से निपटने में इसका उपयोग कर सकते हैं और सतत विकास तथा वैश्विक नागरिकता शिक्षा हेतु शिक्षा के लिए वे इसका उपयोग कर सकते हैं।

विश्व स्तर पर : सहमति और समन्वय को प्रोत्साहित करना

वैश्विक मामलों पर मापने के साधनों और अनुसंधान में समन्वय के लिए तीन कदम प्रस्तावित हैं। शिक्षा को समर्पित एक अन्तर्राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है जो महत्वपूर्ण कमियों को पूरा कर दे। ओवरलैपिंग से बचने के लिए दानकर्ताओं के लिए एक आचार-संहिता सहित, शिक्षा परिणामों की निगरानी के लिए एक सतत् दृष्टिकोण भी अपेक्षित है। वैश्विक शिक्षा मापने हेतु एक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की जाती है, जिसमें प्रमुख शिक्षा परिणामों पर सहमति बनाने में मदद करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

शिक्षा के आंकड़ों के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए इसमें बुनियादी संकल्पना पर सहमति, मजबूत प्रणालियों में निवेश और आसानी से आंकड़े उपलब्ध कराने, खुलापन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समन्वय को शामिल करना चाहिए।

चिट्टागोंग, बांग्लादेश में एक स्कूल का जूते रखने का रैक, जो उस दिन कक्षा में उपस्थित बच्चों की संख्या को दर्शाता है।

सौजन्य: रिपन बरुआ/यूनेस्को

लोगों और संपूर्ण पृथ्वी के लिए शिक्षा :

सभी के लिए सुनिश्चित भविष्य का सृजन

'लोगों और संपूर्ण पृथ्वी के लिए शिक्षा: सभी के लिए सुनिश्चित भविष्य का सृजन' शिक्षा और सतत् विकास के 2030 के नए एजेंडे के बीच जटिल संबंधों की पड़ताल करती है, जिसमें छः मूलभूत तत्व है–पृथ्वी, संपन्नता, लोग, शांति, स्थान और भागीदारी। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि शिक्षा तभी अपनी पूरी संभावनाओं को प्रकट करेगी, जब भागीदारी की दरों में अत्यधिक वृद्धि होगी और सतत् विकास का लक्ष्य शिक्षा प्रणाली के सुधारों का मार्गदर्शन करेगा। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन, आपसी तनाव, अस्थिर उपभोग के विनाशकारी प्रभावों तथा शिक्षा के संबंध में अमीर और गरीब के बीच बढ़ते अंतराल के संबंध में भी चेतावनी देती है। यदि हम सभी के लिए सुनिश्चित भविष्य का सृजन करना चाहते हैं तो आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट (जीईएम रिपोर्ट) का सार-संक्षिप्त संस्करण इस श्रृंखला की पहली पुस्तक है जो नए सुनिश्चित विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अन्तर्गत शिक्षा की प्रगति का आकलन करेगी। जीईएम रिपोर्ट शिक्षा-2030 के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए नीतियों, कार्यनीतियों और कार्यक्रमों पर साक्ष्य-आधारित सिफारिशें उपलब्ध कराती है। यह रिपोर्ट वैश्विक शिक्षा के नए लक्ष्यों के संबंध में हुई प्रगति की निगरानी करने की चुनौतियों और उपलब्धता, शिक्षा प्राप्त करने, शिक्षा पूरी करने, सीखने में सुधार सुनिश्चित करने और असमानता में कमी लाने के लक्ष्यों पर विचार करती है। यह पाठकों को एक आधिकारिक स्रोत उपलब्ध कराती है ताकि वे निर्णय लेने के सभी स्तरों पर शिक्षा के मूल्य और महत्व के संबंध में बहस करने में सक्षम हों।

जीईएम रिपोर्ट संपादकीय दृष्टि से एक स्वतंत्र और साक्ष्य-आधारित प्रकाशन है, जो शिक्षा में हुई प्रगति और उसकी चुनौतियों के बारे में सूचना आधारित बहस को प्रोत्साहित करने तथा जागरूकता बढ़ाने के अनिवार्य साधन के तौर पर कार्य करता है। इस श्रृंखला की रिपोर्टों में वर्ष 2002 से लगभग 200 देशों और क्षेत्रों में शिक्षा में हुई प्रगति का आकलन किया गया है। इस अनुभव के आधार पर तथा एसडीजी लक्ष्यों में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की निगरानी के लिए नए अधिदेश के साथ, जीईएम रिपोर्ट लगभग अगले पंद्रह वर्षों के लिए तत्पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई तथा समीक्षा प्रक्रिया हेतु एक प्रमुख वैश्विक स्रोत के तौर पर कार्य करेगी।

Global Education Monitoring Report

UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Sustainable Development Goals

4 QUALITY EDUCATION
Sustainable Development Goals

www.unesco.org/publishing • www.unesco.org/gemreport

ED-2016/WS/33